राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 8 अंक 53

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, गुरुवार, 13अगस्त, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जीवन व चिकित्सा बीमा प्रीमियम से हटाया जाए जीएसटी

>> 10

विश्वास.News

राहुल गांधी ने नहीं कही हिंदुओं पर कार्रवाई की बात ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज-5

जागरण विशेष

हार्ट अटैक से जान बचाने में मदद करेगी ये डिवाइस

कानपुर : आइआइटी कानपुर के इंजीनियरों व केजीएमयू लखनऊ के चिकित्सकों ने ऐसी डिवाइस तैयार की है, जो हार्ट अटैक की स्थिति में सीपीआर देने में सहायता करती है। (पेज-7)

संपादकीय

अपने भीतर झांके अमेरिका : भारत को उपदेश देने से बेहतर है कि अमेरिकी संस्थान अपने उन पहलुओं पर ध्यान दें, जिनके चलते उनके लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यापक क्षति पहुंची है।

ए. सूर्यप्रकाश का आलेख।

बदहाल शिक्षा की देन हैं कोचिंग केंद्र : व्यावसायिक कोचिंग का विशाल धंधा शिक्षा की घोर दुर्व्यवस्था की स्थिति को ही बयान करता है। **गिरीश्वर मिश्र** का दृष्टिकोण। • पेज 8

विमर्श

तैरते न्यूक्लियर प्लांट से बदलेगी तस्वीर : जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे में तैरने वाला भारत स्माल माड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी प्लांट बनाने के लिए शोध विकास की ओर देश के बढ़ते कदम क्रांतिकारी हैं। **संजय श्रीवास्तव** का आलेख।

औद्योगिक उड़ान के लिए तैयार हो रहा प्रदेश : मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए निरंतर रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इनके माध्यम से आने वाले निवेश प्रस्ताव यदि जमीन पर उतर जाते हैं, तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। **संजय मिश्र** की डायरी। • पेज-9

सप्तरंग

तकनीक की दुनिया का

फोन सुन रहा है आपकी बातचीत!

कैसे बदल रही है इंटरनेट की दुनिया

• पेज-13

बजट में किसी राज्य से कोई भेदभाव नहीं : सीतारमण

नई दिल्ली : लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में राज्यों को कम आवंटन अथवा उनके साथ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि राज्यों को इस वर्ष 22.91 लाख रुपये दिए जाने हैं और यह राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 2.49 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है। कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा जैसे सभी सेक्टरों का आवंटन बढ़ा है। (पेज-3)

संसद में जाति को लेकर घमासान

राहुल की जाति पूछने का मामला ▸ अनुराग ठाकुर के बयान का सरकार ने मजबूती से किया बचाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली में बुधवार को संसद के मानसून सत्र में विपक्ष को जवाब देते केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। प्रेट्र

- कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने आसन के सामने आकर नारेबाजी की, तख्तियां लहराईं
- केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर अराजकता भड़काने का लगाया आरोप
- भाजपा का सवाल, अगर जाति पूछना अपमान है तो जातिगत गणना कैसे होगी

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पूछने के मुद्दे पर बुधवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों ने आसन के सामने आकर नारेबाजी की। तख्तियां लहराईं और पर्चे फाड़े, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला को लगभग आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर के बयान का मजबूती से बचाव किया। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर अराजकता भड़काने का आरोप लगाया। संसद के बाहर भी भाजपा ने कांग्रेस से प्रतिप्रश्न किए। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान में सबकी जाति पूछ सकता है, उसकी जाति पूछने में क्या गड़बड़ी है? अगर जाति पूछना अपमान है तो वह जातिगत जनगणना कैसे कराएंगे?

सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी हंगामे और भारी शोरगुल के बावजूद स्पीकर ने प्रश्नकाल जारी रखा। इस दौरान राहुल गांधी सदन में नहीं थे। कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई समेत विपक्ष के कई सदस्यों के हाथों में 'वी वांट कास्ट सेंसस' के पोस्टर देखे गए, जिसे स्पीकर के टोकने के बावजूद सदन में लहराया जा रहा था। इस दौरान गोगोई और कुछ और विपक्षी सदस्यों ने कागज फाड़कर वेल में फेंक दिए। विपक्ष अनुराग ठाकुर की ओर से माफी की मांग कर रहा था, जबकि राहुल ने मंगलवार को कहा था कि वह माफी की मांग नहीं करेंगे।

स्पीकर के मना करने के बावजूद हंगामा कम नहीं हुआ। इस पर स्पीकर ने कहा, 'यह सही तरीका नहीं है। आपके पक्ष का कोई व्यक्ति सवाल उठा रहा है और आप उसे बोलने नहीं दे रहे हैं? आप किसी व्यक्ति को बोलने से नहीं रोक सकते। हर किसी को अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने का अधिकार है।'

नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राहुल खुद दिनभर जाति-जाति रटते रहते हैं। किंतु किसी ने उनसे उनकी जाति पूछ ली तो हंगामा किया जा रहा है। रिजिजू ने कांग्रेस पर सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया और कहा कि वह देश में हिंसा और अराजकता भड़काने का प्रयास कर रही है। एक दिन पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल का नाम लिए बगैर कहा था कि जिनकी जाति का पता नहीं वह जातिगत गणना की बात करते हैं। संसद के बाहर भी रिजिजू ने विपक्षी हंगामे को देश, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश करार दिया।

पीएम को भाषण पोस्ट करने की क्या जरूरत थी : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री के पोस्ट की निंदा करता हूं, उन्हें पता होना चाहिए कि कहां बोलना है और किसका बचाव करना है। इसके बजाय वह भावनाओं को भड़काने की बात कर रहे हैं। संसद में इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।' खरगे ने कहा, 'उन्होंने जानबूझकर उनका (राहुल) अपमान करने के लिए ऐसा कहा। यह सही नहीं है। वह (अनुराग) अपरिपक्व हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को पोस्ट करने की जरूरत थी?' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती।

चन्नी ने दिया पीएम के विरुद्ध विशेषाधिकार नोटिस

अनुराग ठाकुर के भाषण का वीडियो एक्स पर पोस्ट करने के लिए कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया। स्पीकर ओम बिरला को भेजे नोटिस में चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पोस्ट वीडियो में अनुराग की वे टिप्पणियां भी शामिल हैं, जिन्हें पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही से निकाल दिया था। हालांकि सूत्रों का कहना कि चन्नी का नोटिस शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने कहा कि अनुराग की टिप्पणियां संसदीय रिकार्ड का हिस्सा हैं और उनकी टिप्पणियों को हटाया नहीं गया है।

राहुल का व्यवहार अक्षम्य : संबित पेज>>3

केरल सरकार को सप्ताहभर पहले दी गई थी चेतावनी, नहीं हुई अलर्ट : शाह

नई दिल्ली में बुधवार को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बोलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एएनआइ

- कहा- राज्य सरकार अलर्ट हो गई होती तो काफी नुकसान बच जाता
- केंद्र ने 23 जुलाई को केरल में भेजी थीं एनडीआरएफ की नौ बटालियन
- सप्ताहभर पूर्व चेतावनी देने वाले सिर्फ चार देश हैं, जिनमें से एक भारत भी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वायनाड में भूस्खलन से तबाही और मौतों के लिए केंद्र पर तोहमत थोपने वाले विपक्ष को तब मुंह की खानी पड़ी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्पष्ट किया कि केरल को एक सप्ताह पहले तीन बार चेतावनी दी गई थी कि भारी बारिश और भूस्खलन भी हो सकता है। लोगों की जान जा सकती है। केंद्र की ओर से 23 जुलाई को एनडीआरएफ की नौ बटालियन भी भेज दी गई। यदि राज्य सरकार अलर्ट हो गई होती तो काफी नुकसान बचाया जा सकता था।

शाह ने कहा कि 2014 के बाद से केंद्र ने आपदा की अर्ली वार्निंग का विकसित तंत्र तैयार किया है। अर्ली वार्निंग देने वाले दुनिया में सिर्फ चार देश हैं, जिनमें भारत एक है। इसमें भारी वर्षा, तेज गर्मी, तूफान और चक्रवात के लिए चेताया जाता है। पूर्व में कई राज्यों ने वार्निंग का फायदा उठाकर जानें बचाई भी हैं लेकिन केरल में जो हुआ, वह दुखद है।

बुधवार को शाह ने दोनों सदनों में अपना बयान दिया। कई सदस्यों ने सवाल उठाया था कि केंद्र ने राज्य को चेतावनी क्यों नहीं भेजी। शाह ने कहा कि 23, 24 और 26 जुलाई को केरल को पूर्व चेतावनी दी गई। साफ कहा था कि राज्य में 20 सेमी से ज्यादा वर्षा होगी और भूस्खलन होने की भी आशंका है, जिसमें लोग मर सकते हैं। इतनी स्पष्ट वार्निंग के बावजूद केरल सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। शाह ने बताया कि पूर्व में सात दिन पहले ओडिशा को चक्रवात का अलर्ट भेजा गया था, जिस पर तत्कालीन नवीन पटनायक सरकार ने काम किया और सिर्फ एक व्यक्ति की मौत, वो भी गलती से हुई। गुजरात सरकार को भी तीन दिन पहले चक्रवात का अलर्ट भेजा और वहां एक पशु भी नहीं मरा। फिलहाल भारत सरकार केरल की जनता और सरकार के साथ डटकर खड़ी है।

केरल के सीएम ने शाह के दावे को किया खारिज पेज>>7

हर जिंदगी है कीमती, ऐसे नहीं जाने दे सकते जान : हाई कोर्ट

कोचिंग सेंटर हादसा मामला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- कहा- मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति के कारण ही बुनियादी ढांचा ठीक नहीं कर रही दिल्ली सरकार
- दिल्ली को त्रासदी का इंतजार, मजाक बनकर रह गया एमसीडी, आयुक्त को किया तलब

राव आइएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में जलभराव का पानी घुसने से यूपीएससी के तीन अभ्यर्थियों की मौत से आहत दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए बेहद तल्ख टिप्पणियां की हैं। कहा कि हर जिंदगी कीमती है। ऐसी लापरवाही से जान जाने नहीं दे सकते हैं। इस मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एक त्रासदी का इंतजार कर रही है। सरकार की सिविक अथारिटी दिवालिया है। एमसीडी मजाक बन कर रह गया है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति के कारण जब सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आधारभूत सुविधाओं को उन्नत करने को बुनियादी ढांचा कैसे उन्नत करेगी? पूरे मामले में एमसीडी सिर्फ अपनी जवाबदेही दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कुटंब नामक संगठन की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। एमसीडी के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए पीठ ने पूछा कि जब बिल्डिंग उपनियमों को सरल बनाया जा रहा था तो पहली बार में सदियों पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड क्यों नहीं किया गया? शहर के बुनियादी ढांचे और वर्तमान जरूरतों के बीच एक बड़ा अंतर है। छह मंजिला इमारत की अनुमति दी जा रही है तो इंजीनियर को इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति का अंदाजा होगा। पीठ ने एमसीडी आयुक्त को तीन अगस्त को होने वाली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने और सभी संबंधित रिकार्ड भी पेश करने को कहा।

याची संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आवासीय क्षेत्र में दर्जनों लाइब्रेरी चल रही हैं और एमसीडी खामोश बैठी है। हम एक तरह के जंगल में रह रहे हैं, जहां लोग आग और पानी की वजह से मर रहे हैं। इन इलाकों में कई वर्तमान आयुक्तों की संपत्ति है और एमसीडी और अग्निशमन विभाग जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जवाबदेही तय करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पटेल नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर में कई बहुमंजिला इमारतें हैं और एक-एक इमारत में 50 से 60 छात्र रह रहे हैं। यहां तक की बेसमेंट भी पीजी के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।

क्या किसी अधिकारी को पकड़ा या पूछताछ की : पीठ ने पूछा कि क्या किसी अधिकारी को पकड़ा गया या उससे पूछताछ की गई है? क्या उन्होंने उस अधिकारी से पूछताछ की है जिसने इस नाले से गाद नहीं निकलवाई? क्या नाले से समय पर गाद निकाली गई थी?

कोर्ट ने कहा, अजीब जांच चल रही है पेज>>2

हमास प्रमुख हानिया की तेहरान में हत्या, इजरायल पर शक

- राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने आए थे
- सोते समय मिसाइल से हुआ हमला, अंगरक्षक भी मरा
- ईरान ने कहा, हत्या का बदला लेना उसकी जिम्मेदारी
- अमेरिका बोला, हमला होने पर इजरायल का देंगे साथ

इस्माइल हानिया। फाइल

तेहरान, रायटर : गाजा पट्टी में प्रभावशाली हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया की बुधवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई। 62 वर्षीय हानिया राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए ईरान आए थे उसी दौरान जब वह अपने ठहरने के स्थान पर विश्राम कर रहे थे-तभी मिसाइल हमले में उनकी हत्या कर दी गई। हमले में एक अंगरक्षक भी मारा गया है। इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी ने नहीं ली है लेकिन शक इजरायल पर है। इजरायल ने हानिया की मौत पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है लेकिन इजरायल के विरासती मामलों के मंत्री अमिचय एलियाहू ने हत्या पर खुशी जाहिर की है। हमास प्रमुख की हत्या से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका है, साथ ही गाजा में युद्धविराम के प्रयासों को झटका लगने के आसार हैं। चीन, रूस, तुर्किये, इराक और कतर ने हानिया की हत्या की निंदा की है।

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा है कि हमला ईरान में हुआ है इसलिए जवाब देने की जिम्मेदारी भी ईरान की है। हानिया की हत्या के लिए जिम्मेदार को कड़ा दंड दिया जाएगा। हानिया ने हत्या से कुछ घंटे पहले मंगलवार को तेहरान में खामेनेई से मुलाकात की थी। हानिया की मौत पर ईरान ने तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। ईरान के तेवर देखते हुए इजरायल ने भी बचाव और जवाब देने की तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री योएव गैलेंट ने कहा है कि हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

जनवरी में हमास के दूसरे बड़े नेता अरूरी की हत्या हुई

2017 में हमास के पोलित ब्यूरो का प्रमुख बनने के बाद से ज्यादातर समय हानिया ने तुर्किये और कतर में व्यतीत किया था। वहीं से वह फलस्तीन को लेकर गतिविधियां चलाते थे और समर्थक देशों की यात्राएं करते थे। जनवरी में हमास के दूसरे नंबर के नेता सालेह अल-अरूरी की लेबनान में इसी तरह से हवाई हमले में हत्या हुई थी। अरूरी की हत्या की जिम्मेदारी इजरायल ने नहीं ली थी लेकिन शक उसी पर किया गया था।

इजरायल के सौ से ज्यादा बंधकों की जिंदगी को खतरा

हानिया के मारे जाने से गाजा में युद्धविराम के लिए चल रहे प्रयासों के बाधित होने का अंदेशा है। कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही वार्ता में हानिया के निर्देशन में ही हमास नेता बातचीत कर रहे थे। कतर और मिस्र ने युद्धविराम की कोशिशों को झटका लगने और उसमें गतिरोध पैदा होने की बात कही है। हानिया की मौत की प्रतिक्रिया गाजा में बंधक बने 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को झेलनी पड़ सकती है। जानकारों के अनुसार अब इन बंधकों के जीवन को खतरा पैदा हो गया है। हमास की सैन्य शाखा ने कहा है कि अब इजरायल के साथ लड़ाई को नए स्तर पर ले जाया जाएगा।

अमेरिका बोला, हानिया की मौत से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा पेज>>11

भारी वर्षा से पूरी दिल्ली में लगा जाम

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को हुई बारिश के दौरान दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जाम से जूझते वाहन। प्रेट्र

- धौला कुआं से गुरुग्राम की ओर जाने वाले एनएच-8 पर जीजीआर परेड रोड पर भारी जलभराव के कारण यातायात काफी प्रभावित हुआ
- विकास मार्ग पर कई किमी लंबा जाम लग गया, उत्तरी जिले में दिल्ली गेट, दरियागंज, लाल किला, चांदनी चौक पर घंटों जाम में फंसे वाहन
- मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरने के कारण भी जाम लगा, जिससे कनाट प्लेस आउटर सर्किल और मिंटो रोड पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया

(विस्तृत समाचार पेज 2 पर)

पूजा खेडकर अब नहीं रहीं आइएएस अधिकारी

नई दिल्ली : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने विवादों में फंसी प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को कहा कि उसने पूजा खेडकर की अंतरिम उम्मीदवारी रद कर दी है। इस तरह अब पूजा खेडकर आइएएस अधिकारी नहीं रहीं। (पेज-5)

स्कूल में नर्सरी के बच्चे से चली गोली, एक छात्र घायल

त्रिवेणीगंज (सुपौल) : बिहार के सुपौल जिले में सेंट जान बोर्डिंग स्कूल में नर्सरी का पांच वर्षीय बच्चा बुधवार को बैग में लोडेड पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंच गया और साथियों को दिखाने के दौरान गोली चल गई, जो तीसरी के एक छात्र को जा लगी। (पेज-6)

अच्छी पहल

छात्रों को निजी कोचिंग सेंटरों के चंगुल से निकालने का प्रयास, निश्शुल्क आनलाइन कोचिंग 'साथी' में शामिल होंगी ये परीक्षाएं, पिछले वर्ष जेईई-मेन की तैयारी से हुई थी कोचिंग की शुरुआत

अब कैट, क्लैट और सीयूईटी की भी कोचिंग दिलाएगी सरकार

अरविंद पांडेय • जागरण

नई दिल्ली में बुधवार को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बोलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एएनआइ

नई दिल्ली : निजी कोचिंग सेंटरों पर छात्रों से न सिर्फ बड़ी रकम वसूलने, बल्कि कई अन्य सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन पर नकेल कसने की मांग उठ रही है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों को कोचिंग सेंटरों की दुनिया से बाहर लाना चाहती है और इसके लिए कानूनी और सामाजिक हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। इसमें सरकारी 'साथी' (सेल्फ असेसमेंट, टेस्ट एंड हेल्प आफ एंट्रेंस एक्जाम) कारगर होगा। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष जेईई-मेन की तैयारी कराने से हुई थी। अब इसके जरिये जेईई-एडवांस, नीट-यूजी और केंद्रीय सेवाओं के ग्रेड-2 व ग्रेड-3 श्रेणी के कर्मचारियों के चयन के लिए आयोजित एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निश्शुल्क आनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें जल्द ही विधि संस्थानों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा क्लैट, प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा कैट के साथ ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा सीयूईटी को शामिल करने की तैयारी है। कोई भी छात्र इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराकर पढ़ सकेगा।

प्रतिवर्ष इन सभी परीक्षाओं में देश के 50 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं। ऐसे में यह पहल इन सभी छात्रों के लिए बड़ी मदद है। सरकार का इस दिशा में उत्साह तब बढ़ा है, जब इस वर्ष उसे जेईई-मेन की कोचिंग में बड़ी सफलता मिली। इसके जरिये पढ़ाई करने वाले 12 सौ से ज्यादा छात्रों ने क्वालीफाई किया।

'साथी' प्रोजेक्ट से जुड़े शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, आने वाले दिनों में इसे निजी आनलाइन कोचिंग के मुकाबले खड़ा करने की तैयारी है। उसमें आइआइटी, एनआइटी, आइआइएम और एम्स जैसे देश के शीर्ष संस्थानों के शिक्षकों की मदद ली जा रही है। वे न सिर्फ पढ़ाएंगे, बल्कि वे छात्रों की मदद के लिए आनलाइन उपलब्ध भी रहेंगे। उनके विषय आधारित वीडियो और लेक्चर तैयार कराकर डाले जा रहे हैं।

यह अंग्रेजी और हिंदी के साथ ही तमिल, कन्नड़ व उर्दू जैसी भाषाओं में भी है। इस पहल को छात्रों के लिए इसलिए भी उपयोगी माना जा रहा है क्योंकि इनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता में कोई संशय नहीं है, दूसरा इसके लिए छात्रों को निजी कोचिंग की तरह मोटी राशि नहीं चुकानी पड़ेगी।

छात्र इन माध्यमों से भी जुड़ सकते हैं इस कोचिंग से

प्रतियोगी छात्रों की सुविधा के लिए शिक्षा मंत्रालय सरकारी आनलाइन कोचिंग 'साथी' को वेब पोर्टल के साथ ही मोबाइल एप, यू-ट्यूब, डीटीएच चैनल आदि के जरिये भी उपलब्ध करा रही है। जिन छात्रों के पास इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए ग्राम पंचायतों के कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर यह सुविधा मुहैया करा जा रही है। मंत्रालय ने इसे लेकर सीएससी के साथ करार भी किया है। मौजूदा समय में 'साथी' प्लेटफार्म पर दस हजार से अधिक घंटों की अध्ययन सामग्री मुहैया कराई गई है। इसके लिए छह सौ से अधिक मेंटर जोड़े गए हैं। वहीं अब तक इस पर डेढ़ लाख छात्र पंजीकृत हो चुके हैं।

****

दूसरे पदक से एक जीत दूर लवलीना

नई दिल्ली, जेएनएन

- 75 किग्रा वर्ग में नार्वे की सुनीवा को हराकर अंतिम आठ में पहुंचीं लवलीना
- सेमीफाइनल में पहुंचते ही कम से कम कांस्य पदक हो जाएगा पक्का

पेरिस ओलिंपिक में बुधवार का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। मुक्केबाजी से लेकर बैडमिंटन और तीरंदाजी से लेकर निशानेबाजी में हमारे खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइ (75 किग्रा) ने पेरिस में जीत से अपने अभियान की शुरुआत करते हुएव नार्वे की सुनीवा होफस्ताद को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

अब लवलीना लगातार दूसरे ओलिंपिक पदक जीतने और भारतीय मुक्केबाजी में अभूतपूर्व उपलब्धि से महज एक जीत दूर हैं। लवलीना के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही कम से कम कांस्य पदक पक्का हो जाएगा, हालांकि यह उनके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनका सामना चीन की शीर्ष वरीय लि कियान से होगा। उधर, बैडमिंटन के सिंगल्स वर्ग में पीवी सिंधू और लक्ष्य सेन ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।

पेरिस ओलिंपिक में बुधवार को नार्वे की सुनीवा होफस्ताद के खिलाफ जीत दर्ज कर प्रसन्नता जाहिर करतीं भारत की लवलीना। एएफपी

(पेज-12 भी देखें)

5 कोचिंग सेंटरों को दिल्ली नगर निगम ने बुधवार को बेसमेंट में चलने के कारण सील किया है। इसमें तीन संपत्तियां पश्चिमी जोन में और दो संपत्तियां दक्षिणी जोन में सील की गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 1 अगस्त, 2024

आज का मौसम

सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने एवं हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
1 अगस्त	33.0	27.0
2 अगस्त	33.0	26.0
नोएडा		
1 अगस्त	36.0	27.0
2 अगस्त	37.0	28.0
गुरुग्राम		
1 अगस्त	33.0	30.0
2 अगस्त	32.0	29.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

केजरीवाल, सिसोदिया व कविता की हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली: आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने इसी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सिसोदिया और के. कविता की न्यायिक हिरासत नौ अगस्त तक बढ़ा दी। अदालत ने 25 जुलाई को मनी लांड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ाई थी, जबकि भ्रष्टाचार मामले में उनकी हिरासत आठ अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। (जासं)

दोहरी नागरिकता की मांग वाली याचिका ठुकराई

नई दिल्ली: विदेशों में भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इन्कार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि दोहरी नागरिकता की अनुमति देने पर संसद को निर्णय लेना है, यह मुद्दा हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पीठ ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं और इसके व्यापक प्रभाव हैं। (जासं)

विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली शराब नीति मामले में अनियमितताओं से मनी लांड्रिंग मामले में व्यवसायी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति हृषिकेश राय, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने नायर के वकील के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया। (एएनआइ)

कोचिंग संस्थानों के लिए कानून बनाएगी दिल्ली सरकार

कसेंगे नकेल ▶ संस्थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, मनमानी फीस व भ्रामक विज्ञापनों पर रोक बनाया जाएगा नियम

राज्य सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट के जरिये दिल्ली में कोचिंग संस्थानों का करेगी विनियमन

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

दिल्ली में अब नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगेगी। इन संस्थानों की अवैध गतिविधियों और मनमानी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी। नए कानून द्वारा सरकार कोचिंग संस्थानों में जरूरी बुनियादी ढांचा, मनमानी फीस पर लगाम, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, शिक्षकों की योग्यता सहित तमाम जरूरी बिंदुओं को नियमित करेगी।

बुधवार को दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी और महापौर शैली ओबराय ने प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में फैली है, लेकिन इन्हें नियमित करने के लिए अब तक कोई केंद्रीय कानून नहीं है। मगर दिल्ली सरकार केंद्र के कानून बनाने का इंतजार नहीं करेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट के जरिये दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की अनियमितताओं पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कानून बनाने के लिए सरकार कमेटी गठित करेगी। इसमें दिल्ली सरकार और एमसीडी के अधिकारियों समेत कोचिंग संस्थानों के छात्र भी हिस्सा होंगे। सरकार ने इसके लिए एक ईमेल एड्रेस coaching.law.feedback@gmail.com जारी किया है। आतिशी ने दिल्ली के लोगों और छात्रों से इस पर फीडबैक देने की अपील की है। आतिशी ने कहा कि जिस प्रकार प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस बनती है, मान्यता दी जाती है, लगातार निरीक्षण किया जाता है। उसी प्रकार दिल्ली सरकार एक कानून बनाएगी जो दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों के लिए नियम तय करेगा।

आतिशी ने कहा कि 27 जुलाई की शाम ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग संस्थान में ऐसी घटना हुई। तुरंत सरकार की अलग-अलग एजेंसियां वहां पहुंचीं और रात 11 बजे मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। राजस्व विभाग को इसके लिए 24 घंटे का समय दिया गया। 29 जुलाई को एक अंतरिम जांच रिपोर्ट आई। आतिशी ने कहा कि कोचिंग सेंटर बेसमेंट में क्लास चलाते हैं। हादसे वाले कोचिंग संस्थान में लाइब्रेरी चल रही थी, वो अवैध है। भवन विभाग से इस कोचिंग सेंटर को बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग और स्टोर के लिए अनुमति मिली थी, लेकिन यहां लाइब्रेरी चलाई जा रही थी।

200 कोचिंग सेंटर को दिया है नोटिस: महापौर शैली ओबराय ने कहा कि जहां-जहां कोचिंग सेंटरों ने नालों पर अतिक्रमण किया है, जहां भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में क्लास चला रहे हैं, अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहे हैं, उन पर पिछले तीन दिनों में सख्त कार्रवाई हो रही है। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर इलाके में कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को सील किया गया है।

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने ओल्ड राजेंद्र नगर में धरना दे रहे छात्रों से मुलाकात की। दिल्ली सरकार

शिकायत को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई

आतिशी के मुताबिक जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि किस अधिकारी ने राउ आइएएस स्टडी सर्किल में बेसमेंट के अवैध उपयोग के बारे में एक आइएएस छात्र द्वारा एमसीडी को भेजी गई शिकायत को नजरअंदाज कर दिया, जहां तीन छात्रों की मौत हो गई। आतिशी ने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच से यह पता लगाया जाएगा कि शिकायत पोर्टल का प्रभारी कौन सा अधिकारी था जहां शिकायत अपलोड की गई थी और इसे कैसे नजरअंदाज किया गया। ग्वालियर के एक सिविल सेवा अभ्यर्थी ने सोमवार को दावा किया था कि उसने संस्थान द्वारा बेसमेंट के अवैध उपयोग के बारे में एमसीडी से शिकायत की थी और 15 और 22 जुलाई को पत्र भेजे थे लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

महापौर शैली ओबराय ने कहा कि दिल्ली में जहां पर भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में क्लास चला रहे हैं, अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहे है। उन पर भी पिछले तीन दिनों में सख्त कारवाई हो रही है। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर इलाकों में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील किया गया है। 30 से ज़्यादा बड़े कोचिंग सेंटर की बेसमेंट की सील किया गया है। अभी भी बेसमेंट की सीलिंग चालू रहेगी।

केंद्र सरकार भी कोचिंग सेंटरों के लिए बनाए कानून : आम आदमी पार्टी

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को गंभीरता लेते हुए दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए कानून लाने जा रही है। आप के दिल्ली संयोजक गोपाल राय और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली में कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने की पहल शुरू कर दी है, लेकिन देश भर के कोचिंग सेंटर को भी कानूनी दायरे में लाना जरूरी है। इसलिए दिल्ली की तरह केंद्र की मोदी सरकार भी सख्त कानून बनाए, ताकि कोचिंग सेंटर खोलने, हास्टल चलाने और फीस लेने के लिए एक तय प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। संजय सिंह ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है, लेकिन केंद्र कब तक कानून बनाएगी, यह नहीं पता है। राय ने कहा कि संसद में चर्चा के दौरान आइएनडीआइए के सभी दलों ने भी कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने पर सहमति जताई है। वहीं, संजय सिंह ने कहा कि जानकारी मिली है कि मंगलवार को एलजी ने अधिकारियों व कोचिंग सेंटर मालिकों की बैठक बुलाई थी। भाजपा के लोग कहते हैं कि सभी मामलों में आपदोषी है, लेकिन एलजी दिल्ली में बैठकर किस तरह की साजिश कर रहे हैं, इसके बारे में भी जनता को पता चलना चाहिए।

बड़े कोचिंग हबों में सरकार बनाएगी लाइब्रेरी और रीडिंग रूम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर में राव स्टडी सर्किल के बाहर धरने पर बैठे छात्रों से बुधवार को शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुलाकात की। आतिशी ने छात्रों को हर मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेयर फंड से दिल्ली के बड़े कोचिंग हब्स में सरकारी लाइब्रेरी- रीडिंग रूम बनाए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोचिंग सेंटरों के बनने वाले क़ानून ड्राफ्ट करने की प्रक्रिया में 10 छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। आतिशी ने छात्रों की सभी मांगें सुनीं और कहा कि हमारा वादा है कि घटना की जांच पूरी होते ही जिम्मेदार हर छोटे-बड़े अधिकारियों पर सख्त कारवाई की जाएगी।

निगमायुक्त ने भी शिकायतों के निवारण का दिया आश्वासन : एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार से निगम मुख्यालय में 28 छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को उनकी शिकायतों के निवारण का आश्वासन दिया। छात्रों की मांग थी कि संपत्ति मालिक और प्रापर्टी डीलर उनसे किराये पर कमीशन वसूलते हैं, उसको रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि इसको रोकने के लिए विकसित क्षेत्रों में कोचिंग हब का विस्तार किया जा सकता है। मृतकों के परिवारों को सहायता राशि देने की बात पर आयुक्त ने कहा कि पहले ही राशि जारी की घोषणा हो चुकी है, सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा।

एलजी ने कोचिंग हब बनाने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

▶ वीके सक्सेना ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कोचिंग सेंटर संचालकों की ली बैठक

राजधानी में एक जगह कोचिंग हब बनाया जाएगा। एलजी वीके सक्सेना ने डीडीए उपाध्यक्ष को इसके लिए नरेला और रोहिणी में ऐसी जगहों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। यहां पर कोचिंग संस्थानों को समायोजित किया जाएगा।

ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद एलजी ने सोमवार को छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इसमें उन्होंने छात्रों को उनकी तमाम समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया था। मंगलवार को उन्होंने कोचिंग सेंटर संचालकों और विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एलजी ने दिल्ली में कोचिंग के पूरे व्यवसाय को नई, सुरक्षित और सुविधाजनक रूपरेखा देने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की। सक्सेना ने कोचिंग संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की। समिति में कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि, छात्रों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति सभी मापदंडों को पूरा करते हुए

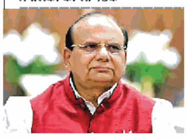

एलजी वीके सक्सेना। फाइल

अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने, मकान मालिकों द्वारा अत्यधिक किराया वसूलने, फायर एनओसी, नालों से गाद निकालने जैसे तमाम मुद्दों पर काम करेगी। यह समिति कोचिंग संस्थानों को धीरे-धीरे विभिन्न स्थानों से सुनियोजित क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्ययोजना तैयार करेगी। मुख्य सचिव की ओर से सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों, ट्यूशन कक्षाओं आदि के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नियामक ढांचा तैयार करने का मुद्दा शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा।

एलजी ने बेसमेंट में लाइब्रेरी या शिक्षण सुविधा चलाने वाले किसी भी कोचिंग संस्थान को तुरंत सील करने के निर्देश दिए। इस पर भी सहमति बनी कि अल्पकालिक उपाय के रूप में संस्थान छात्रों को अपने भवनों कि अन्य मंजिलों पर पढ़ने के कमरे के रूप में स्थान प्रदान करके सहायता करेंगे। एलजी के अनुरोध पर कोचिंग संस्थानों के महासंघ द्वारा तीनों मृत छात्रों के शोक संतप्त परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सहमति बनी। नामांकित छात्रों को हुई परेशानी को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी शुल्क में छूट देने की पेशकश की गई है। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त को इन क्षेत्रों में वसूले जा रहे अत्यधिक किराये और कर चोरी पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त सभी बीट कांस्टेबलों, स्थानीय एसएचओ के बीच ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को सहानुभूतिपूर्ण सक्रिय सहायता प्रदान की जा सके। अधिकारियों के मुताबिक, एलजी ने सभी कोचिंग सेंटरों और वहां पर नामांकित छात्रों के लिए आधार-आधारित लाग-इन क्रेडेंशियल के साथ एक पोर्टल बनाने के आदेश भी जारी किए।

12 एटीएम काटकर एक करोड़ रुपये लूटने वाला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नूंह के रहने वाले कुख्यात एटीएम लुटेरे वाहिद को गिरफ्तार किया है। वह दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र व असम सहित कई राज्यों में एटीएम काटकर रुपये लूटने के 12 मामलों में वांछित था। उक्त एटीएम में करीब एक करोड़ रुपये थे। यह हत्या, हत्या का प्रयास, लूटपाट, डकैती, पुलिस पर गोली चलाने, हथियार अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम व एटीएम तोड़ने सहित 50 से अधिक मामलों में शामिल रहा है। तीन मामलों में कोर्ट उसे भगोड़ा घोषित कर चुका है। उसके कब्जे से एक पिस्टल व पांच कारतूस बरामद हुए हैं।

डीसीपी प्रतीक्षा गोदारा के मुताबिक, वाहिद उर्फ रति खान उर्फ अफरीदी, नावली, फिरोजपुर झिरका, नूंह का रहने वाला है। एटीएम तोड़ने में शामिल नूंह के रहने वाले बदमाश स्पेशल सेल के रडार पर रहे हैं। सेल को बीते दिनों वाहिद के बारे में जानकारी मिली, जो दिल्ली के दो मामलों में भगोड़ा है और अन्य राज्यों के एटीएम तोड़ने के मामलों में वांछित था।

कोर्ट ने कहा, चल रही है अजीब जांच

प्रथम पृष्ठ से आगे

कोर्ट ने जांच पर टिप्पणी की कि बहुत ही अजीब जांच चल रही है। अब तक किसी एमसीडी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। नहीं पता कि जांच अधिकारी ने गाद निकालने की योजना देखी है या स्वीकृत भवन निर्माण योजना देखी है या नहीं। हमें नहीं पता कि उसने ऐसा किया है या उसने एमसीडी अधिकारियों की भूमिका की जांच की है। अदालत ने कहा कि पुलिस किसी भी राहगीर या ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश कर रही है और कह रही है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने कार चलाई थी।

हाई कोर्ट ने पूछा, एसयूवी चालक की क्या जिम्मेदारी थी : हाई कोर्ट ने ने पूछा, क्या अब तक किसी अधिकारी को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? हम आपको बता रहे हैं, एक बार अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय हो जाए, भविष्य में ऐसी कोई घटना कभी नहीं होगी। अदालत ने पूछा एसयूवी चालक को क्यों गिरफ्तार किया गया? आखिर उसकी क्या जिम्मेदारी थी?

मामले में दिल्ली पुलिस को पक्षकार बनाते हुए अदालत ने संबंधित जिले के उपायुक्त व जांच अधिकारी को भी अगली सुनवाई पर पेश होकर यह बताने को कहा कि अब तक क्या जांच की गई है। अदालत ने दो दिन में ओल्ड राजेंद्र नगर में नाले की सफाई व अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिया।

जांच ठीक से नहीं हुई तो केंद्रीय एजेंसी को लगाएंगे : दिल्ली सरकार के अधिवक्ता द्वारा कार्रवाई के लिए कदम उठाने का तर्क देने पर पीठ ने कहा कि यह एक ऐसी रणनीति है जहां किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। संकेत दिया कि अगर जांच अधिकारी सही से जांच नहीं करते हैं तो हम इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपेंगे।

अदालत की अहम टिप्पणियां

- सभी अनधिकृत निर्माण पुलिस व एमसीडी की मिलीभगत से हो रहे हैं
- वरिष्ठ अधिकारियों के बजाय राहगीर को क्यों गिरफ्तार किया गया
- कनिष्ठ अधिकारी को तो बर्खास्त किया, एसी कमरे में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों का क्या
- दिल्ली सरकार की सिविक अथारिटी दिवालिया, वेतन देने के नहीं है पैसे, कैसे करेंगे मूलभूत ढांचा उन्नत

वर्षा से जगह-जगह जल भराव से थमी रफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरने के कारण कनाट प्लेस आउटर सर्किल और मिंटो रोड पर ट्रैफिक को किया डायवर्ट

▶ कमला मार्केट के गोल चक्कर से मिंटो रोड पर आने वाले यातायात को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग से रणजीत सिंह फ्लाईओवर से किया डायवर्ट

राजधानी में बुधवार शाम को हुई भारी वर्षा के कारण पूरी दिल्ली में भीषण जाम लग गया। आइटीओ चौराहे पर जाम लगने से नई दिल्ली व मध्य दिल्ली की सड़कों पर भी वाहनों के पहिये थम गए। पुराना पुलिस मुख्यालय के एक्जिट गेट से आइपी फ्लाईओवर तक इंद्रप्रस्थ मार्ग पर पानी भरने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। अपोलो अस्पताल से बदरपुर की ओर जाने वाली मथुरा रोड पर सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास पानी भर जाने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

धौला कुआं से गुरुग्राम की ओर जाने वाले एनएच-8 पर जीजीआर परेड रोड पर भारी जलभराव के कारण यातायात काफी प्रभावित हुआ। विकास मार्ग पर कई किमी लंबा जाम लग गया। बदरपुर से संगम विहार की ओर जाने वाली एमबी रोड पर काया माया पार्क के पास पानी भरने से यातायात घंटों बाधित हुआ। उत्तरी जिले में दिल्ली गेट, दरियागंज, लाल किला, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट व रिंग रोड पर वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा। इसके अलावा एमबी रोड पर पानी भरने के कारण खानपुर से हमदर्द और इसके विपरीत दोनों तरफ की सड़कों पर भीषण जाम लग गया। क्राउन प्लाजा से कालिंदी कुंज और इसके विपरीत दोनों तरफ ओखला अंडरपास में पानी भर गया। लोगों की सुरक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर बैरिकेड लगा दिए गए।

यातायात पुलिस के मुताबिक, मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरने के कारण जाम लग गया। जिससे कनाट प्लेस आउटर सर्किल और मिंटो रोड पर ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया। यात्रियों को जेएलएन मार्ग, बाराखंबा रोड और रणजीत सिंह मार्ग से वैकल्पिक मार्ग लेने को कहा गया। कनाट प्लेस से मिंटो रोड पर आने वाले यातायात को कनाट प्लेस आउटर सर्किल, बाराखंबा रोड से तुर्कमान गेट, कमला मार्केट की ओर रणजीत सिंह फ्लाईओवर से डायवर्ट कर दिया गया। यातायात को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग से कनाट प्लेस की ओर रणजीत सिंह फ्लाईओवर के माध्यम से डायवर्ट किया गया।

नई दिल्ली में बुधवार को हुई बारिश के बाद पूसा रोड के पास जलमग्न सड़कों में डूबी बाइकें और वाहनों की कतारें। प्रेट्र

सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे

जासं, नई दिल्ली : बुधवार शाम को हुई तेज वर्षा से दिल्ली में जनजीवन प्रभावित हुआ है। जलभराव से निजात दिलाने की मांग के फोन आते रहे। कंट्रोल रूम में देर शाम तक 80 शिकायतें आई थीं। वहीं एलजी वीके सक्सेना से लेकर सरकार के मंत्री लगातार वर्षा को लेकर जानकारी लेते रहे। शिक्षा और राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा है कि बुधवार शाम को बहुत भारी बारिश होने और भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर गुरुवार को सभी सरकारी और निजी स्कूल एक अगस्त को बंद रहेंगे।

नोएडा के मकान में शार्ट सर्किट से लगी आग, तीन बहनें जिंदा जलीं; पिता गंभीर

जागरण संवाददाता, नोएडा

▶ सेक्टर-8 झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) कालोनी में हुआ हादसा, पति व पत्नी भी झुलसे

आस्था। सौ स्वजन

अराध्या। सौ स्वजन

नैना। सौ स्वजन

सेक्टर-8 झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) कालोनी में स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रिकल शार्ट सर्किट के कारण एक मकान में भीषण आग लग गई। हादसे में पति-पत्नी और उनकी तीन बेटियां झुलस गईं। सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान तीनों बच्चियों की मौत हो गई। वहीं बच्चियों के पिता को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है। वहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल में भर्ती बच्चियों की मां की हालत स्थिर है। फेज-1 कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लय गांव थाना किशनी मैनपुरी के दौलतराम पत्नी मीनू (30), पुत्र हनी (11) पुत्री आस्था (10), नैना (7) व अराध्या (5) के साथ सेक्टर-8 बिजली घर के बगल में स्थित झुग्गी-झोपड़ी के डी-240, डी पीकेट में प्रथम तल पर किराये के मकान में रहते थे। उन्होंने बिजली घर में संविदा पर कार्यरत संदीप से 1500 रुपये प्रतिमाह पर 10 गुना 12 फीट का एक कमरा ले रखा है। पिछले सात साल से वह शहर में ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। पत्नी भी आसपास के घरों में घरेलू सहायिका थी। मंगलवार रात मकान में तीनों बच्चे बेड पर, जबकि पति-पत्नी जमीन पर सो रहे थे। रात करीब तीन बजे मकान में शार्ट सर्किट के बाद आग लग गई। इसके बाद बिजली चली गई और चीख-पुखार मच गई। दौलतराम और उनकी पत्नी ने जान दांव पर लगाकर तीनों पुत्रियों आस्था, नैना, आराध्या को बाहर निकाला। चीख-पुखार सुनकर पड़ोसी भी पहुंचे। सभी घायलों को पड़ोसियों की मदद से एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने आस्था, नैना, आराध्या को मृत घोषित कर दिया। 30 प्रतिशत से अधिक झुलसे होने पर दौलतराम को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डाक्टरों का कहना है कि आग लगने के बाद तीनों बच्चियां बुरी तरह से झुलस गई थी।

पहल

एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के सीएसआर फंड के जरिये इसका निर्माण होगा, साफ पानी, फूड वेडिंग मशीन, वेटिंग हाल आदि इसमें होगा

एम्स में 500 लोगों के बैठने के लिए बनेगा सुविधाओं से युक्त लाउंज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

एम्स में 500 मरीजों और तीमारदारों के बैठने के लिए लाउंज बनाया जाएगा। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के सीएसआर फंड के जरिये इसका निर्माण होगा। इसका निर्माण गेट संख्या दो के पास स्थित पार्किंग के स्थान पर होगा। एम्स मीडिया सेल की पीआइसी प्रो. रीमा दादा ने बताया कि लाउंज सर्वसुविधायुक्त होगा। एयरपोर्ट के लाउंज की तर्ज पर यहां भी पीने का साफ पानी, फूड वेडिंग मशीन, वेटिंग हाल आदि इसमें होगा। पूरे दिन में यहां तीन से चार हजार लोग बारी-बारी से बैठ सकेंगे।

प्रो. दादा ने बताया कि अस्पताल में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन कई कदम उठा रहा है। हाल में बस सेवा भी शुरू की जा रही है। मरीज बाहर बैठे रहते हैं, उनको देखते हुए लाउंज बनाने का निर्णय लिया गया है। मरीजों की सुविधा के लिए अंडर ग्राउंड पार्किंग के ऊपर, मदर चाइल्ड ब्लाक के पास पहले से ही वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में और सार्थक प्रयास किया गया है। लोगों की आवाजाही आरामदायक बनाने के लिए ई-बस सेवा शुरू की जा रही है। आधुनिक सुविधाओं जैसे एयर-कंडीशनिंग, ऊर्जा-बचत प्रवेश के लिए लो फ्लोर और व्हीलचेयर एक्सेस के साथ इन ई-बसों (20-सीटर) का एक और सेट केवल एम्स मरीजों और उनके देखभाल करने वालों को प्रदान किया जाएगा। इनमें बैठकर मरीज परिसर के भीतर कहीं भी जा सकेंगे। सुबह सात से शाम सात बजे तक सेवा रहेगी। इस दौरान हर 10 से 15 मिनट में बस मिलेगी। मरीजों के लिए आश्रय और काल बटन के साथ निर्दिष्ट स्टाप की सुविधा होगी।

एम्स दिल्ली। फाइल

चेहरे और गर्दन के दुर्लभ ट्यूमर को हटाया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आमतौर पर हृदय में पाए जाने वाले ट्यूमर को गंगाराम अस्पताल के डाक्टरों ने बुजुर्ग मरीज के सिर और गर्दन की सर्जरी कर निकाला है। डाक्टरों का कहना है कि ऐसी सर्जरी अभी तक नहीं की गई है। भारत के मेडिकल साहित्य में ऐसा कोई रिपोर्टेड केस नहीं मिला है।

सर्जरी करने वाली टीम का हिस्सा रहीं डा. संगीता अग्रवाल ने बताया कि एक 60 वर्षीय पुरुष रोगी को सांस लेने और खाना निगलने में परेशानी और आवाज में परिवर्तन की शिकायत के बाद गंगाराम अस्पताल की ओपीडी में भेजा गया था। प्रारंभ में उसे लेटने के दौरान सांस लेने में कठिनाई होती थी, फिर धीरे-धीरे उसे सीधी स्थिति में भी कठिनाई होने लगी। उसे सिर और गर्दन की सर्जरी टीम द्वारा जांच की गई और एमआरआइ और कोर सुई बायोप्सी की सलाह दी गई। रिपोर्ट में उसे एक बड़ा ट्यूमर निकला। जिसका आकार लगभग 9-10 सेमी था, जो नाक के पीछे के हिस्से के साथ-साथ श्वासनली और भोजन की नली पर दबाव डाल रहा था, जिससे सांस लेने और निगलने में कठिनाई हो रही थी। इसके लिए कोर सुई बायोप्सी के साथ रैबडोमायोमा का निदान किया गया। ट्यूमर पूरे खोपड़ी के आधार और गर्दन के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। डा. अग्रवाल ने कहा, यह एक बहुत ही दुर्लभ ट्यूमर है और इस आकार के ट्यूमर का इस हिस्से में (जिसे पैराफेरिंजील स्पेस कहा जाता है) भारत में कोई दर्ज मामला नहीं मिला है।

****

दिनदहाड़े रोडरेज में गोली मारकर महिला की हत्या

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली

उत्तर पूर्वी जिले में बदमाशों का आतंक चरम पर है। बुधवार को गोकलपुरी थाना क्षेत्र के वजीराबाद रोड पर रोडरेज में नकाबपोश स्कूटी सवार ने दिनदहाड़े एक महिला के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त महिला अपने पति व दो बच्चों के साथ बुलेट मोटरसाइकिल से घर से बैंक जा रही थी। मृतका की पहचान सिमरनजीत कौर के रूप में हुई है।

सिमरनजीत कौर। स्वजन

वैसे वजीराबाद रोड कांवड़ यात्रा मार्ग है, जहां पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवान कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए जगह-जगह तैनात हैं। इसके बावजूद स्कूटी सवार हत्या करके भाग गया।

मृतका के जेठ अवतार सिंह ने बताया कि हीरा सिंह को बच्चों के खाते से कुछ रुपये निकालने थे। इसलिए वह बुधवार को करीब दो बजे पत्नी व बच्चों के साथ बैंक जाने के लिए निकले। करीब 2:45 बजे जब वह गोकलपुरी फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो एक स्कूटी सवार तेज गति से बाइक के बराबर से निकला। इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया। उनके भाई ने विरोध किया तो स्कूटी सवार ने मारपीट पर उतारू हो गया। आरोपित स्कूटी लेकर फ्लाईओवर पर चढ़ गया और पिस्टल निकालकर हीरा पर गोली चला दी। गोली हीरा की जगह पत्नी के सीने में लगी।

11.32 लाख टन दालों का आयात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-मई अवधि के दौरान किया। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में सरकार ने 47.39 लाख टन दालों का आयात किया था।

किसी राज्य से भेदभाव नहीं, मिलेंगे 22.91 लाख करोड़ : सीतारमण

वित्त मंत्री ने राज्यसभा में दिया बजट पर चर्चा का जवाब, कहा- केरल की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख को सही ठहराया

कृषि के लिए आवंटन संप्रग सरकार के मुकाबले पांच गुना ज्यादा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में राज्यों को कम आवंटन अथवा उनके साथ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि राज्यों को इस वर्ष 22.91 लाख रुपये दिए जाने हैं और यह राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 2.49 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।

वित्त मंत्री ने रेखांकित किया कि कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य- सभी सेक्टरों पर आवंटन बढ़ा है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के समय इन सभी क्षेत्रों को दिए गए पैसों से तुलना करते हुए बताया कि मोदी सरकार में सामाजिक क्षेत्र और कल्याणकारी योजनाओं में खर्च बढ़ता ही जा रहा है। उदाहरण के लिए कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों को इस बार 1.52 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 8,000 करोड़ रुपये अधिक है, जबकि संप्रग सरकार ने 2013-14 के बजट में कृषि को केवल 30,000 करोड़ रुपये दिए थे। वित्त मंत्री ने दोहराया कि बजट भाषण में किसी राज्य का जिक्र नहीं होने का यह मतलब नहीं होता कि उसे आवंटन नहीं किया गया। उन्होंने संप्रग सरकार के दस वर्षों के दौरान पेश किए गए बजटों को याद करते हुए बताया कि एक बार 26 राज्यों के नाम नहीं लिए गए थे। गौरतलब है कि विपक्ष ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने बजट में केवल बिहार और आंध्र प्रदेश पर ही ध्यान दिया है, क्योंकि उसके लिए जदयू और तेलुगु देसम पार्टी का समर्थन महत्वपूर्ण है और इन दलों को खुश करने की कोशिश की गई है।

गैरभाजपा दलों के शासन वाले राज्यों के साथ सौतेले व्यवहार के आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त ऋण देने के मामले में भेदभाव की केरल सरकार की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के पक्ष को सही ठहराते हुए कहा था कि केरल सरकार अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकी। राज्यसभा में वित्त मंत्री का जवाब लोकसभा (लगभग पौने दो घंटे) में उनके संबोधन के मुकाबले करीब आधे घंटे लंबा था और इसमें मुख्य रूप से आर्थिक सवालों के जवाब अधिक थे। वित्तीय घाटे पर विपक्षी नेताओं की चिंता का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 2025-26 तक घाटे को 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य हासिल करने की राह पर है।

सीतारमण के अनुसार बजट में विकास, रोजगार, कल्याणकारी खर्च, पूंजीगत निवेश और खजाने के प्रबंधन के बीच बेहतरीन संतुलन कायम किया गया है। संप्रग सरकार के दस वर्षों में पूंजीगत खर्च के लिए आवंटन 13.19 लाख करोड़ रुपये था, जबकि मोदी सरकार के दस वर्षों में यह 43.82 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। देश में आज 97 प्रतिशत मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है। भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ) सफल रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक वैश्विक वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत है और यह बढ़ रही है।

अग्निपथ योजना पर राजनीति न हो: वित्त मंत्री ने विपक्ष को यह नसीहत भी दी कि वह अग्निपथ योजना पर कोई राजनीति न करे, क्योंकि यह योजना देश के सशस्त्र बलों को युवा बनाने के साथ ही युद्ध के लिए सदैव तैयार रखने के लिए लाई गई है। विपक्ष की ओर से इस योजना की आलोचना को खारिज करते हुए सीतारमण ने कहा कि 17.5 से 21 वर्ष उम्र वाले युवाओं की सेना में नियुक्ति से देश को फिट सैनिक मिलेंगे। इस योजना को लेकर अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह योजना सरकार पूरी तरह सोच-समझकर लाई है।

नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देती केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

मोदी सरकार की नीतियों से जम्मू कश्मीर की आर्थिकी हुई बेहतर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार के प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बहुत सुधरी है। जम्मू कश्मीर के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश हुंडी व्यवस्था (एक प्रकार की हवाला प्रणाली) के दौर से बाहर आ गया है। अब रोजमर्रा के खर्चों के लिए जे एंड के बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर काम चलाने का दौर समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। अनुच्छेद-370 की समाप्ति के बाद राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे।

सीतारमण ने कहा कि पिछले चार वर्षों में जे एंड के बैंक में कायापलट वाला बदलाव देखने को मिला है। 2019-20 में यह बैंक 1,139 करोड़ रुपये के घाटे में था, लेकिन 2023-24 में यह 1,700 करोड़ रुपये के मुनाफे में आ गया है। यह केंद्र शासित क्षेत्र अब वित्तीय रूप से बहुत समर्थ स्थिति में है और लोगों की विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में आ गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि एक समय था जब संप्रग सरकार में अलगाववादियों के स्वागत के लिए लालकालीन बिछाया जाता था, लेकिन आज हमारे सुरक्षा बलों और एजेंसियों ने स्पष्ट नीति के तहत आतंकियों और अलगाववादियों को किनारे कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमने जम्मू कश्मीर पुलिस का भार अपने कंधों पर लिया है तो क्या गलत है। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के व्यय अपने हिस्से में लेने से हमने स्थानीय प्रशासन को यह अवसर दिया है कि वह अपने संसाधनों का इस्तेमाल विकास और जनकल्याण के दूसरे कार्यों में कर सके।

अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के खबरियों के भत्ते बढ़े

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो दशकों से भी अधिक समय के बाद अर्धसैनिक बलों और अन्य खुफिया एजेंसियों के महानिदेशकों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें 'अभियानों' के लिए काम कर रहे इनफार्मरों के भत्ते बढ़ाने को कहा है। देश के लिए खुफिया जानकारी जुटाने वाले इन खबरियों के लिए उनके 'खर्चे-पानी' का इंतजाम किया गया है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी), नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) और नेशनल पुलिस एकेडमी (एनपीए) के महानिदेशकों (डीजी) के विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए हैं। जून में जारी आदेश में कहा गया था कि मौजूदा समय में अभियानों के लिए तैनात गाइडों, दुभाषिये और खबरियों को एक समय में 50 रुपये और सालाना 500 रुपये देने का अधिकार है। लेकिन अब इस मद में भत्ते की इस सीमा को प्रति व्यक्ति एक बार में न्यूनतम तीन हजार रुपये कर दिया है जो सालाना अधिकतम धनराशि 30 हजार रुपये की जा सकेगी। जारी आदेश के अनुसार इन भत्तों में बढ़ोतरी पिछली बार वर्ष 2002 में हुई थी।

दुनिया में सबसे सस्ती काल दरों वाले देशों में शामिल है भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र : दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि भारत में अब 117 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 93 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हैं। यही नहीं दुनिया में भारत सबसे सस्ती काल दरों वाले देशों में शुमार है।

सिंधिया ने कहा कि पहले काल की दर 53 पैसा प्रति मिनट थी जो अब सिर्फ तीन पैसा प्रति मिनट है जिसमें 93 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि देश में एक जीबी डाटा की कीमत 9.12 रुपये है, जो दुनिया में सबसे कम है। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया इनीशिएटिव के तहत टायर-2 और टायर-3 शहरों में लगभग 800 करोड़ रुपये की कुल राशि से टेक्नोलाजी इन्क्यूबेशन एंड डेवलपमेंट आफ एंटप्रेन्योर्स (टाइड 2.0), जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फार इनोवेटिव स्टार्टअप्स (जेनेसिस), डोमेन स्पेसिफिक सेंटर्स फार एक्सीलेंस (सीओईएस) और नेक्स्ट जेनेरेशन इन्क्यूबेशन स्कीम (एनजीआइएस) जैसे विभिन्न तकनीकी स्टार्टअप्स एवं इनोवेशन योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि मार्च, 2024 तक देश में कुल इंटरनेट ग्राहकों में से 39.83 करोड़ ग्राहक ग्रामीण थे। देश के 6,44,131 गांवों में से 6,12,952 गांवों में 3जी/4जी मोबाइल कनेक्टिविटी है। लिहाजा, 95.15 प्रतिशत गांवों में इंटरनेट की पहुंच है।

- दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बताया, देश में अब 117 करोड़ मोबाइल कनेक्शन

ज्योतिरादित्य सिंधिया। एएनआइ

स्वदेशी तकनीक से बुलेट ट्रेन बनाने पर काम कर रहा है भारत : वैष्णव

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया है कि भारत बुलेट ट्रेन बनाने की स्वदेशी तकनीक पर काम कर रहा है। देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलनी है और इसकी बहुत ही जटिल तकनीक है। इस पर जापान की मदद से काम हो रहा है। इसे भारतीय जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा रहा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन को बताया कि शुरुआत में हमें बुलेट ट्रेन की तकनीक विदेश से मिली। लेकिन अब देश में भी कई तकनीकों का विकास हो गया है। अब भारत बुलेट ट्रेन को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाने और 'आत्मनिर्भर भारत' बनने की दिशा में काम कर रहा है।

उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अधिकतम सुरक्षा और रखरखाव के प्रोटोकाल तकनीकी रूप से बहुत जटिल और गहन हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना से संबंधित सिविल कार्य, ट्रैक, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग, टेलीकम्यूनिकेशंस और ट्रेन सेट की आपूर्ति का काम पूरा होने के बाद ही प्रोजेक्ट पूरा होने की समय-सीमा का पालन किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना (शिंदे) नीत सरकार आने के बाद से वहां भी कार्य की गति बहुत तेज हो गई है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन 508 किमी की दूरी तय करेगी। इसमें 320 किमी की दूरी पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। भारत की पहली 21 किमी लंबी समुद्र के नीचे बनी सुरंग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

रेल मंत्री ने बताया कि 9784 रेलवे पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाएगा। महाराष्ट्र के पुराने पुलों की पहचान की गई है और पिछले तीन सालों से इनकी मरम्मत का काम चल रहा है। महाराष्ट्र के सभी ब्रिज सुरक्षित हैं। पिछले तीन सालों में 5405 पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जा चुका है। रेल मंत्री ने बताया कि कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के लिए एक रेल डिविजन बनाने की बात थी, लेकिन सर्वेक्षण के बाद उस मांग को उचित नहीं पाकर इसे प्रस्तावित नहीं किया गया है।

- रेल मंत्री ने कहा-अब देश में भी कई तकनीकों का हो गया है विकास
- रेलवे ने दी 9784 रेल ब्रिजों की मरम्मत और पुनर्निर्माण को मंजूरी

अश्विनी वैष्णव। प्रेट्र

संसद प्रश्नोत्तर

केवी में प्रवेश के लिए सांसद कोटा फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में प्रवेश के लिए सांसदों के लिए विवेकाधीन कोटा फिर से शुरू करने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। शिक्षा राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

जयन्त ने कहा- 'सांसदों के कोटे सहित कुछ विशेष प्रविधानों के तहत स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश दिए गए थे, जिससे कक्षाओं में छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बढ़ने के कारण पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसदों के लिए कोटा फिर से शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।' विशेष प्रविधान के तहत सांसदों के पास केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों के प्रवेश की सिफारिश करने का विवेकाधीन अधिकार था। यहां तक कि एक जिला मजिस्ट्रेट के पास केंद्रीय विद्यालयों में स्पांसरिंग अथारिटी कोटे के तहत 17 छात्रों की सिफारिश करने का अधिकार था। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्य सामूहिक रूप से कोटे के तहत एक वर्ष में 7,880 दाखिले की सिफारिश कर सकते थे। 2022 में केंद्र ने ये कोटा खत्म कर दिया था।

जयन्त चौधरी। एएनआइ/फाइल

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण अक्टूबर, 2025 तक होगा पूरा : गडकरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत के सबसे लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण अक्टूबर, 2025 तक पूरा हो जाएगा। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय ने 1,386 किलोमीटर की लंबाई वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू कर दिया गया है। गडकरी ने कहा कि 1,136 किमी लंबाई का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

असम में इस साल बाढ़ से 117 लोगों की हुई मौत: नित्यानंद राय : असम में बाढ़ के कारण इस वर्ष अब तक 117 लोगों की मौत हुई है। पिछले पांच सालों में देखे तो बाढ़ से राज्य में 880 लोगों की जान चली गई है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि असम सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2019 से 27 जुलाई 2024 तक असम में विनाशकारी बाढ़ के परिणामस्वरूप कुल 880 लोगों की जान चली गई। वहीं, 2023 में 65, 2022 में 278, 2021 में 73, 2020 में 190 और 2019 में 157 लोगों की मौत हुई है।

बीएसएफ में 10,145 पद खाली: नित्यानंद : गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि इस साल 1 जुलाई तक सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कुल 10,145 पद खाली हैं। इसमें 387 समूह 'ए' में राजपत्रित अधिकारियों के लिए हैं, 1,816 पद समूह 'बी' में अधीनस्थ अधिकारियों के लिए हैं और 7,942 पद समूह में अन्य रैंक समूह 'सी' के लिए हैं। देश में सीमा सुरक्षा बल में वर्तमान रिक्तियों के विवरण के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने यग लिखित जवाब में बताया।

देश में चारे की कमी: ललन सिंह : मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने बताया कि देश में चारे की कमी है। उन्होंने कहा, 'आइसीएआर-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (आइजीएफआरआइ) झांसी ने अनुमान लगाया है कि देश में हरे और सूखे चारे की क्रमशः 11.24-32 प्रतिशत और 23 प्रतिशत कमी है।' एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि देश में दूध का उत्पादन 2018-19 में 18.77 करोड़ टन से बढ़कर 2022-23 में 23.06करोड़ टन हो गया है।

राज्यसभा में संघ के बचाव में आए धनखड़, कहा-राष्ट्र की सेवा में रत

नई दिल्ली, प्रेट्र : उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सपा सांसद की टिप्पणी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का बचाव करते हुए कहा कि उसकी निर्दोष साख है और वह राष्ट्र की सेवा कर रहा है।

प्रश्नकाल के दौरान सपा सदस्य रामजी लाल सुमन ने कहा कि एनटीए प्रमुख को चुनने में सरकार ने संघ से जुड़े व्यक्ति को अपनी वरीयता में रखा। इस पर धनखड़ ने खुद आपत्ति जताते हुए कहा कि यह बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

सभापति ने दो टूक कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्र के विकास की यात्रा में अपनी भागीदारी देने का पूरा अधिकार है। यह संगठन निर्दोष साख रखता है। यह उन लोगों को अपने साथ लेता है जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा कि इस कथन का सार यह है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र कल्याण में योगदान देता है और हमारी संस्कृति को संजोने का काम करता है। ऐसा कोई भी संगठन जो इतनी प्रतिबद्धता से काम करे, उसके लिए गर्व का अनुभव करना चाहिए।

इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सपा सदस्य सुमन का बचाव करते हुए कहा कि अगर कोई सदस्य नियमों के तहत अपनी बात कह रहा है और किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो उसे अपना बयान देने से रोकना नहीं चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सपा सदस्य रामजी लाल सुमन जो कह रहे थे वह सही है और सभापति धनखड़ का उन्हें रोकना गलत है।

इस पर सभापति धनखड़ ने कहा कि खरगे ने यह संकेत दिया है कि जब नियमों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा हो तो सभापति को दखल देना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि वह देख रहे हैं कि लोग विभाजनकारी गतिविधियों में अधिक लिप्त रहते हैं। यह देश के विकास को रौंदने की प्रणाली के लिए काम कर रहे हैं।

- सपा सदस्य सुमन के बयान पर जताई आपत्ति, कहा-रिकार्ड में नहीं जाएगी बात
- कहा-संघ को राष्ट्र के विकास की यात्रा में अपनी भागीदारी देने का पूरा अधिकार

सभापति जगदीप धनखड़ बुधवार को सदन को संचालित करते हुए। प्रेट्र

पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन बनीं यूपीएससी की नई चेयरपर्सन

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया है। वह मनोज सोनी का स्थान लेंगी। वर्तमान में वह यूपीएससी की सदस्य हैं और गुरुवार को नया कार्यभार संभालेंगी। उनका कार्यकाल अप्रैल 2025 तक होगा। मनोज सोनी ने प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी पूजा खेड़कर से जुड़े विवाद के बीच चार जुलाई को 'निजी कारणों' से इस्तीफा दे दिया था। आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की रिटायर्ड आइएएस अधिकारी सूदन ने महिला एवं बाल विकास, रक्षा मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया है। उन्हें सरकार में प्रशासन का करीब 37 वर्षों का अनुभव है।

सूदन को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत मिशन में अहम योगदान के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल आयोग और ई-सिगरेट पर प्रतिबंध का कानून बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में उनका कार्यकाल अक्टूबर 2017 से जुलाई 2020 तक रहा। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्य रणनीतिकार की भूमिका निभाई। उन्होंने तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल के सदस्य के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा, सूदन ने वर्ल्ड बैंक के साथ सलाहकार के रूप में काम कर चुकीं हैं। उन्होंने सोशल पालिसी एंड प्लानिंग में एमएससी और लंदन स्कूल आफ इकोनामिक्स से अर्थशास्त्र में एम फिल की डिग्री हासिल की है।

यूपीएससी की चेयरपर्सन प्रीति सूदन। फाइल

चीन से सामान्य स्थिति बहाली के लिए एलएसी का सम्मान जरूरी : भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को हल करने के लिए बुधवार को बातचीत की। यह वार्ता भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) के ढांचे के तहत दिल्ली में हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने लंबित मुद्दों का जल्द समाधान खोजने के उद्देश्य से एलएसी पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। शांति और स्थिरता की बहाली और एलएसी के प्रति सम्मान द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए एक आवश्यक आधार है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन के प्रतिनिधि दोनों सरकारों के बीच प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकाल के अनुसार सीमा क्षेत्रों में जमीन पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए। मंत्रालय ने कहा, बैठक में हुई चर्चा रचनात्मक और भविष्योन्मुखी थी। दोनों पक्ष स्थापित राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से बातचीत की गति बनाए रखने पर सहमत हुए।

बताते चलें, पूर्वी लद्दाख में कुछ जगहों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद कई इलाकों से सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। लेकिन, कुछ क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी होनी है। इस गतिरोध का असर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ा है। भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों के लिए सीमा पर स्थिति सामान्य होना जरूरी है।

- दोनों पक्षों ने लंबित मुद्दों के समाधान के लिए एलएसी के हालात की समीक्षा की

विमानन क्षेत्र में कारोबार को और आसान बनाएगी सरकार, विधेयक पेश

नई दिल्ली, प्रेट्र: विमानन क्षेत्र में कारोबार को और आसान बनाने के लिए सरकार ने बुधवार को 90 साल पुराने विमान अधिनियम की जगह लेने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 में विमान अधिनियम, 1934 को बदलने का प्रयास किया गया है। विमान अधिनियम, 1934 को अब तक 21 बार संशोधित किया जा चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में विमानों के डिजाइन और निर्माण को विनियमित करने का प्रविधान शामिल है।

एक अधिकारी ने बताया कि एक बार यह अधिनियम लागू हो जाने के बाद रेडियो टेलीफोन आपरेटर (प्रतिबंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस जारी करने का काम विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा किया जाएगा, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है।

राहुल का व्यवहार अक्षम्य : संबित पात्रा

प्रथम पृष्ठ से आगे

भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में संबित पात्रा ने कहा कि जब से 18वीं लोकसभा शुरू हुई है, तब से 99 की संख्या और अहंकार का खेल दिखाई दे रहा है। राहुल का व्यवहार और उसके कारण उनकी पार्टी के सदस्यों का व्यवहार अक्षम्य है। अनुराग ठाकुर ने तो किसी का नाम नहीं लिया था और कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं, वह गणना की बात कर रहे हैं तो एक ही व्यक्ति को बुरा लगा, जबकि सदन में 543 सदस्य हैं।

पात्रा ने कहा कि पिछले दिनों राहुल पत्रकारों से जाति पूछ रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि हलवा समारोह में किस-किस जाति के अधिकारी हैं। वह जजों-सैनिकों की जातियां भी पूछते हैं और कहते हैं कि देश को जानने का अधिकार है कि किस जाति के सर्वाधिक सैनिक हैं। कांग्रेस के सदस्यों ने संसद में चिल्ला-चिल्लाकर कहा कि यह पवित्र सदन है, यहां किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। जब सदन में नहीं पूछी जा सकती तो बाहर कैसे पूछी जा सकती है? क्या यह धरती पवित्र नहीं है, सिर्फ सदन ही पवित्र है?

अनुराग ने साझा किया अखिलेश का पुराना वीडियो : जाति पर विवाद के बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने इंटरनेट मीडिया पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक पुराना वीडियो साझा किया। इसमें उन घटनाओं का संकलन है जिनमें अखिलेश ने पत्रकारों से उनकी जाति पूछी थी। इस वीडियो में अखिलेश को पत्रकार की जाति के बारे में जानबूझकर पूछताछ करते और फिर उसके उपनाम का मजाक उड़ाते दिखाया गया है।

उधर अखिलेश ने कहा, 'मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकता जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से साफ किया गया था। मुख्यमंत्री आवास गंगाजल से कैसे साफ किया जा सकता है, अब आप चांद पर जाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया, अमृतकाल, विकसित भारत की बात करते हैं और फिर भी मंदिरों को गंगाजल से धोते हैं।'

****

कह कर रहेंगे

माधव जोशी

78 सदस्य हैं भाजपा के ओडिशा विधानसभा में, जबकि विपक्षी बीजद के पास 51 सीटें हैं। 14 सीटों पर कांग्रेस, तीन पर निर्दलीय और एक पर सीपीआइ (एम) का कब्जा है

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 1 अगस्त, 2024

विस चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन से बदल सकती है देश की राजनीति : सोनिया

कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा, माहौल पार्टी के पक्ष में

जनगणना में देरी, जम्मू-कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमले जैसे मुद्दे पर घेरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को नई दिल्ली में मानसून सत्र के दौरान संसद में सीपीपी की आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद रवाना हुईं। साथ में पार्टी सांसद राजीव शुक्ला और रजनी पाटिल भी हैं। एएनआइ

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जनगणना नहीं कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसा कर एससी-एसटी की आबादी का अनुमान लगाने से रोका जा रहा है। साथ ही दावा किया कि जनगणना में देरी की वजह से कम से कम 12 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून के लाभ से वंचित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली संजीवनी के मद्देनजर सोनिया गांधी ने चार राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत व विश्वास के साथ लग जाने का आह्वान करते हुए कहा कि माहौल पार्टी के पक्ष में है। बेहतर चुनावी नतीजे देश की राजनीति बदल सकते हैं।

संसद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की बुधवार को हुई पहली बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने जम्मू-कश्मीर में बढ़ते आतंकवादी हमलों की घटनाएं, मणिपुर में जारी हिंसा से लेकर देश में समुदायों को विभाजित कर वैमनस्य बढ़ाने की राजनीति कायम रहने जैसे मुद्दों पर राजग सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार का 2021 की जनगणना अब भी कराने का कोई इरादा नहीं दिख रहा और इससे देश की जनसंख्या, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अद्यतन अनुमान नहीं लग पाएगा। इसका अर्थ है कि करीब 12 करोड़ नागरिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभ से वंचित रहेंगे।

आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के लिए पार्टी जनों को प्रोत्साहित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो उत्साह तथा सद्भावना मिली है, उसे बरकरार रखा जाए। पार्टी जनों को आत्मसंतुष्ट और अति-आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, मगर हमें एकजुट होकर काम करना होगा। चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से देश की राजनीति में बदलाव आएगा। आम बजट की खामियां गिनाते हुए उन्होंने दावा किया कि किसानों व युवाओं की मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। सामाजिक वैमनस्य बढ़ने की चर्चा करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि उम्मीद थी कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में गिरावट से सबक लेगी, मगर इसके बजाय वह समुदायों को विभाजित करने और भय और दुश्मनी का माहौल फैलाने की अपनी नीति पर कायम हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम पट्टिका लगाने के विवाद की ओर संकेत करते हुए कहा कि सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया। मगर यह केवल एक अस्थायी राहत हो सकती है। नौकरशाही को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए अचानक नियम बदलने पर भी सवाल उठाया गया और कहा गया कि संघ खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है, पर पूरी दुनिया यह जानती है कि यह भाजपा का राजनीतिक व वैचारिक आधार है। ऐसे में नियम में यह असंवैधानिक है।

मणिपुर की स्थिति को लेकर की आलोचना

संसदीय दल की बैठक शुरू होते ही सबसे पहले वायनाड के भूस्खलन में मारे गए लोगों और दिल्ली के कोचिंग संस्थान में डूबने से तीन छात्रों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। इसके बाद सोनिया गांधी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की भूमिकाओं की प्रशंसा की तो राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाली जम्मू-कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं का जिक्र किया। कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में अकेले जम्मू क्षेत्र में कम से कम 11 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें सुरक्षाकर्मियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की जान गई है। ये घटनाएं मोदी सरकार के दावों का मजाक उड़ाती हैं। मणिपुर में स्थिति में सुधार नहीं है और पीएम दुनियाभर की यात्रा करते हैं, पर वहां जाकर सामान्य स्थिति बहाली की पहल नहीं करते हैं।

संघ, सरकार और भाजपा के बीच दूरी कम करने की कवायद हो गई है तेज...

नीलू रंजन • जागरण

- सरकारी कर्मियों के संघ से जुड़ने से रोक हटाने के आदेश को गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट के होम पेज पर लगाया
- हरियाणा विस चुनाव पर हुई समन्वय बैठक में आरएसएस के सुझावों पर काम करने का भाजपा ने दिया भरोसा

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद भाजपा, सरकार और संघ के बीच दूरी कम करने की कवायद तेज हो गई है। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर दशकों पुराने प्रतिबंध को हटाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्मिक विभाग के इस आदेश को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर लगाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सरकार के इस फैसले से अवगत कराना है। दूसरी ओर, आरएसएस भी भाजपा में संगठन मंत्रियों की कमी को दूर करने के लिए नए प्रचारक भेजने को तैयार है। सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के फैसले को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इससे संबंधित दाखिल याचिका से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन गृहमंत्रालय ने फैसले को अपनी वेबसाइट के पहले पेज लगाने के फैसले को सीधे तौर पर संघ के साथ संबंधों को बेहतर बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि गृहमंत्रालय के बाद अन्य मंत्रालय भी अपनी वेबसाइट पर कार्मिक मंत्रालय के आदेश को लगाने का फैसला ले सकते हैं। सरकार के इस फैसले से 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे आरएसएस को अपने सामाजिक कार्यों की स्वीकार्यता बढ़ाने और अपनी गतिविधियों का दायरा बड़ा करने में मदद मिल सकती है। भाजपा और आरएसएस के बीच बेहतर समन्वय का अंदाजा कई सालों बाद संगठन मंत्रियों को भेजे जाने की तैयारी भी लगाया जा सकता है। दरअसल भाजपा में संगठन मंत्री आरएसएस द्वारा भेजे जाते हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और पार्टी के बीच बेहतर समन्वय का काम करते हैं। फिलहाल कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान बड़े राज्यों में संगठन मंत्री के खाली पद हैं। पिछले दिनों हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की समन्वय बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी की ओर से नियुक्त केंद्रीय प्रभारियों ने आरएसएस की ओर मिले सुझावों को चुनाव तैयारियों में शामिल करने का आश्वासन दिया।

राजस्थान में कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रम में शामिल होने पर लगी रोक हटाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, जयपुर : केंद्र के बाद अब राजस्थान की भाजपा सरकार भी प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है। कार्मिक और विधि विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश के बाद केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक हटाने के आदेश का अध्ययन किया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत इस संबंध में अधिकारियों के साथ अनौपचारिक चर्चा कर चुके हैं। वर्ष 1981 में राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई थी। 18 मार्च 1981 को तत्कालीन मुख्य सचिव मदन मोहन किशन वाली द्वारा जो आदेश जारी किया गया था, उसके मुताबिक प्रदेश का कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस, जमात-ए-इस्लामी और आनंद मार्ग संगठन के न तो सदस्य बन सकते हैं, न ही उनकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद सत्ता में आई भाजपा सरकारों ने रोक हटाने पर विचार तो किया, लेकिन निर्णय नहीं हो सका था।

बागी नेताओं के निष्कासन के विरोध में उतरे ढींडसा, बोले-कार्रवाई असंवैधानिक

चंडीगढ़ में हुई बैठक में पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा की बात सुनते शिरोमणि अकाली दल के सरपरस्त सुखदेव सिंह ढींडसा। साथ में हैं गुरप्रताप सिंह वडाला व एसजीपीसी की पूर्व प्रधान बीबी जागीर कौर। जागरण

कैलाश नाथ • जागरण

- एक दिन पहले निकाले गए नेताओं की बैठक में पहुंचकर शिअद सरपरस्त ने किया धमाका
- कहा-सुखबीर को कोई पसंद नहीं करता, पार्टी से कहूंगा सम्मेलन बुलाकर नया प्रधान चुने

चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल की अनुशासन कमेटी द्वारा पार्टी के 8 बागी नेताओं को निष्कासित करने का फैसला पार्टी के सरपरस्त (संरक्षक) सुखदेव सिंह ढींडसा ने यह कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि यह कार्रवाई गैर-संवैधानिक है। यही नहीं, ढींडसा ने यहां तक कहा कि पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर जिस प्रकार के आरोप लगे हैं, उन्हें देखते हुए उन्हें पार्टी के प्रधान पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल को कोई पसंद नहीं करता है इसलिए वह पार्टी से कहेंगे कि वह शीघ्र सम्मेलन बुलाए और नया प्रधान चुने। शिअद ने कल्पना नहीं की होगी कि बागी नेताओं के निष्कासन का कोई नेता पार्टी में रहते हुए इस प्रकार विरोध कर सकता है। सुखदेव ढींडसा पार्टी में हैं जबकि उनके पुत्र परमिंदर सिंह ढींडसा निष्कासितों में हैं।

जानकारों का कहना है कि यद्यपि सुखदेव सिंह ढींडसा ने बागियों के निष्कासन को खारिज कर दिया है पर सरपरस्त होने के नाते उनके पास अपनी बात मनवाने की कोई शक्ति नहीं है। उनकी नाराजगी केवल अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहेगी, उसका पार्टी की अनुशासन कमेटी के फैसले पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा जिसे पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल का वरदहस्त प्राप्त है।

ढींडसा ने अनुशासनहीनता के लिए पार्टी से निकाले गए बागी नेताओं की चंडीगढ़ में बुधवार को हुई बैठक में शामिल होकर सुखबीर बादल के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। पार्टी की निष्कासन कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को निकाला गया, उनमें से किसी को भी नोटिस नहीं जारी किया गया। टकसाली अकालियों ने कुर्बानियां दी हैं, जेल काटी और हरेक मोर्चे पर लड़ाई लड़ी परंतु सुखबीर बादल की न तो कोई कुर्बानी दी है और न ही उन्होंने जेल काटी। उल्लेखनीय है कि पार्टी ने मंगलवार को प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा, गुरप्रताप सिंह वडाला, बीबी जागीर कौर, परमिंदर सिंह ढींडसा, सिकंदर सिंह मलूका, सुरजीत सिंह रखड़ा, सुरिंदर सिंह ठेकेदार व चरणजीत सिंह बराड़ को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। उधर, वरिष्ठ नेता बलविंदर सिंह भूंदड़ ने कहा कि पार्टी के सरपरस्त सुखदेव सिंह ढींडसा के पास अनुशासन कमेटी की कार्रवाई पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद ममता मोहंता ने छोड़ी पार्टी

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीजू जनता दल (बीजद) नेता ममता मोहंता ने बुधवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच उन्होंने अपनी पार्टी भी छोड़ दी है। बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे इस्तीफे में मोहंता ने कहा कि उन्हें लगता है कि पार्टी में उनकी और उनके समुदाय की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा, ''मुझे मयूरभंज के लोगों की सेवा करने और राष्ट्रीय स्तर पर ओडिशा के मुद्दे को उठाने का मौका देने के लिए मैं ईमानदारी से आपका आभार व्यक्त करती हूं।''

वह बीजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। मोहंता के इस्तीफे के साथ ही राज्यसभा में बीजद की ताकत घटकर आठ हो गई। लोकसभा में इसका कोई सांसद नहीं है। भाजपा सूत्रों ने कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि वह उस सीट पर फिर से चुनी जा सकती हैं, जिसे खाली कर रही हैं।

'राजनीति में या तो आप रहोगे या मैं रहूंगा'

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

- पार्टी कार्यकर्ताओं की सम्मेलन में उद्धव ठाकरे ने दी चेतावनी
- कहा, देवेंद्र फडणवीस मुझे और मेरे पुत्र आदित्य को भेजना चाहते थे जेल

उद्धव ठाकरे। फाइल

देवेंद्र फडणवीस।

शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दी है कि राजनीति में या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। उद्धव ने यह बात बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही।

बांद्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि उन्हें महाविकास आघाड़ी सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस मुझे एवं मेरे पुत्र आदित्य को जेल भेजना चाहते थे। अब तक मैं बहुत कुछ सहता रहा। लेकिन, अब मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में या तो आप (फडणवीस) रहोगे, या मैं रहूंगा।

उद्धव ने कहा कि आप मेरा सब कुछ छीन लो। लेकिन हम आपकी नाक पर पैर रखकर सत्ता लेकर आएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अपना चुनाव चिह्न का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मुझे मेरा 'शिवसेना' नाम चाहिए। जब तक यह नहीं मिलता, आप सब लोग नए चुनाव चिह्न 'मशाल' का घर-घर प्रचार कीजिए।

उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के साथ ही भाजपा के केंद्रीय नेताओं को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, जो इन लोगों (मोदी-शाह) के खिलाफ बोले। लेकिन, हम बोले। मैंने कहा कि हम तो ऐसे ही हैं। सत्ता पक्ष में बैठे इन लोगों ने हमारी पार्टी तोड़ दी। लेकिन, हम झुके नहीं। उद्धव ने दिल्ली के नेताओं को भी चुनौती देते हुए कहा कि आप चुनाव प्रचार के लिए मुंबई आओ। हम आपकी बची-खुची गर्मी भी निकाल देंगे। आपको भीख का कटोरा लेकर ही हमारे सामने आना होगा।

ये हमारा आखिरी चुनाव, यदि जीत गए तो हमें कोई चुनौती नहीं दे सकेगा

उद्धव ने कहा कि ये हमारा आखिरी चुनाव है। यदि यह चुनाव जीत गए तो देश में हमें कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उनके विरोधी हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि हाल के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों और ईसाइयों ने खुलकर उनका समर्थन किया। उद्धव ने कहा कि मुस्लिम समाज की एक सभा में मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको मेरे हिंदू होने पर आपत्ति है। लोगों ने कहा कि नहीं। फिर उद्धव ने शिवसेना से गद्दारी करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसको जाना है, जाओ। लेकिन भीतर रहकर दगाबाजी मत करो। मैं शिव सैनिकों को लेकर लड़ाई जीतूंगा।

झारखंड विस का चुनाव राजग के साथ लड़ेगा जदयू

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना: जदयू ने साफ कर दिया है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव वह अकेले नहीं लड़ेगा। बिहार की तरह वहां भी राजग के घटक दल के रूप में ही चुनाव लड़ेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता साथ में मिल-बैठकर इस विषय पर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में राजग की सरकार बनेगी। मालूम हो कि झारखंड विस चुनाव को लेकर जदयू में दुविधा की स्थिति बनी हुई है। पार्टी का एक खेमा स्वतंत्र ढंग से चुनाव लड़ने की वकालत कर रहा है। निर्दलीय विधायक सरयू राय व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात के बाद स्वतंत्र ढंग से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। राय कभी भाजपा के विधायक थे। लेकिन, 2019 के विस चुनाव में उन्होंने तत्कालीन सीएम रघुवर दास को निर्दलीय की हैसियत से पराजित किया।

कांग्रेस आलाकमान से बोले अधीर, तृणमूल के खिलाफ मैं चुप कैसे रह सकता हूं?

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- कहा - पार्टी साथियों के साथ सड़कों पर उतरूंगा और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा
- दिल्ली को बंगाल में पार्टी का झंडा थामे रखने वाले कार्यकर्ताओं से बात करने की जरूरत

अधीर रंजन। फाइल

दिल्ली में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद पूर्व लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने इंटरनेट मीडिया पर अपनी पार्टी के आलाकमान पर तृणमूल कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए अप्रत्यक्ष रूप से हमला किया। अधीर रंजन ने मंगलवार रात को अपने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा कि तृणमूल के खिलाफ मैं चुप कैसे रह सकता हूं, हमारे अलावा और कौन हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से बोलेगा, जिन्हें बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हर दिन पीटा जा रहा है? राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी हर दिन कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

मालूम हो कि अधीर रंजन और कांग्रेस आलाकमान के बीच हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों से पहले ही मतभेद सामने आने लगे थे। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मई में मीडियाकर्मियों को यह बयान दिया था कि चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, यह तय करने का काम अधीर रंजन का नहीं है, बल्कि पार्टी आलाकमान का है। खरगे ने यहां तक कह दिया था कि या तो पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करना होगा या फिर बाहर निकलना होगा। खरगे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अधीर रंजन ने कहा था कि कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य होने के नाते वह भी पार्टी आलाकमान का हिस्सा हैं।

अधीर ने कहा कि आधिकारिक तौर पर आइएनडीआइए का हिस्सा होने के बावजूद तृणमूल ने हम पर अत्याचार करना बंद नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मैं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुप कैसे रह सकता हूं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं अपने जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करूंगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बंगाल के उन पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करने की जरूरत है जो पार्टी का झंडा थामे रखने के लिए रोजाना संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने पार्टी साथियों के साथ सड़कों पर उतरूंगा और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा।

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने भाजपा विधायकों को दी टांग तोड़ने की धमकी

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- बंगाल के कुछ जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बयान पर नाराजगी

हुमायूं कबीर। फाइल

इससे पहले बड़बोले विधायक ने हिंदुओं को गंगा में बहा देने की दी थी धमकी

अपने विवादित बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले बंगाल के मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद के भरतपुर के तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने भाजपा के दो विधायकों को टांग तोड़ने की धमकी दी है। हाल में जिले के बहरमपुर के भाजपा विधायक सुब्रत मैत्रा और मुर्शिदाबाद के भाजपा विधायक गौरी शंकर घोष ने बंगाल के कुछ मुस्लिम बहुल जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। इसके पीछे उन्होंने हिंदुओं के अस्तित्व की रक्षा का तर्क दिया था। भाजपा विधायकों की इसी मांग पर हुमायूं कबीर नाराज हैं।

कबीर ने आरोप लगाया कि ये विधायक देश के लोकतंत्र और सौहार्द को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि अगर दोनों विधायकों ने ज्यादा उछल-कूद मचाया तो मैं उन्हें उल्टा लटका दूंगा। इस पर भाजपा विधायक सुब्रत मैत्रा ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। इसे लेकर हमलोग काफी आतंकित हैं। पहले हुमायूं ने कहा कि हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे, आज कह रहे हैं कि टांग तोड़ देंगे, उल्टा लटका देंगे। भाजपा विधायक गौरी शंकर घोष ने कहा कि राज्य में जिहादी शासन चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य को तालिबानी अंदाज में चला रही हैं। अगर मुख्यमंत्री इन टिप्पणियों को देखते हुए कोई कार्रवाई नहीं करती हैं तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि राज्य में लोकतांत्रिक माहौल है। उल्लेखनीय है कि बंगाल के विभाजन मामले में ममता बनर्जी खुद तल्ख टिप्पणी कर चुकी हैं।

रणनीति

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद सीट से सांसद को लोस में अधिष्ठाता मंडल का सदस्य बनाकर दलित वोटबैंक को साधने की कोशिश की है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने

अवधेश प्रसाद का कद बढ़ाकर चला पीडीए दांव

निशांत यादव • जागरण

अवधेश प्रताप सिंह। फाइल

लखनऊ: पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (पीडीए) के फार्मूले पर चलते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और दांव चल दिया है। फैजाबाद सीट से सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने लोकसभा में अधिष्ठाता मंडल का सदस्य बनाकर दलित वोटबैंक को साधने की कोशिश की है। वहीं, धर्मेंद्र यादव को लोकसभा का मुख्य सचेतक बनाकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी सक्रियता उत्तर प्रदेश में और बढ़ाने के संकेत भी दे दिए हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोटबैंक साधने के लिए विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाया है।

सपा अध्यक्ष ने विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष, किरनपाल कश्यप को मुख्य सचेतक और आशुतोष सिन्हा को सचेतक, जबकि मो. जासमीर अंसारी को सदन का उपनेता मनोनीत किया था। लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद यह कयास लग रहे थे कि अखिलेश विधानसभा में किसी दलित चेहरे को मौका दे सकते हैं। इंद्रजीत सरोज और तूफानी सरोज का नाम इसमें सबसे आगे था। अखिलेश ने माता प्रसाद पांडेय को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि मनोज पांडेय के साथ बागी विधायकों के चले जाने के बाद भी पार्टी में स्वर्ण समाज से आने वाले विधायकों की भूमिका कम नहीं हुई है। उनके साथ पीडीए के अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल में सदस्य, कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाया था। इसी तरह राकेश कुमार उर्फ डा. आरके वर्मा को उप सचेतक बनाया गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को एक्स पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने में पीडीए की उपेक्षा करने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को भी हमलावर होने का मौका मिला। इन आरोपों पर विराम लगाते हुए अखिलेश यादव ने दलित वर्ग से आने वाले सांसद अवधेश प्रसाद को अधिष्ठाता मंडल का सदस्य बना दिया है। वहीं, पिछड़े वर्ग से आने वाले जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा को संसदीय दल का उपनेता बनाकर पीडीए के पिछड़ा वर्ग को महत्व दिया है। आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव को लोस का मुख्य सचेतक बनाने के पीछे विस चुनाव से पहले दूसरी पंक्ति के नेता तैयार करने की भी है।

कश्मीर में कई पूर्व आतंकी राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में

राज्य ब्यूरो, जागरण • श्रीनगर

- जम्मू-कश्मीर में लगातार सुधरते हालात और बदलते राजनीतिक परिदृश्य का साफ दिख रहा असर

जम्मू-कश्मीर में लगातार सुधरते हालात और बदलते राजनीतिक परिदृश्य का असर बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले पूर्व आतंकियों पर भी साफ दिखने लगा है। मुख्यधारा में लौटे कई पूर्व आतंकी भी अपना एक अलग राजनीतिक दल बनाकर विधानसभा चुनाव में उतरने के मूड में हैं। हालांकि पहले भी कई आतंकी बंदूक छोड़कर मुख्यधारा की राजनीति में अपना भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रीय दलों के सहारे।

हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े रहे एक पूर्व आतंकी फारूक बट ने कहा कि नेशनल कान्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स कान्फ्रेंस समेत हर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल ने हमारे कल्याण का यकीन दिलाते हुए हमसे वोट मांगे। हमारे नाम पर वोट भी बटोरे, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसलिए अब हम चाहते हैं कि हमारी बात करने वाला, कश्मीरियों की बात करने वाला कोई संगठन हो। जिहाद, आतंकवाद, आजादी, स्टेटहुड, 370 हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा जम्मू-कश्मीर में शांति खुशहाली और बंदूक छोड़कर एक सामान्य जिंदगी जी रहे पूर्व आतंकियों और उनके स्वजनों के मानवीय मुद्दों का समाधान है।

अनंतनाग जिला के पट्टन के निकट मामूसा के रहने वाले एक अन्य पूर्व आतंकी ने नाम न छापने के अनुरोध पर कहा कि मैं पीपुल्स कान्फ्रेंस में भी शामिल रहा हूं, लेकिन हमारी समस्याओं के समाधान के नाम पर वोट मांगा जाता है, उन्हें हल नहीं किया जाता। अगर हमें गुमराह करने वाली जमात-ए-इस्लामी चुनाव लड़ने की बात कर सकती है तो हम चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते।

कई पूर्व आतंकी बने हैं एमएलसी, विधायक व मंत्री: कश्मीर मामलों के जानकार सलीम रेशी ने कहा कि यहां जावेद शाह, फिरदौस शाह जैसे पूर्व आतंकी मुख्यधारा में शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर विधान परिषद में एमएलसी तक बनाए गए। ऐसे ही कूका पारे ने चुनाव जीता था और वह विधायक बना था। उस्मान मजीद जो कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, वह भी एक पूर्व आतंकी हैं। बिलाल लोधी को पीडीपी ने और फिरदौस शाह और जावेद शाह को नेशनल कान्फ्रेंस ने एमएलसी बनाया था।

****

5 घटनाएं हुईहैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में डाटा उल्लंघन की। संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर ने लोस को बताया कि 2023-24 में दो घटनाएं दर्ज की गई हैं। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण सेवा प्रदाताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

नीट-यूजी की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण 14 अगस्त से शुरू होगा

नई दिल्ली, एएनआइ : राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (नीट-यूजी) 2024 काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होने जा रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के सचिव डा. बी श्रीनिवास ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त से काउंसलिंग शुरू कर रहे हैं। हम छात्रों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पहले कर सकते हैं। यह प्रक्रिया दो महीने तक जारी रहेगी और देश भर के जो छात्र पात्र हैं, वे इसमें भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग आनलाइन चार राउंड में आयोजित की जाएगी। उनसे जब किसी विशिष्ट दिशानिर्देश के संबंध में पूछा गया, तो कहा कि दिशानिर्देश पिछले वर्ष के समान हैं। छात्रों को नीट उत्तीर्ण होना चाहिए। पात्रता मानदंड के अंतर्गत जो कोई भी आएगा, उनकी काउंसलिंग शुरू करेंगे। संशोधित नीट-यूजी 2024 परिणाम शुक्रवार को जारी किए गए थे। पांच मई को आयोजित नीट-यूजी का रिजल्ट चार जून को ही जारी हो गया था। लेकिन बाद में कई गड़बड़ियां सामने आईं।

पूजा खेडकर नहीं रहीं आइएएस अधिकारी, यूपीएससी ने उम्मीदवारी रद की

- भविष्य में होने वाली किसी परीक्षा में शामिल होने पर भी लगा दी रोक
- सीएसई-2022 के नियमों के उल्लंघन पर आयोग ने की कार्रवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने विवादों में फंसी प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने बुधवार को कहा कि उसने पूजा खेडकर की अंतरिम उम्मीदवारी रद कर दी है और भविष्य में उनके किसी परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक लगा दी है। इस तरह अब पूजा खेडकर आइएएस अधिकारी नहीं रहीं। आयोग ने एक बयान में कहा, यूपीएससी ने उपलब्ध रिकार्ड की सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल की है और उन्हें सीएसई-2022 (सिविल सेवा परीक्षा-2022) के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है।

आयोग ने कहा है कि सीएसई-2022 के लिए उनकी अंतरिम उम्मीदवारी रद कर दी गई है और भविष्य में यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में उनके शामिल होने या चयन पर भी स्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। आयोग ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में खेडकर का यह एकमात्र मामला है, जिसमें यह पता नहीं चल पाया कि किसी उम्मीदवार ने

पूजा खेड़कर। इंटरनेट मीडिया

सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित प्रयासों की संख्या पार कर ली है। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण हुआ कि उन्होंने न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता-पिता का नाम भी बदल लिया था। आयोग ने कहा कि यूपीएससी मानक संचालन प्रक्रिया को और मजबूत करने की प्रक्रिया में है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसा मामला दोबारा न हो।

आयोग ने कहा कि पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को अपनी फर्जी पहचान बताकर परीक्षा के लिए स्वीकृत सीमा से अधिक अवसर धोखाधड़ी के जरिये प्राप्त करने को लेकर 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था। उन्हें 25 जुलाई तक इस नोटिस का जवाब देना था, लेकिन उन्होंने जवाब देने के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाने की खातिर चार अगस्त तक का समय मांगा।

आयोग ने कहा कि उन्हें 30 जुलाई को दोपहर बाद साढ़े तीन बजे तक जवाब देने के लिए अंतिम मौका दिया गया था, लेकिन वह निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने में विफल रहीं। 2023 बैच की प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए दिव्यांग कोटे का दुरुपयोग किया। इस मामले में यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

'बार-बार बयान बदल रही पूजा से हिरासत में पूछताछ जरूरी'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पुणे के कलेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत के कारण हो रही कार्रवाई : खेडकर
- यूपीएससी की दली, हम कोई जांच एजेंसी नहीं, धोखाधड़ी करने वालों से गंभीरता से निपटा जाए

विवादित प्रशिक्षु सिविल सेवा अधिकारी (आइएएस) पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर दोनों तरफ से लंबी बहस के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला एक अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया। खेड़कर की तरफ से कहा गया कि पुणे के कलेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। यह कहना गलत है कि उन्होंने नाम बदलकर सीमा से अधिक परीक्षा दी। उन्होंने जानकारी नहीं छिपाई, बस अपने प्रयासों की संख्या गलत बताई। पुलिस का कहना था कि पूजा बार-बार अपना बयान बदल रही हैं। अगर अग्रिम जमानत दी गई तो वह सहयोग नहीं करेंगी। उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।

मालूम हो कि यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने खेड़कर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपीएससी ने खेडकर पर दस्तावेज और पहचान बदलकर परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास करने का आरोप लगाया था। खेडकर की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र जांगला ने यूपीएससी के अधिवक्ता नरेश कौशिक से पूछा कि क्या यह उसकी विफलता है कि उसने ऐसा होने दिया या आवेदक की अति-विशेषज्ञता। क्या उसे पता था कि पूजा खेड़कर द्वारा प्रयासों की जानकारी छिपाई जा रही है। यूपीएससी ने कहा कि हम कोई जांच एजेंसी नहीं हैं। सिस्टम को धोखा देने वाले ऐसे व्यक्तियों से बहुत गंभीरता से निपटा जाना चाहिए। पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि मामले में जांच शुरुआती चरण में है। पूजा ने अपनी खामियों का फायदा उठाकर तथ्यों को छुपाया। उन्होंने पहले मानसिक बीमारी को आधार बनाया, फिर बहु दिव्यांगता (मल्टीपल डिसएबिलटी) कहने लगीं। खेड़कर की अधिवक्ता बीना माधवन का कहना था कि एम्स में आठ डाक्टरों के बोर्ड द्वारा जारी खेड़कर का दिव्यांगता प्रमाणपत्र अदालत में जमा किया गया है। बीना ने दावा किया कि हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये अतिरिक्त प्रयास की अनुमति दी थी। यूपीएससी का कहना था कि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है कि पूजा अतिरिक्त परीक्षाओं में बैठने के योग्य हैं।

न्यूज गैलरी

हर घर तिरंगा अभियान 11 अगस्त से होगा शुरू

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा 11 अगस्त से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान सहित कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता चार दिन तक देशभर में मार्च निकालेंगे। भाजपा विभाजन की भयावहता को याद करने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी। इससे पहले 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी तरह, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अभियान में भाग लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक लोगों के घरों, कार्यालयों और दुकानों पर तिरंगा फहराया जाए। 28 जुलाई को मन की बात में पीएम मोदी ने सभी भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का भी आह्वान किया था। पीएम ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी लेने और हर घर तिरंगा डाट काम पर अपलोड करने का आग्रह किया था। (आइएएनएस)

अमृत पाल सिंह की याचिका पर पंजाब व केंद्र सरकार को नोटिस

चंडीगढ़ : नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने और इसे विस्तार देकर हिरासत अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अमृतपाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ एनएसए लगाने समेत अन्य कार्रवाई असंवैधानिक, कानून के खिलाफ और राजनीतिक असहमति के कारण की गई हैं जो दुर्भावनापूर्ण हैं। याची ने कहा कि न केवल एक वर्ष से अधिक समय तक निवारक हिरासत अधिनियम लागू किया गया बल्कि उसे पंजाब से दूर हिरासत में रखकर असामान्य व क्रूर तरीके से स्वतंत्रता छीन ली गई है। (राब्यू)

स्कूलों में गुड मार्निंग की आदत समाप्त कर जयहिंद शब्द का करें प्रयोग : त्रिखा

रोहतक : हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि स्कूलों में गुड मार्निंग कहने की आदत को समाप्त करना होगा। इसकी जगह पर जय हिंद शब्द का प्रयोग शुरू करें। प्रत्येक अध्यापक को इस पर विशेष गौर करना चाहिए। वह महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण एवं सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा शिक्षा पर किसी तरह की राजनीति करना गलता है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो सबसे पहले उन्हें चार लाख नकली विद्यार्थियों का जवाब देना चाहिए। (जासं)

चक्रधरपुर रेल दुर्घटना : 48 घंटे बाद ट्रैक पर चली ट्रेनें

झारखंड में बेपटरी मालगाड़ी से टकराकर हावड़ा-मुंबई मेल हुई थी दुर्घटनाग्रस्त, जांच शुरू

रेलवे संरक्षा आयुक्त करेंगे रेल हादसे की जांच, दुर्घटना में दो लोगों की गई थी जान

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर

झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ाबांबो रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को हावड़ा-मुंबई मेल के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। इस हादसे में मंगलवार तड़के बेपटरी हुई मालगाड़ी से टकराकर हावड़ा से मुंबई जा रही मुंबई मेल के सभी डिब्बे पलट गए थे, जिसमें दो यात्रियों की मौत हो गई थी और 47 घायल हो गए थे। दुर्घटना के 48 घंटे बाद दूसरे दिन हावड़ा- मुंबई रेल मार्ग सामान्य हो सका। बुधवार को भी मरम्मत कार्य जारी रहा। रेलवे को इस रूट की 47 ट्रेनों को रद करना पड़ा था। रेलवे ने जांच के लिए कमेटी बनाई है, जिसमें चक्रधरपुर रेलवे डीआरएम, सीनियर डीओएम, सीनियर डीईईओपी (इलेक्ट्रिक) समेत अन्य रेल अधिकारी शामिल हैं। दुर्घटना की जांच करने एक अगस्त को रेलवे संरक्षा आयुक्त मौके पर पहुंचेंगे।

इससे पहले गुरुवार को जांच कमेटी के अधिकारी चक्रधरपुर रेल मंडल के मीटिंग हाल में हादसे को लेकर संबंधित रेलकर्मियों से पूछताछ कर जानकारी लेंगे। जांच के लिए रेलवे प्रशासन रेलवे के अलग-अलग विभाग के कुल आठ रेल कर्मचारियों को जांच के दौरान उपस्थित रहने के लिए आदेश दिया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीओएम अविनाश ने संबंधित रेलकर्मियों को पूछताछ में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। रेलवे की घोषणा के अनुरूप घटना में जान गंवाने वाले दोनों यात्रियों के परिवार वालों तथा घायलों को मुआवजे की रकम उपलब्ध करा दी गई है। उल्लेखनीय है कि बीते सात महीने में पांच बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं। सभी दुर्घटनाओं में कहीं न कहीं रेलवे की लापरवाही नजर आई है। कांचनजंघा एक्सप्रेस हादसे में भी लोको पायलट को समय पर सूचना नहीं दी गई। इस हादसे में भी ऐसी ही बात सामने आ रही है।

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में बड़ाबांबू के पास दुर्घटनाग्रस्त हावड़ा-मुंबई मेल के क्षतिग्रस्त डिब्बों को क्रेन की मदद से पटरियों से उठाते हुए। प्रेट्र

बंगाल के रंगापानी में मालगाड़ी पटरी से उतरी

जासं, सिलीगुड़ी : करीब डेढ़ महीने के अंदर फिर उसी जगह पर ट्रेन दुर्घटना हुई है जिस जगह पर सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस दुर्घटना में 10 यात्रियों की मौत हो गई थी। बुधवार को बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के निकट रंगापानी में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। यह दुर्घटना तब हुई जब एक मालगाड़ी तेल टैंकरों को लेकर रंगापानी साइडिंग पर जा रही थी। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची दे ने बताया कि दो तेल टैंकर पटरी से उतर गए। यह दुर्घटना दिन में करीब 11:45 बजे हुई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बढ़ती ट्रेन दुर्घटना पर अपनी चिंता प्रकट की है।

कवच सिस्टम लगा होता तो नहीं होती दुर्घटना

कवच सिस्टम एक स्वदेशी एंटी प्रोटेक्शन सिस्टम (एपीएस) है जिसे रेल दुर्घटना रोकने को तैयार किया गया है। यदि इंजन के 100 से 200 मीटर आगे कोई बाधा आती है और ड्राइवर समय पर ब्रेक नहीं लगाता है तो कवच प्रणाली तुरंत एक्टिव हो जाता है और आपातकालीन स्थिति में खुद से ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक देती है। मौसम खराब होने पर या ठंड के समय धुंध की स्थिति में यह कवच बहुत ही कारगर है। इस कवच प्रणाली के लगने से किसी भी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है। चक्रधरपुर मंडल में आज तक ये सिस्टम लगा ही नहीं है यदि लोको में सिस्टम लगा होता तो संभवत: दुर्घटना से बचाव हो सकता था।

विस भंग होने के बाद भी जारी रह सकती है विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही

चेन्नई, आइएएनएस : मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निर्वाचित विधायकों के खिलाफ शुरू की गई विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही उस विधानसभा के भंग होने के बाद भी जारी रहती है, जिसके लिए वे चुने गए हैं। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी. कुमारप्पन की खंडपीठ ने कहा कि यदि निर्वाचित विधानसभा के कार्यकाल के पूरा होने के दौरान कार्यवाही समाप्त होने पर विधानसभा के कुछ विशेषाधिकार निरर्थक हो जाएंगे। खंडपीठ ने कहा कि सदन की संप्रभुता और गरिमा को उन लोगों के हित में महत्व दिया जाना चाहिए, जिन्होंने प्रतिनिधियों को चुना है। विशेषाधिकार हनन जैसे मुद्दों को प्रत्येक विधानसभा के विघटन के बाद खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने तत्कालीन विधान सभा सचिव के साथ-साथ समिति के अध्यक्ष द्वारा 2021 में दायर रिट अपील की अनुमति देते हुए ये टिप्पणियां कीं। इसमें एकल न्यायाधीश के 2020 के आदेश को चुनौती दी गई थी। आदेश में जुलाई 2017 में विस में गुटखा पाउच प्रदर्शित करने के लिए निवर्तमान सीएम एम.के. स्टालिन और 18 अन्य डीएमके विधायकों को कारण बताओ नोटिस को रद कर दिया गया था। न्यायाधीशों ने द्रमुक विधायकों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि 15वीं विधानसभा के दौरान शुरू की गई कार्यवाही 16वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान जारी नहीं रखी जा सकती है। 15वीं विधानसभा को मई 2021 में भंग कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश विस

नजूल भूमि के पट्टों के नवीनीकरण को उत्तर प्रदेश सरकार अंतत : राजी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ

- भारी विरोध के बीच विधानसभा में पारित हुआ उप्र नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध व उपयोग) विधेयक-2024

विधान सभा में उप्र नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध व उपयोग) विधेयक-2024 विपक्ष के कड़े विरोध व हंगामे के बीच पारित हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की मांग पर सरकार ने नजूल जमीनों के उन पट्टाधारकों के पट्टों का 30 वर्ष के लिए नवीनीकरण का भरोसा दिलाया जिनका पट्टा अभी चालू है, जो नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और जिन्होंने शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जिन्होंने नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराने के लिए रकम जमा कराई है, उन्हें भी पट्टों के नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने सदस्यों को इसके लिए नियमों के तहत प्रबंध किए जाने का भरोसा दिलाया। हालांकि इस दौरान विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए विधान सभा अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और धरने पर बैठ गए। विपक्षी 'विधेयक वापस लो व काला कानून वापस लो' के नारे लगाते रहे। संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून में नियम बनाने का अधिकार है। इसे नियम में स्पष्ट किया जाएगा। यह भी कहा, किसी गरीब को नहीं उजाड़ेंगे। नजूल भूमि पर बने कोर्ट, शैक्षणिक व मेडिकल संस्थान यथावत रहेंगे। इससे पूर्व संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों व सार्वजनिक कार्यों में नजूल भूमि का उपयोग किए जाने के लिए सरकार यह विधेयक लाई है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने वालों की जिन जमीनों को जब्त कर लिया गया था, वही नजूल भूमि है। बताया कि अब नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं मिलेगा।

एनसीआर की तर्ज पर विकसित होगा राज्य राजधानी क्षेत्र

एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) प्लानिंग बोर्ड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन संबंधी उप्र राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) व अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक-2024 बुधवार को शोर-शराबे के बीच विधान सभा में पारित हो गया। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही उप्र राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2024, उप्र नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक-2024, बोनस संदाय (उप्र संशोधन) विधेयक-2024 व कारखाना (उप्र संशोधन) विधेयक-2024 भी पारित किए गए। सात मार्च को ही एससीआर के गठन का रास्ता साफ हो गया था लेकिन अब अधिनियम बनाने के लिए सरकार ने विधेयक पारित कराया है।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफार्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

राहुल गांधी ने नहीं कही हिंदुओं पर कार्रवाई की बात

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। 23 सेकेंड की इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने धमकी दी है कि जब भाजपा सरकार हट जाएगी, तब हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई होगी।

पड़ताल: विश्वास न्यूज ने राहुल गांधी की प्रसारित क्लिप के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सबसे पहले इसके कई कीफ्रेम्स निकाले। फिर इन्हें गूगल लेंस के जरिये सर्च किया। हमें राहुल गांधी के एक्स हैंडल पर बड़ा वीडियो मिला। इसे इसी वर्ष 24 मार्च को अपलोड किया गया था। वीडियो में राहुल गांधी जांच एजेंसियों के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं, 'यदि ये इंस्टीट्यूशन अपना काम करते हैं, यदि सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो यह नहीं होता। तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जो वह यह सब कर रहे, किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी। फिर कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी दे रहा हूं। यह फिर से कभी नहीं होगा।'

निष्कर्ष : विश्वास न्यूज की पड़ताल में पता चला कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने जांच एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। हमारी जांच में प्रसारित पोस्ट फर्जी साबित हुई।

क्या हो रहा है प्रसारित

फेसबुक यूजर सत्या शुक्ला ने 27 जुलाई को प्रसारित वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, 'सुनिए खान पौत्र की हिंदुओं को चेतावनी। अच्छा किया राहुल बाबा तुने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वो इस हिंदू विरोधी-सनातन विरोधी राहुल खान से निपटने के लिए अपनी तैयारी करे। यह तो खुली धमकी दे रहा हैं। तुझे खुली चुनौती है तू करके दिखा दे।'

झूठी खबर और अफवाहों का सच जानने के लिए विश्वास न्यूज के वाट्सएप चैनल को फालो करने के लिए कोड स्कैन करें।

गिनती में ईवीएम के कुछ मत कम निकले या फिर ज्यादा

इस बार लोकसभा चुनाव में मतों की गिनती के दौरान बिहार में कोई गड़बड़झाला तो सामने नहीं आया, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट मतगणना की विसंगतियों को उजागर कर रही है। यह विसंगति सभी 40 सीटों पर रही है। हालांकि, विसंगति वाले मतों की तुलना में हार-जीत का निर्णय अधिक मतों के अंतर से हुआ है। ऐसे में इस विवाद के गहराने की आशंका नहीं के बराबर है, क्योंकि चुनाव परिणाम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर भी मतगणना की पारदर्शी व्यवस्था पर प्रश्न तो खड़ा हो ही जाता है। पटना से **विकाश चन्द्र पाण्डेय** की रिपोर्ट :

40 सीटों पर रही है विसंगति। विसंगति वाले मतों की तुलना में हार-जीत का निर्णय अधिक

बिहार के स्तर पर

21 संसदीय क्षेत्रों में पड़े कुल मतों से 5015 मत अधिक गिने गए

19 लोकसभा क्षेत्रों में पड़े कुल मतों से 9924 मत कम गिने गए

चार जून को मतगणना हुई थी और उसी शाम परिणाम भी सामने आ गया। अब चुनावी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पक्षों का विश्लेषण हो रहा तो कुछ विसंगतियां भी उजागर हो रहीं। बिहार में लोकसभा की 21 सीटों पर ईवीएम में जितने मत पड़े थे, उनसे 5015 मतों की अधिक गिनती हुई। 19 संसदीय क्षेत्रों में गिने गए मत कुल पड़े मतों से 9924 कम रहे। इस तरह कुल 40 सीटों पर 14939 मतों की विसंगति रही है। एडीआर का दावा है कि पूरे देश में पांच संसदीय क्षेत्रों (अमरेली, अत्तिंगल, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव) को छोड़कर 538 में यह विसंगति मिली है। कुल पड़े मत और गिनती के मतों में 589691 का अंतर रहा है। हालांकि, सूरत में चुनाव निर्विरोध हुआ था।

राष्ट्रीय स्तर पर

362 संसदीय क्षेत्रों में पड़े कुल मतों से 554598 मत कम गिने गए

176 संसदीय क्षेत्रों में पड़े कुल मतों से 35093 मत अधिक गिने गए

पिछली बार भी बिहार के औरंगाबाद लोस क्षेत्र में आई थी गड़बड़ी

ऐसी विसंगति पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में 140 संसदीय क्षेत्रों में मिली थी। एडीआर इस प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तब निर्वाचन आयोग ने आरोपों को निर्मूल बताते हुए तर्क दिया था कि याचिकाकर्ताओं व मीडिया ने अपने आकलन में एप पर प्रकाशित मतदान की अनुमानित संख्या को लिया था। यही कारण है कि उनके आंकड़े गिने गए वोटों की वास्तविक संख्या से मेल नहीं खाते। तब यह विसंगति बिहार के औरंगाबाद लोस क्षेत्र में पाई गई थी।

पिछली बार विसंगति औरंगाबाद में

2019 के लोकसभा चुनाव में भी 140 सीटों पर ऐसी विसंगति पाई गई थी। तब गिनती वाले मतों की संख्या ईवीएम में डाले गए मतों से अधिक थी। अंतर दो से लेकर 3811 मतों के बीच रहा। बिहार के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में 930758 वोट डाले गए थे। मतगणना में यह संख्या 939526 रही। इस तरह 8760 मतों की अधिक गिने गए। ये वोट जीत-हार के मतों के अंतर से काफी कम थे। तब भाजपा के सुशील कुमार सिंह 71325 मतों के अंतर से चुनाव में विजयी रहे थे।

संदेह का समाधान आवश्यक

महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से डाले गए सभी वोटों की गिनती क्यों नहीं की। अगर आवश्यकता पड़ती तो उन जगहों पर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की जा सकती थी, जहां जीत का अंतर बहुत कम था। इस प्रश्न के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान रंजन का कहना है कि 2019 के चुनाव के दौरान की अनियमितता और अनैतिकता को दोहराए जाने से रोकने में निर्वाचन आयोग 2024 में भी विफल रहा। इससे मतदाताओं के मन में संदेह पैदा हो

****

'पेयजल का दुरुपयोग रोकने को कानून बनाएगी बंगाल सरकार'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- विधानसभा में राज्य के पीएचईडी मंत्री ने दी जानकारी
- ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा बंगाल

पेयजल का दुरुपयोग रोकने के लिए बंगाल सरकार जल्द एक कानून बनाने जा रही है। बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण (पीएचईडी) मंत्री पुलक राय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संबंधित विधेयक (कानून) की रूपरेखा तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि विधानसभा के आगामी सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा। मंत्री के अनुसार, ऐसा कानून बनाने वाला बंगाल पहला राज्य होगा।

मंत्री ने कहा कि विभाग को कई शिकायतें मिली है कि पीने का पानी आम लोगों के घरों तक पहुंचने के बजाय दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगहों पर खेती से लेकर विभिन्न कारखानों, होटलों, रेस्तरां में इसका अवैध तरीके से उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद से ही विभाग ने पेयजल का दुरूपयोग रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार पहले ही शुरू कर दिया था। मंत्री ने कहा कि हम राज्य के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना चाहते हैं। कृषि कार्य हेतु सिंचाई विभाग है। लघु सिंचाई विभाग हैं। हमारा विभाग आम लोगों तक पेयजल पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित है। हम चाहते हैं कि पीने के पानी का इस्तेमाल केवल पीने के लिए ही किया जा सके। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि पेयजल का दुरूपयोग रोकने के लिए हम कठोर कदम नहीं उठाते हैं तो पीने के पानी की उपलब्धता मुश्किल हो जाएगी।

32 हजार 403 करोड़ रुपये कथित जीएसटी चोरी को लेकर देश की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कंपनी इन्फोसिस को कर्नाटक राज्य जीएसटी प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। यह मामला जुलाई, 2017 से मार्च, 2022 के बीच का है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 1 अगस्त, 2024

आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार को लेकर हिमाचल में 17 स्थानों पर ईडी की दबिश

दो कांग्रेस नेताओं के अस्पतालों और घरों में भी पहुंचे अधिकारी

जागरण टीम, धर्मशाला

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) में भ्रष्टाचार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऊना, मंडी और कुल्लू जिलों में सात निजी अस्पतालों व उनके संचालकों के घरों और अन्य स्थानों समेत कुल 17 ठिकानों पर दबिश दी। कांगड़ा के जिन दो अस्पतालों में ईडी की टीम पहुंची, उनमें एक नगरोटा बगवां के कांग्रेस विधायक व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली और दूसरा हिमाचल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा का है। दोनों नेताओं के घरों में भी ईडी ने जांच की है।

ईडी के अधिकारी सबसे पहले ऊना के निजी अस्पताल के संचालक के घर, अस्पताल समेत तीन स्थानों पर पहुंचे। कांगड़ा में चार अस्पतालों, संचालकों के घरों सहित नौ स्थानों पर दबिश दी गई। मंडी-कुल्लू में पांच स्थानों पर दस्तावेज खंगाले गए। दबिश देर रात तक जारी थी। कुछ अस्पताल प्रबंधकों के मोबाइल फोन ईडी की टीम ने जब्त कर लिए, जबकि कई प्रबंधकों ने अपने फोन स्विच आफ कर लिए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने कांगड़ा में कांग्रेस नेताओं के दोनों अस्पतालों से आयुष्मान भारत व हिमकेयर योजना का रिकार्ड भी मांगा है। जिस समय टीम ने दबिश दी, उस वक्त आरएस बाली घर से बाहर थे। वह स्वजन के साथ दिल्ली गए थे। जबकि, डा. राजेश शर्मा घर पर ही थे। बता दें कि आयुष्मान भारत और प्रदेश की हिमकेयर योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के निश्शुल्क उपचार का प्रविधान है। आरोपों के मुताबिक इन अस्पतालों में आवश्यकता से अधिक बिलिंग की गई। फर्जी कार्डों से मेडिकल बिल बनाए गए और सरकारी खजाने में सेंध लगाई गई।

कैग की आडिट रिपोर्ट बनी कार्रवाई का आधार : आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ईडी की कार्रवाई का आधार बनी है। केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 23 दिसंबर 2018 को देश में योजना लागू की थी। इसके तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। जो लोग कार्ड से वंचित रह गए थे, प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार उनके लिए हिमकेयर योजना लेकर आई थी। आयुष्मान योजना का आडिट करने के बाद कैग ने 700 से 800 करोड़ रुपये का गड़बड़झाला होने की बात कही थी। ईडी ने जिन निजी अस्पतालों में दबिश दी, वहां बड़े पैमाने पर फर्जी आयुष्मान कार्ड के आधार पर फर्जी मरीजों के इलाज की शिकायतें हैं। मरीजों को गंभीर बीमारी से पीड़ित बता उनका लंबा इलाज व सर्जरी होना दिखाया गया। जांच में फर्जीवाड़े के करीब 373 मामले सामने आए, जिसके बाद सरकार ने हिमाचल में 8,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड रद भी कर दिए थे।

- उनके अस्पतालों से आयुष्मान भारत व हिमकेयर योजना का रिकार्ड तलब

ससस

यहां दी दबिश

कांगड़ा: श्रीबालाजी अस्पताल कांगड़ा, हिमाचल हेल्थ केयर कंपनी द्वारा संचालित फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा (फोर्टिस अस्पताल की फ्रेंचाइजी), सिटी अस्पताल मटौर व सूद नर्सिंग होम नगरोटा बगवां।

ऊना : श्री बांके बिहारी अस्पताल। इनके संचालक वजिंद्र सिंह के आवास व नंगल स्थित पूर्व महिला कर्मचारी के घर पर टीम ने दबिश दी।

मंडी-कुल्लू: नीलकंठ अस्पताल मंडी व हरिहर अस्पताल कुल्लू। इन अस्पतालों के संचालकों के आवास पर भी रिकार्ड खंगाला गया।

मैं 29 जुलाई को परिवार सहित बेटे रियान की छुट्टियों के दौरान दो दिन के लिए बाहर आया था। अभी मुझे पता चला कि मेरे निवास पर कुछ अधिकारी आए हैं। मैं अपने परिवार सहित वापस आ रहा हूं। हम जांच एजेंसियों की इज्जत करते हैं और उन्हें पूरा सहयोग देंगे। मेरी नगरोटा बगवां परिवार से व प्रदेश में जो भी हमसे जुड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप एक पालिटिकल जिंदगी जीते हैं तो कई बार इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है।

– आरएस बाली, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा के संचालक (दिन में इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की गई उनकी पोस्ट)

ईडी ने तेल कारोबारियों की 814 करोड़ की प्रापर्टी को किया अटैच

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

ईडी की प्रयागराज टीम ने वाराणसी के प्रमुख तेल कारोबारी सत्य नारायण झुनझुनवाला व आदर्श झुनझुनवाला की 814 करोड़ रुपये की प्रापर्टी को अटैच किया है। ईडी ने वाराणसी और चंदौली, बिहार के रोहतास, नई दिल्ली के पालम और महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थित 521 एकड़ भूमि को कुर्क किया है।

सीबीआइ की लखनऊ टीम ने जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इसी केस के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी ने जांच को आगे बढ़ाते हुए 21 जून, 2024 को जेवीएल ग्रुप आफ कंपनीज, सत्य नारायण झुनझुनवाला, उनके परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों के 12 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान फंड के डायवर्जन से संबंधित दस्तावेज और रिकार्ड बरामद हुए थे। जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और बंगाल में व्यवसाय करने वाली जेवीएल विभिन्न खाद्य तेलों के विनिर्माण (मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया) और व्यापार में शामिल थी। कंपनी अपनी विदेशी सहायक कंपनी जेवीएल ओवरसीज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से सिंगापुर, मलेशिया से कच्चे तेल का आयात करती थी। जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हेरफेर कर और बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए वित्तीय विवरणों से बैंकों से लोन का लाभ उठाया। साथ ही फंड को डायवर्ट किया। वहीं, सत्यनारायण झुनझुनवाला का कहना है कि 'ईडी द्वारा 814 करोड़ की प्रापर्टी अटैच किए जाने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। न ही कोई मुझे नोटिस मिला है।'

- उप्र, बिहार, नई दिल्ली और महाराष्ट्र में 521 एकड़ भूमि को किया कुर्क

कागजी कंपनी खोल कठपुतली निदेशक बनाए

ईडी का कहना है कि सत्य नारायण झुनझुनवाला ने जेवीएल एग्रो की समूह कंपनियों के रूप में तमाम कागजी संस्थाओं का अधिग्रहण किया और खोला। इसके बाद उसमें कठपुतली निदेशक बनाए गए, जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और उनके कर्मचारी हैं। इनका उद्देश्य जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फंड को ऐसी कागजी संस्थाओं के माध्यम से डायवर्ट करना है। झुनझुनवाला और उनके सहयोगियों की कारस्तानी से बैंक आफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 1992 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ।

राशन आवंटन घोटाला

बंगाल के पूर्व मंत्री के करीबी के घर से छापे में मिले 20 लाख रुपये

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : ईडी की टीम ने बंगाल के राशन आवंटन घोटाले में छापेमारी के दौरान जेल में बंद पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के करीबी चावल मिल मालिक अब्दुल बारिक बिस्वास के कोलकाता स्थित फ्लैट से 20 लाख रुपये बरामद किए हैं।

- केंद्रीय एजेंसी ने कारोबारी समेत दो टीएमसी नेताओं को जारी किया समन

टीम ने मंगलवार को कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले के विभिन्न हिस्सों में कुल 10 स्थानों पर छापेमारी की थी। बता दें कि राशन आवंटन घोटाले में करीब एक दशक तक नियमों को ताक पर रखकर भारी मात्रा में राशन सामग्रियां निजी कंपनियों को आपूर्ति की गई थी, इन कंपनियों ने राशन को ऊंची कीमत पर खुले बाजार में बेचा था।

उल्लेखनीय है कि ईडी अधिकारियों ने कल बारिक बिस्वास के घर, चावल मिल और कार्यालय पर तलाशी अभियान चलाया था। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ने टीएमसी नेता मुकुल रहमान के घर पर भी छापेमारी की थी। जांच टीम ने तृणमूल नेता कैसर अहमद के भाई जहांगीर आलम के घर पर भी तलाशी ली थी।

नलिनी चिदंबरम के खिलाफ ईडी की पूरक चार्जशीट तीसरी बार अस्वीकार

सारधा चिटफंड मामला

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

सारधा चिटफंड मामले में वकील और आयकर सलाहकार नलिनी चिदबंरम के खिलाफ ईडी की ओर से पेश की गई तीसरी पूरक चार्जशीट को कोलकाता की सीबीआइ की विशेष अदालत ने स्वीकार नहीं किया। न्यायाधीश प्रशांत कुमार मुखर्जी ने कहा, नलिनी और सारधा समूह के मालिक सुदीप्त सेन के बीच पीएमएलए धारा के तहत कोई अवैध वित्तीय लेनदेन नहीं हुआ था। इसलिए यह पूरक चार्जशीट स्वीकार्य नहीं है।

मालूम हो कि वर्ष 2013 में राज्य का सबसे बड़ा सारधा चिटफंड घोटाला सामने आया था। समूह ने बंगाल, असम और ओडिशा में हजारों निवेशकों से आकर्षक रिटर्न का प्रस्ताव देकर लगभग तीन हजार करोड़ रुपये जुटाए थे। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ व ईडी इस घोटाले की जांच कर रही है।

नलिनी चिदंबरम।

विशेष अदालत ने कहा, नलिनी व सारधा समूह के मालिक के बीच अवैध वित्तीय लेनदेन नहीं हुआ था

बता दें कि यह तीसरी बार है जब विशेष अदालत ने सारधा घोटाले में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी के खिलाफ पूरक चार्जशीट को खारिज किया है। इसके पहले कोर्ट ने तकनीकी प्रश्न उठाते हुए पूरक चार्जशीट को स्वीकारने से मना कर दिया था। साथ ही ईडी से पूछा था कि 11 साल बाद तीसरी पूरक चार्जशीट क्यों पेश की गई।

केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि नलिनी को सुदीप्त सेन से 1.5 करोड़ रुपये मिले थे। हालांकि नलिनी का दावा है कि उन्हें कानूनी परामर्श शुल्क के तौर पर यह रकम मिली थी, पर वह इसके लिए कोई सहायक दस्तावेज पेश नहीं कर सकी थीं।

सियाचिन के योद्धाओं के बीच पहुंचे कोर कमांडर ने जाने सुरक्षा हालात

राज्य ब्यूरो, जागरण • जम्मू

लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने बुधवार को सियाचिन का दौरा कर क्षेत्र के सुरक्षा हालात जाने। कोर कमांडर ने फारमेशन कमांडर से मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों व उनका सामना करने के लिए सेना के प्रबंधों के बारे में बातचीत की और सियाचिन के योद्धाओं से मिलकर उनका मनोबल भी बढ़ाया। सियाचिन ब्रिगेड की अग्रिम चौकियों के दौरे के दौरान कोर कमांडर के साथ से कई वरिष्ठ अधिकारी भी रहे।

हितेश भल्ला ने एक जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली से फायर एंड फ्यूरी कोर के जीओसी का पदभार संभाला था। कोर की कमान संभालने के बाद वह लगातार पाकिस्तान से लगते भारतीय इलाकों की सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सियाचिन के कठिन हालात में देश सेवा कर रहे जवानों की सराहना करते हुए कहा, कड़ी सतर्कता से दुश्मन के हर षड्यंत्र को नाकाम बनाने का अभियान जारी रखें। उन्होंने सैनिकों को सम्मानित भी किया। कोर कमांडर ने इससे पहले कारगिल में दो बार अग्रिम इलाकों का दौरा कर नियंत्रण रेखा के हालात के बारे में जानकारी ली थी।

लद्दाख में लगातार मजबूत हो रही सेना : इस समय लद्दाख में भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत हो रही है। पीएम मोदी ने भी 26 जुलाई को कारगिल दौरे के दौरान सिंकुन ला टनल के निर्माण का शुभारंभ किया था। इस टनल के बनने के बाद हिमाचल प्रदेश की ओर से सेना के साजो सामान को जल्द लद्दाख के अग्रिम क्षेत्रों तक पहुंचाना संभव होगा। इस समय एक ओर जहां लद्दाख के अग्रिम इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में काम हो रहा है, वहीं सेना की आपरेशनल तैयारियां भी जोरों पर हैं। सेना आधुनिक हथियार, संचार उपकरणों को शामिल करने के साथ सैनिकों की सुविधाओं में भी वृद्धि कर रही है।

- लेफ्टिनेंट जनरल भल्ला ने सैनिकों का बढ़ाया मनोबल, प्रबंधों को परखा
- दुश्मन के हर षड्यंत्र को विफल करने के लिए तैयार रहने का दिया निर्देश

लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए। सौ : सेना

डूंगरपुर प्रकरण के एक और मुकदमे में आजम खां बरी

जागरण संवाददाता, रामपुर

डूंगरपुर प्रकरण के एक मुकदमे में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां सहित सभी छह लोगों को बरी कर दिया है। सभी पर छह दिसंबर, 2016 को घर में घुसकर दंपती से लूट, छेड़छाड़ और जानलेवा हमला करने का आरोप था। राहत पाने वालों में तत्कालीन सीओ आले हसन (अब सेवानिवृत्त) और ठेकेदार बरकत अली भी शामिल हैं। ये दोनों रामपुर और आजम खां सीतापुर की जेल में हैं। बुधवार को तीनों की वीडियो कान्फ्रेंस से पेशी हुई। इससे पूर्व डूंगरपुर प्रकरण के चार मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो में आजम खां को सजा हुई है और दो में बरी किया गया है।

उत्तर प्रदेश में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में 2016 में सपा सरकार में गरीबों के लिए आसरा आवास बनवाए गए थे। इसके लिए कुछ मकानों को सरकारी जमीन पर बताकर ध्वस्त कर दिया गया था। बेघर 12 लोगों ने 2019 में भाजपा सरकार में अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए। आरोप था कि आजम खां के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने उनके घरों को जबरन खाली कराया था। उनका सामान लूट लिया और मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया। मुकदमों में आजम खां पहले नामजद नहीं थे। दूसरे आरोपितों की गिरफ्तारी और उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने आजम खां के खिलाफ भी आरोप-पत्र दायर किया। बुधवार को जिस मुकदमे में फैसला आया, वह इदरीश ने दर्ज कराया था। उन्होंने परिवार की महिलाओं से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था।

आजम खां। फाइल

बेईमानी से दर्शकों और बीसीसीआइ से धन हड़पने के लिए रचा गया षडयंत्र : कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पटियाला हाउस कोर्ट ने वर्ष 2000 में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच हुए मैच फिक्सिंग मामले में चार आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने लंदन के बुकी संजीव चावला, दिल्ली के बुकी राजेश कालरा व सुनील दारा और टी-सीरीज के सह मालिक किशन कुमार के खिलाफ आइपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (षड्यंत्र) के तहत आरोप तय किए हैं।

एडिशनल चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट नेहा प्रिया ने कहा कि आरोपितों ने 16 फरवरी से 20 मार्च 2000 तक चले दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दौरान दर्शकों और बीसीसीआइ से धोखाधड़ी और बेईमानी से धन हड़पने के लिए आपराधिक षडयंत्र रचा।

अदालत ने मैच का टिकट खरीदने वाले दर्शक शिवदासन पीएन, शरथ रामाचंद्रन, नरेश भाई, पुरोहित शाहंद और विवेक रिषी को समन भेजकर गवाही के लिए बुलाया है।

अदालत ने कहा कि आरोपितों ने दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन कप्तान हैंसी क्रोनिए के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। आरोपितों ने दर्शकों को धोखा देकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोचीन, नागपुर, जमशेदपुर, फरीदाबाद, बड़ौदा और नागपुर में आयोजित फिक्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही आरोपितों ने बीसीसीआइ को फिक्स्ड मैच का आयोजन करने के साथ ही उसके लिए गारंटी राशि का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया था। आरोपितों ने मामले में कोर्ट के समक्ष ट्रायल का दावा किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

- मैच फिक्सिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप तय
- चार के खिलाफ चलेगा धोखाधड़ी व षडयंत्र रचने का केस

ये हैं आरोप

संजीव चावला पूरे मामले का मास्टमाइंड है। उसने मैचों के परिणाम में हेरफेर करने, अन्य टीम के खिलाड़ियों को शामिल करने, क्रोनिए व अन्य खिलाड़ियों का भुगतान तय करके मामले में सबसे सक्रिय भूमिका निभाई। संजीव क्रोनिए व अन्य आरोपितों के बीच अहम कड़ी रहा।

- राजेश कालरा ने अपने नाम से लिया सिमकार्ड क्रोनिए को दिया था। किंग्स कमीशन ने भी यही बात कही थी।
- सुनील दारा उर्फ बिट्टू ने सट्टेबाजी व मैच फिक्सिंग पर संजीव चावला से बात की थी। क्रोनिए को कितना पैसा देना चाहिए और वो लोग स्वयं क्या कमाएंगे, इस बारे में भी बात की थी।
- किशन कुमार ने अपने क्रेडिट कार्ड से 20 मार्च, 2000 को मुंबई के होटल ताज में संजीव के लिए कमरा बुक किया था। वहीं संजीव व क्रोनिए ने मैच फिक्स की साजिश रची थी।

'तरंग शक्ति' अभ्यास में 30 देशों की वायु सेना दिखाएगी अपनी ताकत

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय वायु सेना पहली बार ऐसा हवाई अभ्यास कराने जा रही है, जिसमें भारत समेत 30 देशों की वायु सेना एक साथ आसमान में ताकत दिखाएगी। लड़ाकू विमानों के साथ सेना के जांबाज सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान के सुलूर में छह अगस्त से भारतीय वायु सेना तरंग शक्ति 24 हवाई अभ्यास का आयोजन करेगी।

वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'तरंग शक्ति' अभ्यास का पहला चरण 6-14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में और दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए 51 देशों को आमंत्रित किया गया था। करीब 30 देश इसमें भाग लेंगे। वायु सेना के एलसीए तेजस, मिराज 2000 व राफेल मेगा अभ्यास में हिस्सा लेंगे। वायु सेना के वाइस चीफ एयर मार्शल ए पी सिंह ने कहा, यह अभ्यास भारत की रक्षा शक्ति को प्रदर्शित करेगा और अपनी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। फ्रांस के राफेल, जर्मनी के टाइफून, आस्ट्रेलिया के एफ-18 विमान अभ्यास में भाग लेंगे।

बिहार में पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंचे नर्सरी के बच्चे से चली गोली, एक छात्र घायल

जागरण संवाददाता, त्रिवेणीगंज (सुपौल)

बिहार के सुपौल जिले में सेंट जान बोर्डिंग स्कूल में बुधवार को नर्सरी में पढ़ने वाला पांच वर्षीय बच्चा अपने बैग में लोडेड पिस्तौल लेकर पहुंच गया। सुबह नौ बजे स्कूल परिसर में प्रार्थना के लिए सभी बच्चे इकट्ठा हो रहे थे, इसी दौरान बच्चे ने बैग से पिस्तौल निकाली। वह इसे साथियों को दिखा ही रहा था कि पिस्तौल से गोली चल गई, जो पास ही खड़े तीसरी कक्षा के 11 वर्षीय छात्र के बायें हाथ में जा लगी। स्कूल प्रबंधन ने घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। घायल छात्र के पिता ने स्कूल संचालक, स्टाफ, स्कूल भवन के मालिक एवं नर्सरी के बच्चे के पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपितों पर बच्चे की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को बुलाया, पर पुलिस को सूचना नहीं दी। स्कूल में तोड़फोड़ होने की सूचना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देने पर पुलिस पहुंची।

- सुपौल जिले की घटना, घायल के पिता ने हत्या की साजिश का केस दर्ज कराया
- आरोपित बच्चा पुलिस की देखरेख में, पिता पिस्तौल लेकर फरार

पापा ने चोर को मारने के लिए रखी थी पिस्तौल

नर्सरी का बच्चा भी फायरिंग की आवाज सुनकर डर गया। सूत्रों के अनुसार, घटना के बाद पिस्तौल की बाबत पूछने पर बच्चे ने कहा, यह मेरे पापा ने चोर को मारने के लिए रखी थी। मैं पुलिस बनना चाहता हूं, इसलिए अपने दोस्तों को इसे दिखाने स्कूल ले आया। वहीं, पुलिस को यह भी अंदेशा है कि शायद बच्चे को पता नहीं था कि पिस्तौल असली है या नकली। वह इसे खेलने की चीज समझ रहा था। दोस्तों को दिखाने के दौरान अचानक पिस्तौल से गोली चल गई।

पिस्तौल। फाइल

आरोपित छात्र पुलिस सुरक्षा में है जबकि उसका पिता फरार है। स्कूल प्रशासन के अनुसार, घटना के बाद दोनों बच्चों के स्वजन को बुलाया गया था और उनसे बात हो रही थी। पिस्तौल पास ही टेबल पर रखी थी। इसी दौरान नर्सरी के छात्र का पिता पिस्तौल लेकर भाग गया। भागने के क्रम में पिस्तौल की मैगजीन गिर गई, जिसे घायल बच्चे के स्वजन ने उठा लिया और पुलिस को दे दिया।

पुलिस अधीक्षक शैशव यादव ने कहा, जांच में पता चला है कि नर्सरी का छात्र स्कूल बैग में पिस्तौल लाया गया जिससे गोली चली। घर में बच्चे ने किस नीयत से बैग में पिस्तौल रखी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। नर्सरी के बच्चे को मां के साथ कर दिया गया है। उसे सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। छात्र के पिता की तलाश जारी है। वह पांच माह पूर्व तक उसी विद्यालय में सुरक्षा गार्ड था।

हिंदुओं के नाम से फर्जीवाड़ा

मप्र में 56 मदरसों ने लिया 125 करोड़ रु. का अनुदान

सुरेश वैष्णव, नईदुनिया

मदरसों में 9132 बच्चों के नाम दर्ज, जिसमें से 650 हिंदू बच्चों के नाम, जिनके नाम सामने आए हैं, उनमें कोई विदेश में है तो, कोई बड़े पद पर, मृतकों के नाम भी दर्ज कर लिए

श्योपुर: मप्र के श्योपुर जिले में मंगलवार को जिला शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पर मदरसा बोर्ड द्वारा जिन 56 मदरसों की मान्यता रद की गई, वहां हिंदू बच्चों के नाम विद्यार्थी के रूप में दर्ज कर वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक सात वर्षों में 125 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान लिया गया। मदरसा संचालकों ने शहर के गणमान्य नागरिकों, व्यापारी वर्ग और जनप्रतिनिधियों के बच्चों के नाम भी विद्यार्थी के रूप में दर्ज कर लिए थे। 56 मदरसों में 9132 में 650 हिंदू बच्चों के नाम दर्ज पाए गए हैं।

जिन बच्चों के नाम सामने आए हैं, उनमें कोई विदेश में रह रहा है तो कोई बड़े पद पर नौकरी कर रहा है, मृतकों के नाम दर्ज कर भी सरकारी अनुदान लिया गया। जिला शिक्षा अधीक्षक रवींद्र सिंह तोमर का कहना है कि फर्जीवाड़ा कर धन हड़पने की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। जो भी निर्देश आएंगे, उसके आधार पर मदरसा संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

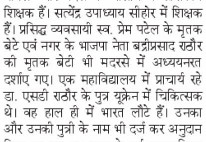
मध्य प्रदेश के एक मदरसे में पढ़ते छात्र। फाइल

शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार श्योपुर के डा. देवेंद्र शर्मा के दो पुत्रों व एक पुत्री को भी मदरसे में अध्ययनरत दर्शाकर उनके नाम पर अनुदान लिया जा रहा था, जबकि इनके एक पुत्र बैंक आफ बड़ौदा की ग्वालियर शाखा में अधिकारी हैं। जिला पंचायत कार्यालय में खाद्यान्न प्रभारी का कार्य देख रहे प्रमोद गुप्ता के दोनों बच्चों को ही नहीं, भाजपा के युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सौरभ भार्गव का नाम भी मदरसे में बतौर विद्यार्थी दर्ज किया गया है। इसी तरह मदरसे में छात्र दर्शाए गए गौरव गोयल उत्तर प्रदेश के जालौन में शासकीय शिक्षक हैं। सत्येंद्र उपाध्याय सीहोर में शिक्षक हैं। प्रसिद्ध व्यवसायी स्व. प्रेम पटेल के मृतक बेटे एवं नगर के भाजपा नेता बद्रीप्रसाद राठौर की मृतक बेटी भी मदरसे में अध्ययनरत दर्शाए गए। एक महाविद्यालय में प्राचार्य रहे डा. एसडी राठौर के पुत्र यूक्रेन में चिकित्सक थे। वह हाल ही में भारत लौटे हैं। उनका और उनकी पुत्री के नाम भी दर्ज कर अनुदान लिया जा रहा था। शहर के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और सर्राफा कारोबारी के स्वजन के नाम भी छात्र के रूप में दर्ज किए गए हैं।

शहर काजी अतीकउल्लाह कुरैशी की पोती मदरसे में अध्ययनरत दर्शाई गई, जबकि वह विदेश जाने की तैयारी में थी, पर प्रसूता होने के चलते वह अभी भारत में ही निवासरत है। एक ही गांव में एक ही नाम से कई मदरसे अलग-अलग पतों पर संचालित पाए गए। इन मदरसों में 100 से 350 तक बच्चों के नाम दर्ज किए गए हैं।

****

मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वालों पर हो एफआइआर : कोर्ट

पाटन, प्रेट्र: गुजरात के पाटन जिले की एक अदालत ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वाले एक समूह के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एच पी जोशी ने बलिसाना थाने के उपनिरीक्षक को याचिकाकर्ता मकबूल हुसैन शेख की शिकायत पर केस दर्ज कर समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि बलिसाना में कुछ लोगों ने 16 जुलाई, 2023 को सांप्रदायिक दंगे के बाद स्थानीय लोगों को मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए उकसाया था। इस कदम से क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों के व्यवसाय व आजीविका प्रभावित हुई है। कुछ को तो यह स्थान छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपित समूह पर समूहों के बीच दुश्मनी की भावना पैदा करने या बढ़ावा देने का केस दर्ज किया जाए।

आगरा एयरपोर्ट व कैंट रेलवे स्टेशन को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी

जागरण संवाददाता, आगरा

डीजीपी कंट्रोल रूम लखनऊ को मंगलवार शाम धमकी भरा मेल मिला। इसमें आगरा के खेरिया एयरपोर्ट और कैंट रेलवे स्टेशन को 50 किलोग्राम आरडीएक्स से तीन अगस्त को उड़ाने की धमकी दी गई। साइबर सेल की मदद से ई-मेल भेजने वाले को खोज निकाला गया। आरोपित धौलपुर, राजस्थान का रहने वाला 10वीं कक्षा का छात्र निकला। उसने फर्जी आइडी बनाकर धमकी भरा मेल भेजा था। पुलिस आरोपित को बाल कल्याण समिति के सामने गुरुवार को पेश करेगी।

ईमेल में लिखा था तीन अगस्त को खेरिया एयरपोर्ट में 50 किलोग्राम आरडीएक्स रखने वाला हूं। उसके बाद आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर। किसी पुलिस वाले में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज करता हूं। सेव कर सकते हो तो करके दिखाओ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। डीजीपी कंट्रोल रूम ने आगरा पुलिस आयुक्त को सूचना दी। इसके बाद शाहगंज थाने में बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया एयरपोर्ट और स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही बम निरोधक दस्ते से चेकिंग कराई गई। इस बीच साइबर सेल ने यह पता लगा लिया कि ईमेल भेजने के लिए किस कनेक्शन का प्रयोग किया गया है। पता चलने के बाद पुलिस धौलपुर पहुंची। आरोपित सामान्य परिवार से है। पिता पैकिंग फैक्ट्री में काम करते हैं। छात्र हिंदू है, जबकि उसने मुस्लिम नाम से फर्जी आइडी बनाई थी।

- डीजीपी कंट्रोल रूम को मिले ईमेल में पुलिस और मुख्यमंत्री को दी चुनौती

1000 लोगों को अब तक बचाया है वायनाड के आपदा प्रभावित इलाके से सेना के जवानों ने। जवान भारी इंजीनियरिंग उपकरण तथा खोजी श्वान दलों की मदद से मलबे में दबे लोगों को तलाशने में जुटे हैं।

वायनाड में मलबे में शव तलाश रहे बचाव कर्मी, अब तब 167 के शव मिले

मंगलवार को भारी वर्षा के बाद भूस्खलन से चार गांव हो गए थे पूरी तरह तबाह

191 लोग अभी भी लापता, 200 से ज्यादा घायल, अब तक 1,592 लोगों को बचाया गया

वायनाड, प्रेट्र : केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 167 हो गई, जबकि 191 लोग अभी भी लापता हैं। 200 घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अभी मृतक संख्या और बढ़ने की आशंका है। सेना सहित बचाव दलों ने तलाशी अभियान के दूसरे दिन बुधवार को मलबे में फंसे लोगों को खोजने के प्रयास और तेज किए। इस दौरान कई क्षतिग्रस्त मकानों के मलबे में दबे शवों को उसी अवस्था में बाहर निकाला गया, जिस अवस्था में वह दुर्घटना के वक्त घर में थे। इनमें कुछ शव बैठे और लेटी हुई अवस्था में थे। भारी बारिश के कारण मंगलवार तड़के बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन में वायनाड के चार गांव मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टमाला और नूलपुझा पूरी तरह तबाह हो गए थे।

राहत और बचाव टीमें मलबे को खोदकर और मिट्टी में दबे घरों के अवशेषों को तोड़कर जीवित बचे लोगों की तलाश कर रही हैं। बचावकर्मी अभी भी कई अंदरुनी इलाकों तक नहीं पहुंच पाए हैं जिनका संपर्क बुधवार सुबह पूरी तरह से टूट गया था। चैनलों पर प्रसारित दृश्यों में देखा जा सकता है कि मुंडक्कई में एक स्थान पर सेना के जवान कीचड़ में डूबे एक घर की टिन की छप्पर तोड़ रहे हैं। वे रस्सियों का उपयोग करके अंदर पहुंच कर वहां दबे शवों को निकाल रहे थे। ऐसे ही एक मकान में अंदर गए एक स्थानीय व्यक्ति के.बाबू ने बताया कि उसने कुर्सियों पर बैठे और चारपाई पर लेटी हुई मुद्राओं में मिट्टी में दबे शव देखे। आपदा के वक्त मुंडक्कई में बच्चों के अलावा 860 से अधिक लोग मौजूद थे। इसके अलावा प्रवासी मजदूर और पर्यटक भी थे। बाबू ने बताया- 'कई स्थानों पर लोगों को मलबे में जीवित फंसे देखा और वे मदद को तरस रहे थे। शवों में बच्चों को एक-दूसरे से कसकर गले लगे हुए देखा गया। महिलाओं के शव पेड़ के विशाल तनों के बीच पाए गए।'

केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा- ''वायनाड में बचाव अभियान जोरों पर चल रहा है। हमारी धरती ने पहले कभी ऐसे दर्दनाक दृश्य नहीं देखे।'' इससे पहले दिन में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आपदा में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। विजयन ने कहा, जिले के मुंडक्कई और चूरलमाला क्षेत्र में दृश्य विनाशकारी हैं। ये दोनों इलाके पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। बचाव अभियान के तहत अब तक 1,592 लोगों को बचाया गया। वायनाड जिले में 82 राहत शिविरों में 8,017 लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा, नदी में बह रहे शवों को खोजने के लिए अभियान चल रहा है। ये शव मलप्पुरम जिले में पहुंच रहे हैं।

सेना व अन्य बचाव दल युद्ध स्तर पर चलाए हुए हैं राहत एवं बचाव कार्य, बचाव दलों ने कुछ शवों को बैठे और लेटी हुई अवस्थाओं में मलबे से निकाला बाहर

वायनाड में हुए भूस्खलन के दूसरे दिन बुधवार को मशीनों से मलबे को हटाते राहत एवं बचाव दल के कर्मी। एपी

सेना ने दिल्ली से भेजे बेली ब्रिज से लेकर विशेष खोजी कुत्ते दस्ते

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सेना का विशेष फोकस भूस्खलन में दबे लोगों की तलाश कर उनकी जिंदगी बचाना है। इसके लिए बुधवार को दिल्ली से सेना के विशेष खोजी कुत्ते दस्ते को भेजा गया। साथ ही मुश्किल इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए तीन बेली ब्रिज विशेष विमानों से वायनाड पहुंचाए। 500 सैनिक, अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ राहत और बचाव में जुटे हैं। सेना ने 1000 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला है। कोझीकोड में ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन के साथ कर्नाटक व केरल उप क्षेत्र के जनरल आफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वीटी मैथ्यू की अध्यक्षता में कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। वायुसेना के हेलीकाप्टरों ने खाद्य पदार्थ व अन्य राहत सामग्री पहुंचाने के लिए बुधवार को कई उड़ानें भरीं। वहीं तिरुअनंतपुरम, सुलूर में कई विमान स्टैंडबाय पर हैं।

पेड़ों की कटाई और मूसलाधार बारिश से भरभराया पहाड़

जेएनएन, नई दिल्ली

- देश में भूस्खलन प्रोन जिलों में वायनाड का 13वां स्थान
- 1950 से 2018 के बीच जिले में 62 प्रतिशत जंगल साफ
- 140 मिमी बारिश के बाद चट्टानी पहाड़ों से बही मिट्टी

केरल में प्राकृतिक आपदा आने के कारणों में उसके पर्वतीय इलाके के पर्यावरण से छेड़छाड़ होना प्रमुख है। अव्वल तो वायनाड और आसपास के जिले अत्यधिक भूस्खलन वाले जोन में आते हैं। उसमें जिन इलाकों में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है, शहरीकरण और पर्यटन क्षेत्र के चलते वहां के जंगल ही साफ किए जा चुके हैं। उस पर से तीव्रतम मूसलधार बारिश ने पहाड़ी को कई जगहों से बेहद कमजोर कर दिया।

वर्ष 2021 के स्प्रिंगर के प्रकाशित शोध पत्र में बताया गया है कि भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र वेस्टर्न घाट में स्थित केरल के पर्वतीय क्षेत्र भूस्खलन के हाटस्पाट हैं, जहां करीब हर साल ही भूस्खलन होते हैं पर इस बार की त्रासदी जैसी पहले कभी नहीं हुई। वेस्टर्न घाट में स्थित केरल के इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टयम, वायनाड, कोझिकोड और मल्लापुरम जिले सबसे संवेदनशील हैं। इसरो की ओर से गत वर्ष जारी 'लैंडस्लाइड एटलस' के अनुसार, भारत के तीस सबसे अधिक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में दस केरल में हैं। देश के इन 30 जिलों में वायनाड का स्थान 13वां है। केरल के जिन 59 प्रतिशत क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, वह खेती वाले इलाके हैं। वर्ष 1950 से 2018 के बीच वायनाड के 62 प्रतिशत जंगल साफ हो गए हैं। करीब 1800 प्रतिशत हरियाली का सफाया हुआ है।

इसके अलावा, वायनाड में सोमवार व मंगलवार की दरमियानी रात 140 मिमी बरसात हुई। कुछ क्षेत्रों में तो 300 मिमी से अधिक वर्षा हुई, जिसने सबसे भीषण आपदा से रूबरू कराया। केरल विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के प्रोफेसर केएस सजिनकुमार ने कहा, इस क्षेत्र में पहाड़ पर दो तरह की परतें हैं। सख्त चट्टानों पर मिट्टी की परत चढ़ी रहती है, पर भारी वर्षा से मिट्टी में नमी भर जाती है और पानी से फूलकर चट्टानों से फिसलना और धंसना शुरू हो जाता है।

चेताते रहे विशेषज्ञ, हादसे की आशंका पर आंखें मूंदे रही केरल सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वायनाड में भूस्खलन से हुई जान-माल की हानि के बाद चिंतन इस पर भी शुरू हो गया है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विभिन्न दलों के सुझाव आ रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा के पूर्वानुमान की व्यवस्थाएं अधिक चाक-चौबंद हों।

- केरल में भूस्खलन के संबंध में दो विशेषज्ञ पैनलों की रिपोर्ट 10 साल से ठंडे बस्ते में

बुधवार को लोस व रास में भी सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा की। लोस में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या इतना ही कह पाए थे कि केरल में गत पांच वर्ष में 350 से अधिक लोगों की जान भूस्खलन के कारण जा चुकी है। यह आपदाएं वेस्टर्न घाट क्षेत्र में अनियमित व्यावसायिक गतिविधियों की वजह से आईं। इस संबंध में कई रिपोर्ट सामने आईं, पर केरल की यूडीएफ व एलडीएफ सरकार वर्षों से इन्हें दबाती रही। तेजस्वी के बयान का कांग्रेस सदस्य वेणुगोपाल ने विरोध किया पर केरल से जुड़ी यह रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि भूस्खलन के संबंध में दो विशेषज्ञ पैनलों की रिपोर्ट दस साल से ठंडे बस्ते में पड़ी है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

के. केस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाले वर्किंग ग्रुप ने इकोलाजिकल सेंसिटिव क्षेत्र चिह्नित किए थे, जिनमें वायनाड के भी 13 गांव थे। समिति ने इन क्षेत्रों में अनियमित व्यावसायिक-औद्योगिक गतिविधियां रोकने को विशेष प्रविधान की अनुशंसा की थी। तब राज्य के विभिन्न संगठनों सहित कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी विरोध किया। उसके बाद राज्य सरकार की तीन सदस्यीय समिति ने भी ऐसी ही अनुशंसाएं करते हुए 2014 में रिपोर्ट दी, पर अब तक राज्य सरकार नोटिफिकेशन तक जारी नहीं कर सकी।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री जार्ज कुरियन ने भूस्खलन प्रभावित लोगों से भेंट की। उन्होंने कहा, पीएम नरेन्द्र मोदी स्थिति पर करीबी नजर रखे हैं। केंद्र ने राज्य को हरसंभव सहायता देने का वादा किया है।

शोकाकुल परिवारों ने प्रियजनों की पहचान की, अंतिम संस्कार किया: प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के शव मेप्पाडी स्वास्थ्य केंद्र और नीलांबुर सरकारी अस्पताल में रेफ्रिजरेटर में रखे गए थे। लोग अपने प्रियजनों के शवों को पहचानते हुए और आखिरी बार देख कर बदहवास होकर रोते बिलखते देखे गए। इसी तरह के दृश्य श्मशानों में भी देखे गए, जहां शवों को एक-दूसरे के करीब दफनाया गया या उनका दाह संस्कार किया गया। प्रशासन ने लकड़ी व गैस आधारित दाह संस्कार भट्टियों में एक-दूसरे के बगल में कई शवों के अंतिम संस्कार किए जाने की तस्वीरें भी जारी कीं।

कहीं बाढ़ की नौबत तो कहीं सूखे की आशंका

जागरण टीम, नई दिल्ली

- उप्र, उत्तराखंड, हिमाचल व हरियाणा में जोरदार बारिश अलर्ट जारी, बिहार में मानसून के मुंह मोड़ने से किसानों की बेचैनी, जम्मू में सामान्य से कम वर्षा, उमस से लोग बेहाल

उत्तर भारत में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि कहीं बाढ़ की नौबत आ गई है तो कहीं सूखे की आशंका गहरा रही है। उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ने की आशंका है तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व उत्तराखंड में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते बदरीनाथ व केदारनाथ राजमार्ग पर मलबा आने से बाधित हुए हैं। उधर, बिहार में मानसून के मुंह मोड़ने से किसानों की बेचैनी बढ़ रही है। जम्मू में सामान्य से कम वर्षा हुई है। हालत यह है कि लगातार हो रही उमस लोगों को हाल-बेहाल किए हुए है।

कुछ जनपदों को छोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में बुधवार को झूम के वर्षा हुई। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं ने पूर्वी एवं मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और रुहेलखंड में दोपहर बाद जोरदार बारिश की। फर्रुखाबाद व बदायूं में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। वाराणसी में सभी प्रमुख घाटों का आपसी संपर्क पूरी तरह टूटने के साथ ही दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती स्थल और मणिकर्णिका घाट पर चिता स्थल और ऊपर कर दिया गया है। वहीं तेज बहाव के कारण छोटी नावों का संचालन रोक दिया गया है। आजमगढ़ में सरयू का जलस्तर खतरा बिंदु के करीब पहुंच गया है। वज्रपात से चित्रकूट में सगे भाइयों व फर्रुखाबाद में एक महिला की मौत हो गई।

हरियाणा में बुधवार को 10 जिलों जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, अंबाला, हिसार, भिवानी, रोहतक व यमुनानगर में तेज वर्षा हुई। गुरुवार को भी विभिन्न जिलों के लिए वर्षा का आरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी पर्वतीय जिलों में जोरदार वर्षा हुई। इससे चारधाम यात्रा मार्ग बाधित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गुरुवार को भी उत्तराखंड में भारी वर्षा जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर व चमोली में भारी वर्षा का आरेंज अलर्ट जारी किया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिसर में भरा पानी, शिवपाल ने ली चुटकी

लखनऊ में बुधवार को दो घंटे की जोरदार बारिश ने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोल दी। विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा था तभी बाहर सड़क से पानी गेट के अंदर घुसने लगा। इसे लेकर सपा महासचिव शिवपाल यादव ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट कर चुटकी भी ले ली। नगर निगम मुख्यालय के बरामदों में भी पानी भर गया था।

लखनऊ में बुधवार को विधानसभा परिसर में बारिश का पानी भर जाने के बाद पानी बाहर निकालता कर्मचारी। प्रेट्र

विस परिसर में पानी भर जाने पर वैकल्पिक मार्ग से निकलते सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रेट्र

अधिकतर राज्यों में सामान्य रही बारिश

पूरे भारत में मानसून फैल चुका है। देश में 1 जून से 30 जुलाई तक 12 राज्यों में सामान्य बारिश हुई है। वहीं, आठ राज्यों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। देश के सात राज्य ऐसे हैं, जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई है। केंद्र शासित क्षेत्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सामान्य से कम बारिश हुई है वहीं लद्दाख में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में सामान्य बारिश दर्ज की गई है।

जुलाई में 9% अधिक बारिश

भारत में जुलाई माह में औसत से 9 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के बुधवार तक के आंकड़ों से पता चलता है कि इस बार पूरे देश में मानसून तय समय से छह दिन पहले पहुंच गया और मध्य व दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मानसून का आगमन समय से होने से किसानों को खरीफ की फसलों की बुआई शुरू करने में मदद मिली है। (रायटर)

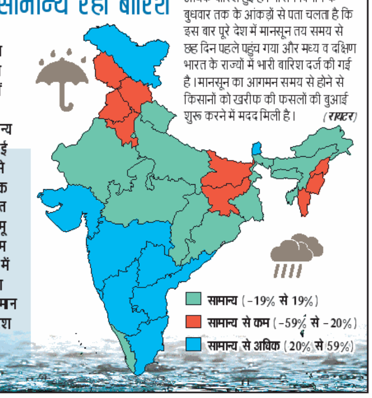

केरल के सीएम विजयन ने अमित शाह के दावे को किया खारिज

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने शाह के इस दावे को खारिज कर दिया कि राज्य सरकार को भारी बारिश के कारण वायनाड में प्राकृतिक आपदा के बारे में 23 जुलाई को ही चेतावनी दे दी गई थी। विजयन ने कहा कि भूस्खलन से पहले आइएमडी ने जिले के लिए केवल आरेंज अलर्ट जारी किया था। हालांकि जिले में 572 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई जोकि आइएमडी द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान से बहुत अधिक थी।

उन्होंने कहा कि मंगलवार सुबह (30 जुलाई) भूस्खलन के बाद ही जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि फिलहाल दोषारोपण का समय नहीं है और वह शाह की टिप्पणियों को प्रतिकूल रूप से नहीं ले रहे हैं। आरेंज अलर्ट का मतलब बहुत भारी बारिश (6 सेमी से 20 सेमी) है जबकि रेड अलर्ट 24 घंटे में 20 सेमी से अधिक भारी से अत्यधिक भारी बारिश को इंगित करता है।

जर्जर झूला पुल पर झूल रही तीन मुख्यमंत्रियों की घोषणा

जागरण पड़ताल

अजय खंतवाल • जागरण

कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल): तंत्र बेपरवाह हो तो घोषणाएं हवा में ही झूलती रहती हैं। करीब 14 वर्ष पहले नयार नदी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हुए सतपुली तहसील के बड़खोलू झूला पुल की जगह नया मोटर पुल बनाने की घोषणा अब तक तीन मुख्यमंत्री कर चुके हैं, पर आज तक पुल निर्माण के नाम पर एक पत्थर नहीं रखा गया। पुल इस कदर क्षतिग्रस्त है कि कभी भी नदी में समा सकता है। नवंबर 2022 में पुल से गिरकर एक बुजुर्ग की मौत भी हो चुकी है। आवाजाही का दूसरा विकल्प है, पर उससे दूरी 20 से 25 किमी बढ़ जाती है। ऐसे में डेढ़ दर्जन गांवों की तीन हजार से अधिक आबादी जान हथेली पर रखकर इसी पुल से आवाजाही करती है। सरकारी तंत्र भी यह जानता है, पर पुल पर आवाजाही प्रतिबंधित का बोर्ड लगाकर खानापूर्ति कर ली।

जनपद पौड़ी के अंतर्गत सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली की स्थिति बयां करता क्षतिग्रस्त झूला पुल। जागरण

- पौड़ी जिले की सतपुली तहसील में तीन मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी नहीं बन पाया मोटर पुल
- 14 वर्ष पहले नदी के उफान से जर्जर हुए झूला पुल से आवाजाही करने को मजबूर तीन हजार ग्रामीण

जनपद पौड़ी के अंतर्गत क्षतिग्रस्त झूला पुल में आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए लगाया गया चेतावनी बोर्ड। जागरण

> विश्व बैंक से पुल निर्माण को धनराशि आवंटित की गई है। हालांकि, अभी इस संबंध में विभाग को बांड नहीं मिला है, जिस कारण स्वीकृत धनराशि के बारे में जानकारी नहीं है। पुल निर्माण को निविदा जारी कर दी गई है। जल्द ही निर्माण शुरू किया जाएगा। -मृत्युंजय शर्मा, सहायक अभियंता, प्रांतीय खंड, लोनिवि पौड़ी

पौड़ी जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर सतपुली के पास बड़खोलू में नयार नदी पर वर्ष 1986 में झूला पुल बनाया गया था। 200 मीटर लंबा व चार मीटर चौड़ा यह पुल डेढ़ दर्जन गांवों को सतपुली जाने वाले मुख्य मार्ग से जोड़ता है। 17 सितंबर 2010 की रात नदी में आए उफान से पुल क्षतिग्रस्त होने के साथ टेढ़ा हो गया। ग्रामीणों ने नए पुल के लिए अफसरों व नेताओं से गुहार लगाई। वर्ष 2012 के विस चुनाव से पूर्व तत्कालीन सीएम बीसी खंडूड़ी ने मोटर पुल सहित बड़खोलू से कांडा तक 12 किमी सड़क बनाने का शासनादेश जारी किया। चुनाव बाद सरकार बदली और पुल निर्माण की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। बाद में कांग्रेस सरकार में सीएम हरीश रावत ने पुल बनाने का वादा किया, पर कुछ नहीं हुआ। वर्ष 2017 में सीएम बने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुल निर्माण की घोषणा की, लेकिन हालात जस के तस हैं।

13 काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत

शासन ने मोटर पुल के लिए करीब 12.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे 150 मीटर लंबा सिंगल लेन पुल बनना है। बड़खोलू ग्रामसभा के प्रधान रणवीर सिंह ने बताया कि पुल निर्माण के लिए 13 काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की गई है।

एक वर्ष पहले तक निर्भर थे तीन दर्जन गांव

एक वर्ष पहले तक बड़खोलू झूला पुल से तीन दर्जन गांवों के लोग सतपुली के लिए आवाजाही करते थे। इस बीच साकिन खेत होते हुए सतपुली तक सड़क बन गई, जिसके बाद डेढ़ दर्जन गांवों के लोग सड़क से आने-जाने लगे। शेष गांवों के लोग इसलिए सड़क का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि 20 से 25 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है।

सुकमा में सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया नक्सली स्मारक

टीम नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के जगरगुंडा में गत जून माह में आइईडी ब्लास्ट में दो जवानों के बलिदान होने के बाद नक्सलियों द्वारा बनाए गए स्मारक को बुधवार को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। सीआरपीएफ, कोबरा व जिला बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान के तहत तिम्मापुरम की ओर निकली थी। इसी दौरान उन्हें गांव में नक्सली स्मारक नजर आया, जिस पर त्वरित कार्रवाई की गई।

उधर, बीजापुर में नक्सल संगठन की भैरमगढ़ एरिया कमेटी से जुड़े एक लाख के इनामी सहित पांच नक्सलियों ने बुधवार को एसपी व अन्य अफसरों के समक्ष समर्पण किया। समर्पित नक्सलियों में मंगू पोटाम पर एक लाख रुपये का इनाम था। समर्पित नक्सली लूट और हत्या में शामिल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इसके पहले सोमवार रात पुन्नूर से पकड़े गए चार नक्सलियों महेन्द्र ईरपा, जोगा मिडियम, राकेश सोढ़ी व धर्मेंद्र ईरपा के विरुद्ध थाना आवापल्ली में कार्रवाई के बाद बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

जागरण विशेष

हार्ट अटैक से जान बचाने में मदद करेगी आइआइटी में बनी डिवाइस

इसकी मदद से न केवल घर में ही दी जा सकेगी सीपीआर बल्कि ये यह भी बताएगी सीपीआर कितना कारगर, केंद्र ने दिया पेटेंट

अखिलेश तिवारी • जागरण

कानपुर: आइआइटी कानपुर के इंजीनियरों और किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) लखनऊ के चिकित्सकों ने ऐसी डिवाइस तैयार की है, जो हार्ट अटैक की स्थिति में कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) देने में सहायता करती है। इसकी मदद से जाना जा सकता है कि हृदय पर सीपीआर का कितना असर हो रहा है। कितना अधिक या कम दबाव देने की जरूरत कितनी देर तक है। डिवाइस की मदद से सीपीआर देने का तरीका भी सीखा जा सकता है। आइआइटी को चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कई फार्मा कंपनियों के प्रस्ताव मिले हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद तय होगा कि किस कंपनी को उत्पादन के लिए डिवाइस दी जाएगी। तभी स्पष्ट हो सकेगा कि वह कब तक बाजार में आ सकेगी।

उपकरण की विशेषता

रियल-टाइम फीडबैक : सही दबाव गहराई सुनिश्चित करता है।

विशिष्ट प्रशिक्षण साधन : सीपीआर सीखना सरल बनाता है।

तकनीकी एकीकरण : उन्नत सेंसर और आडियो मार्गदर्शन।

इन्होंने किया आविष्कार: आदित्य राज, उर्वशी, प्रो. डा. जे. रामकुमार, केजीएमयू के डा. ऋषि सेठी

सीपीआर डिवाइस के प्रयोग की डिजिटल इमेज • आइआइटी कानपुर

> डिवाइस की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में सीपीआर की सुविधा हासिल हो सकेगी। पैरामेडिकल क्षेत्र के साथ ही स्कूल, कालेज के विद्यार्थियों को भी इसके प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे आकस्मिक हालत में तुरंत रोगियों का उपचार किया जा सके। इस तरह की कोई डिवाइस अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है।

प्रो. डा. जे. रामकुमार, आइआइटी कानपुर

आइआइटी और केजीएमयू के स्कूल आफ इंटरनेशनल बायोडिजाइन-सिनर्जाइजिंग हेल्थकेयर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (एसआइबी-शाइन) ने हृदयरोगियों को ध्यान में रखकर सीपीआर डिवाइस 'प्रयास' तैयार की है। इसकी मदद से हृदयरोगियों को आघात की स्थिति में उनके स्वजन घर में सीपीआर दे सकते हैं। हृदयाघात के मामलों में शुरुआती डेढ़ मिनट सबसे अहम होते हैं, जब सीपीआर देकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। एसआइबी-शाइन के फेलो सदस्य आदित्य राज भाटिया के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों के मामले में अक्सर देखा गया है कि सीपीआर देने का तरीका ठीक नहीं था, जिससे मरीज को लाभ नहीं मिल सका। इस समस्या का समाधान ही 'प्रयास' है।

ऐसे काम करती है डिवाइस: डिवाइस का वजन 100 ग्राम से भी कम है। इसे हार्ट अटैक वाले मरीज के सीने के बीच में रखा जाता है। यह हृदय की गति और सीपीआर से पड़ने वाले दबाव का आकलन करती है। जो सीपीआर दिया जा रहा है, उसका दिल पर कितना असर हो रहा, सही दबाव दिया रहा है या अधिक दबाव की जरूरत है, इस तरह की गलतियों को पहचान भी डिवाइस से होती है। सही सीपीआर पर नीला और गलत तरीका होने पर लाल रंग का छोटा सा बल्ब जलता है। सीपीआर देने में गलती होने पर इनबिल्ट स्पीकर से डिवाइस आगाह भी करती है। शोध टीम के भाटिया ने बताया कि हमारी कोशिश स्कूल, कालेज और सामाजिक संगठनों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीपीआर के लिए प्रशिक्षित करने की भी है। बाजार में अभी इस तरह की डिवाइस नहीं है। उनके मुताबिक इसे एक हजार रुपये के न्यूनतम मूल्य पर बाजार में उतारा जा सकता है। इसके लिए फार्मा कंपनियों से बात की जा रही है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

सुप्रीम कोर्ट ने की गवली की रिहाई पर रोक संबंधी अपने आदेश की पुष्टि

- निर्णय सुनाते समय फिल्म शोले के एक संवाद 'सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा' का किया जिक्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली की समय पूर्व रिहाई पर रोक लगाने संबंधी अपने पहले के आदेश की पुष्टि की। कोर्ट ने इस मामले में निर्णय सुनाते समय फिल्म शोले के एक संवाद 'सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा' का जिक्र किया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने बांबे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के पांच अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए तीन जून के अपने आदेश को बरकरार रखा। उसने अपीलों पर सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की। हाई कोर्ट ने राज्य प्राधिकारियों को 2006 की सजा माफी नीति के तहत गवली की समय पूर्व रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा, हम कोई अंतरिम राहत देने के पक्ष में नहीं हैं। हमारे द्वारा दिए गए अंतरिम रोक संबंधी आदेश की पुष्टि की जाती है। अपील की सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने गवली की याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसमें उसने 10 जनवरी, 2006 की सजा माफी नीति के आधार पर राज्य सरकार को समय से पहले रिहाई के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था जो 31 अगस्त, 2012 को उसकी दोषसिद्धि की तारीख तक लागू थी। गवली मुंबई में शिवसेना के पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की 2007 में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसने 2006 की सजा माफी नीति की सभी शर्तों का पालन करने का दावा किया है।

दैनिक जागरण
आस्था के अभाव में भक्ति का कोई औचित्य नहीं

जाति की राजनीति

बहुत दिन नहीं हुए, जब राहुल गांधी लोगों और विशेषकर अधिकारियों एवं मीडिया वालों की जाति पूछते थे, लेकिन जब लोकसभा में उनका उल्लेख किए बिना यह तंज कसा गया कि जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं, वे उसकी गणना की मांग कर रहे हैं तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता संसद के भीतर और बाहर आपे से बाहर हो गए। इनमें कांग्रेस के वे नेता भी हैं, जो लोगों की जाति जानने की राहुल गांधी की उत्कंठा को उनका मास्टर स्ट्रोक बताया करते थे। जब कोई घूम-घूमकर इनकी-उनकी जाति जानने की कोशिश करेगा तो फिर उसे वैसे कटाक्ष सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा विगत दिवस भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने किया। राहुल गांधी इस कटाक्ष को अपना अपमान बता रहे हैं। यह वही राहुल हैं, जो चंद दिन पहले ही लोकसभा में भाजपा नेताओं को दुर्योधन, शकुनी आदि बताने में लगे हुए थे। इसके पहले वह एक जनसभा में यह कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो ओबीसी हैं ही नहीं। यह एक नीति की बात है कि किसी को भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसा उसे अपने लिए पसंद न हो। अनुराग ठाकुर के बयान पर संसद में जो हंगामा हो रहा है, वह केवल खीझ मिटाने और जनता का ध्यान भंग करने के लिए हो रहा है। यह हास्यास्पद ही है कि अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन करने के कारण कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने पर विचार कर रही है।

संसद में जाति पर जैसा घमासान हो रहा है, वह जाति की राजनीति का नतीजा है। दुर्भाग्य से जब देश को जाति की राजनीति से बाहर लाने की कोशिश की जानी चाहिए, तब कुछ दलों और विशेष रूप से कांग्रेस के नेता जाति की राजनीति को तूल देकर समाज में विभाजन और वैमनस्य पैदा करने में लगे हुए हैं। वे यह कहकर जाति गणना की मांग करने में लगे हुए हैं कि इससे ही समस्त समस्याओं का समाधान होगा और सामाजिक न्याय का लक्ष्य हासिल होगा। यदि जाति गणना इतनी ही आवश्यक थी तो दशकों तक केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? प्रश्न यह भी है कि क्या लोगों की जाति जाने बिना उन्हें गरीबी से बाहर निकालने और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रश्न हल करना संभव नहीं? हर कोई इससे अच्छी तरह परिचित है कि जाति की राजनीति ने समाज को विभाजित करने के साथ सामाजिक न्याय की राह में मुश्किलें पैदा की हैं, फिर भी कुछ नेता अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए समाज को जातियों में बांटने में लगे हुए हैं। जातीय वैमनस्य के रूप में इसके दुष्परिणाम सामने हैं, लेकिन जातिवादी नेता यह देखने-समझने को तैयार नहीं। हमारे समाज में तो केवल दो ही जातियां होनी चाहिए-अमीर एवं गरीब और उनका ही पता लगाया जाना चाहिए।

अराजकता पर रोक जरूरी

पंजाब में पिछले कुछ दिनों से निहंगों की ओर से जिस तरह हमले किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की छवि प्रभावित हो रही है। ताजा मामला तरनतारन में एक दुकानदार की हत्या का है। पैसे के लेनदेन को लेकर उसकी बाजू काट देने से अस्पताल में मौत का मामला अत्यंत गंभीर है। यदि किसी भी तरह का विवाद था तो निहंगों को इसकी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवानी चाहिए थी। पैसे के लेनदेन के विवाद की स्थिति में संबंधित सक्षम अधिकारी के पास जाना चाहिए। यदि वहां सुनवाई नहीं होती है तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। निहंगों द्वारा अराजकता की घटनाएं लगातार बढ़ना चिंता वाली बात है। जुलाई में ही पांच घटनाएं हो चुकी हैं। लुधियाना में शिवसेना नेता सहित दो व्यक्तियों पर तलवार से हमला करने के अलावा संगरूर में बिजली मैकेनिक की हत्या मामूली बात पर कर दी गई। अमृतसर में भारतीय प्रबंधन संस्थान परिसर में भी निहंग द्वारा उत्पात मचाया गया। इसके अलावा जालंधर सहित अन्य जिलों में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस तरह की घटनाओं को राज्य सरकार और पुलिस विभाग के आलाधिकारियों को गंभीरता से लेना होगा। किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट किसी भी कीमत पर नहीं दी जानी चाहिए। लगातार यदि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो समाज में भय पैदा होना स्वाभाविक है। कभी भी राज्य की जनता को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पुलिस असहाय बनी हुई है। राज्य में कानून का शासन होने के साथ ही यह दिखना भी चाहिए। पुलिस के लाचार दिखने की स्थिति भविष्य में गंभीर संकट पैदा कर सकती है।

> किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट किसी भी कीमत पर नहीं दी जानी चाहिए। राज्य में कानून का शासन होने के साथ ही यह दिखना भी चाहिए

अपने भीतर झांके अमेरिका

ए. सूर्यप्रकाश

भारत को उपदेश देने से बेहतर है कि अमेरिकी संस्थान अपने उन पहलुओं पर ध्यान दें, जिनके चलते उनके लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यापक क्षति पहुंची है

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर गठित संयुक्त राज्य (अमेरिकी) आयोग यानी यूएससीआइआरएफ ने बीते दिनों अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और इस गिरावट के लिए मुख्य रूप से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आयोग के अनुसार भाजपा सरकार भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों की राह पर चलते हुए नफरती विमर्श को बढ़ावा दे रही है। सरकार-मुस्लिम, ईसाई, सिख, दलित, यहूदी और आदिवासी आदि तबकों की सांप्रदायिकता से रक्षा नहीं कर पा रही। उसका यह भी कहना है कि यूएपीए, एफसीआरए, सीसीए और मतांतरण विरोधी एवं गोहत्या पर शिकंजा कसने वाले कानूनों के जरिये भी न केवल इन तबकों, बल्कि उनके पक्ष में आवाज उठाने वालों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला भी आयोग को पचा नहीं, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को सही पाया। आयोग ने जम्मू-कश्मीर का एक 'मुस्लिम बहुल' राज्य के रूप में हवाला देते हुए वहां उत्पीड़न की बातों के साथ ही एक मुस्लिम पत्रकार की गिरफ्तारी का भी संदर्भ रखा। हालांकि, आयोग ने इस तथ्य के प्रति आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांधे रखी कि इसी एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य से करीब पांच लाख हिंदुओं को बेदखल कर दिया गया और वे अपने ही देश के दूसरे हिस्सों में शरणार्थियों का जीवन जीने पर विवश हैं। इस रिपोर्ट का सार समझें तो उसकी दृष्टि में हिंदुओं के जीवन का कोई मोल ही नहीं।

बुनियादी रूप से अमेरिकी रिपोर्ट आरोपों और अर्धसत्यों से भरी पड़ी है। इसमें यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि भारत 'राज्यों का एक संघ' है, जहां राज्यों के पास व्यापक विधायी एवं प्रशासनिक अधिकार और कार्यक्षेत्र हैं। इसमें कानून एवं व्यवस्था का दारोमदार तो मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। अर्थात चाहे सांप्रदायिक हिंसा हो या कानून एवं व्यवस्था के मोर्चे पर कोई अन्य चुनौती सामने आए तो उससे निपटने का दायित्व राज्यों में कमान संभाल रही सरकारों का है। रिपोर्ट में इसका भी संज्ञान नहीं लिया गया है कि भारत में करीब 40 प्रमुख राजनीतिक दल हैं। उनमें से कुछ अलग-अलग गठबंधनों का हिस्सा हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल, झारखंड, हिमाचल और पंजाब जैसे राज्यों में तो भाजपा या राजग विरोधी सरकारें सत्तारूढ़ हैं। इसके बावजूद रिपोर्ट में अन्य राजनीतिक दलों के शासन वाले राज्यों का उल्लेख नहीं। भाजपा विरोधी दलों के शासन वाले राज्यों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों का भी कोई जिक्र नहीं। बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाओं पर भी रिपोर्ट मौन है।

अवधेश राजपूत

अमेरिकी रिपोर्ट लगभग उसी दौरान आई जब विभिन्न देशों में लोकतंत्र की दशा-दिशा से जुड़ी प्यू की एक रिपोर्ट सामने आई। प्यू के सर्वे के अनुसार केवल 19 प्रतिशत अमेरिकी ही यह मानते हैं कि उनका लोकतंत्र अन्य देशों के लिए अनुकरणीय है। उनमें से कुछ युवाओं का तो यहां तक मानना रहा कि अमेरिकी लोकतंत्र कभी भी दूसरों के लिए एक आदर्श रहा ही नहीं। दूसरी ओर, करीब 77 प्रतिशत भारतीय देश में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर संतुष्ट हैं। इस मामले में 80 प्रतिशत के आंकड़े के साथ सिंगापुर शीर्ष पर है। अगर किसी देश के नागरिकों का लोकतंत्र में इतना व्यापक विश्वास है तो क्या वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना उचित है? इन उत्तरदाताओं में अल्पसंख्यक नागरिक भी शामिल रहे होंगे। जबकि अमेरिका में लोकतंत्र के प्रति धारणा खासी नकारात्मक है। इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है, जिसमें सदियों पुराने नस्लीय दंगों, हिंसक भीड़ के मामले, कैलिफोर्निया में नरसंहार, प्रवासियों को लेकर हुए दंगे, 1919 में शिकागो का नस्लीय दंगा और 1921 में तुलसा नस्लीय नरसंहार जैसे अध्याय शामिल हैं। यह सिलसिला 2020 में श्वेत पुलिसकर्मी द्वारा अश्वेत जार्ज फ्लायड की हत्या के बाद हुए विरोध-प्रदर्शनों तक जारी रहा। ऐसे में अमेरिकी आयोग को अपने भीतर झांकना चाहिए। वहां नस्लीय संघर्ष निरंतर काबू से बाहर होकर अमेरिका की लोकतांत्रिक साख पर बट्टा लगा रहा है। यह भी दुखद है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों को न तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कोई जानकारी है और न ही वे भारतीय राज्यों के सामाजिक एवं धार्मिक तानेबाने से ही परिचित हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आठ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक स्थिति में हैं। लक्षद्वीप में हिंदू 2.5 प्रतिशत, मिजोरम में 2.75 प्रतिशत, मेघालय में 11.53 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर में 28.44 प्रतिशत, अरुणाचल में 29 प्रतिशत, मणिपुर में 31.39 प्रतिशत और पंजाब में 38.40 प्रतिशत हैं। रिपोर्ट में इन राज्यों में प्रताड़ना के शिकार हिंदुओं या मुस्लिमों के दबदबे वाले केरल एवं उत्तर प्रदेश से ऐसी घटनाओं पर एक शब्द नहीं खर्च किया गया। कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं। अमेरिकी आयोग ने विश्व के सबसे जीवंत एवं गतिशील लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से प्राप्त व्यापक मूल अधिकारों से संरक्षित अल्पसंख्यकों को लेकर अनावश्यक चिंता व्यक्त की है। अब हमें इस आयोग को प्यू रिसर्च सर्वे के जरिये आईना दिखाकर खुद उसे एक 'चिंतित करने वाले संस्थान' के रूप में चिह्नित करना चाहिए। भारतीय राज्य की प्रकृति एवं स्वरूप पर समग्रता में विचार किए बिना यह अमेरिकी आयोग मूर्खतापूर्ण ढंग से भारत को एकल सरकार और एक राजनीतिक दल केंद्रित व्यवस्था के रूप में देखता है। चूंकि यूएससीआइआरएफ अमेरिका का एक राष्ट्रीय संस्थान है तो उसकी यह प्रस्तुति और हैरान करती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बस होने ही वाले हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि वहां के संस्थान अपने देश की उन भ्रंश रेखाओं पर ध्यान दें, जिनके चलते हाल के वर्षों में उनके लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यापक क्षति पहुंची है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला इसका ही नतीजा माना जा रहा है।

(लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

बदहाल शिक्षा की देन हैं कोचिंग केंद्र

गिरीश्वर मिश्र

व्यावसायिक कोचिंग का विशाल धंधा शिक्षा की घोर दुर्व्यवस्था की स्थिति को ही बयान करता है

पिछले दिनों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। आइएएस की तैयारी कराने वाले एक नामचीन कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में अचानक भरे पानी में डूबकर तीन छात्रों की मौत हो गई। यह दुर्घटना आपराधिक लापरवाही का परिणाम लगती है, क्योंकि यह हादसा गैर कानूनी ढंग से चलने वाले कोचिंग सेंटर की निजी व्यवस्था के तहत हुआ। देखा जाता है कि देश में जब भी कोई गंभीर घटना होती है और जनता की आवाज उठती है तो जांच कमेटी बैठेगी, सख्त कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा जैसी घोषणाएं करते हुए सरकार थोड़ी देर के लिए जगती है। जैसे कि इस दर्दनाक हादसे में भी देखा जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रायः घटनाओं को और उनके आशय को अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। समय बीतने के साथ लोग भी भूल जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इस बीच राजनीति और राजनेता भी बदल जाते हैं। फिर हम अक्सर वहीं खड़े रहते हैं, जहां पहले खड़े थे। उम्मीद है यह घटना इस यथास्थितिवाद को तोड़ेगी।

इसमें दोराय नहीं कि भारत के पास अतीत की बड़ी थाती है। हम सभी नागरिक भारतीय होने पर गर्व भी करते हैं। यह महान देश निकट भविष्य में विश्वगुरु बनने की उत्कट इच्छा पाले हुए है। इसके साथ ही भारत को विकसित देश बनाने का दावा भी किया जा रहा है। इस दृष्टि से युवा वर्ग की भूमिका और दायित्व खास हो जाता है। आज देश में सामाजिक और भौतिक विविधताएं तो हैं ही आर्थिक विषमता भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में हर युवा ऊंची से ऊंची उड़ान भरने के लिए स्वाभाविक रूप से आतुर हो रहा है। इस हलचल भरे माहौल में युवा वर्ग अपने भविष्य को संवारने के लिए घर-बार छोड़ कर कोचिंग करने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं। अभिभावक गण रुपया-पैसा जुटा कर अपने बच्चों को कोचिंग के साथ परीक्षा की तैयारी में आर्थिक मदद करते हैं। आशाओं और आकांक्षाओं की उठापटक के बीच ये युवा कठिन परिस्थितियों में अथक परिश्रम करते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए धैर्यपूर्वक और लगन के साथ कोशिश करते हैं। अब औपचारिक डिग्री की गुणवत्ता पिटने के फलस्वरूप हर काम के लिए, यहां तक कि

दिल्ली में सील किए जाते कोचिंग केंद्र। एएनआइ

अगली कक्षा में प्रवेश या फेलोशिप के लिए भी कोई न कोई परीक्षा अनिवार्य हो गई है। खस्ताहाल हो रही औपचारिक शिक्षा अपर्याप्त होती है। ऐसे में यदि कोचिंग केंद्रों की झड़ी लग रही है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, मगर इस लाभ वाले व्यापार के विस्तार के साथ इसके सुचारु संचालन के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी है। वस्तुतः व्यावसायिक कोचिंग का विशाल धंधा शिक्षा की घोर दुर्व्यवस्था को ही बयान करता है।

विद्यालय की पढ़ाई से विद्यालय की परीक्षा की तैयारी और कोचिंग की पढ़ाई से व्यावसायिक परीक्षा की तैयारी, यह आज हर अभिभावक और विद्यार्थी की मानसिकता बन गई है। इसके चलते आज मेधावी बच्चे भी विद्यालय को छोड़ कोचिंग में भर्ती हो रहे हैं। कोटा नगरी की व्यथा-कथा विश्व प्रसिद्ध हो चली है। सरकारी शिक्षा के प्रति सरकार, समाज और विद्यार्थी सबका अविश्वास बढ़ रहा है। इस टूटते भरोसे के बीच कोचिंग की वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था खूब फल-फूल रही है। इसकी रोकथाम करने के बदले साझी प्रवेश परीक्षा पर जोर इसी अविश्वास की पुष्टि करती है और घोषित करती है कि विद्यालय की पढ़ाई जैसे हो रही थी, जारी रहेगी। यदि आगे पढ़ने-पढ़ाने की इच्छा है तो विद्यालयी परीक्षा के अतिरिक्त इस नई परीक्षा को अनिवार्य रूप से पास करना होगा। विद्यालय की पढ़ाई प्रवेश परीक्षाओं के लिए सिर्फ प्रवेश पत्र रह गई है। यह दुर्भाग्य है कि सरकार विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए तत्पर नहीं हो रही है। वह हर चीज को तब तक झुलाती रहती है जब तक इंतहा न हो जाए।

शिक्षा पर बाजार की भयंकर जकड़न दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकारी व्यवस्था अक्सर इस बात से बेखबर और उदासीन रहती है कि शिक्षा और कोचिंग संस्थानों में क्या और कैसे हो रहा है। शिक्षा के प्रति उदासीनता का रवैया और युवा वर्ग की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ आत्मघाती और अक्षम्य अपराध है। गैरकानूनी शिक्षा की दुकानों में और उनके आसपास विद्यार्थियों के रहने के लिए बने पीजी आवासों में भी आए दिन हादसे होते रहते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से निहायत बुरे हालात में चलने वाले ये कोचिंग के व्यापार केंद्र देश में शिक्षा की दुर्गति की हकीकत बयान करते हैं। आज की जनसंख्या में युवावर्ग के अनुपात में हो रही वृद्धि के साथ शिक्षा पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा नीति से क्रांति लाने के दावे के बावजूद दूर-दूर तक कोई राहत नजर नहीं आ रही है। यह जरूर है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि सरकारी पहल नदारद या नाकाफी है। न तो सरकार की ओर से शिक्षा में पर्याप्त निवेश हो रहा है, न व्यवस्था ही ठीक हो पा रही है। चूंकि शिक्षा देश के समाज के मानस-निर्माण, उत्पादकता तथा सृजनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है और देश के भविष्य को प्रभावित करती है, लिहाजा इस दिशा में तत्काल ध्यान देना आवश्यक है। दिल्ली में युवा जीवन की असमय मौत की यह दास्तान शिक्षा के क्षरण का ही एक लक्षण है, जो समूचे देश के लिए खेद का विषय है। समाज और सरकार सबको इस पर सोचना होगा और आवश्यक कदम उठाने होंगे।

(लेखक पूर्व कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

रुद्राभिषेक

रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने के रस के अर्पण के निहितार्थों पर गौर किया जाए तो ये समस्त पदार्थ ज्वलनशीलता से राहत देने वाले पदार्थ हैं। भगवान शंकर के अभिषेक का संबंध मानव-जीवन के साथ भी जुड़ता है। मनुष्य को भी जीवन में कठिनाइयों एवं विसंगतियों की ज्वलनशीलता का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब तक शीतल और शांत ढंग से मन को अभिसिक्त नहीं किया जाएगा तब तक विपरीत माहौल को अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। मनुष्य का शीश भी शिवलिंग जैसा है। इसी शीश भाग में स्थित पंच ज्ञानेंद्रियां शिवतत्व का अहसास कराती हैं और इन्हीं पंच ज्ञानेंद्रियों में विकृतियां आ जाती हैं तो दैत्य भाव जागृत हो जाता है। देखा जाए तो मस्तिष्क ही नहीं पूरे शरीर में जल-तत्व है। जब कभी यह जलतत्व कम हो जाता है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है।

भगवान शंकर का प्रत्यक्ष जलाभिषेक उनके मस्तक पर विराजने वाले चंद्रमा ने किया था। धर्मग्रंथों में उल्लिखित 'शिवशिरोमालिका स्तुतिः' के अनुसार कार्तिकेय मोर पर बैठकर पिता शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी के गले में लिपटा सर्प मोर को देखकर डर गया। अपने सान्निध्य में रहने वालों को भगवान शंकर तो अभयदान देते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे अग्नि-ज्वाला प्रकट होने लगी। अग्नि की ज्वलनशीलता को देखकर मस्तक पर स्थिति चंद्रमा ने 'सुधामृत' से भगवान का अभिषेक करना शुरू किया। चंद्रमा के अमृत-अभिषेक की बूंदें शंकर जी के गले के मुंडमाल में स्थित ब्रह्मा के पांचवें कटे हुए मुख में जाकर पड़ा तो वह भी जीवंत हो गया। ब्रह्मा ज्ञान के देवता हैं। ऐसी स्थिति में सुषुप्त ज्ञान भी जागृत हो गया। इस प्रकार सावन में भगवान शंकर के अभिषेक का आशय मन को शीतल बनाने एवं ज्ञान को जागृत करना भी है।

सलिल पांडेय

रेल दुर्घटनाओं पर नियंत्रण

मनीष कुमार

आधुनिक तकनीक के माध्यम से सभी रेलवे ट्रैक को कवच तकनीक से सज्जित किया जाना चाहिए

देश में रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड में एक मालगाड़ी के डिब्बों से टकराकर हावड़ा से मुंबई जा रही मुंबई मेल के अनेक डिब्बे पटरी से उतर गए। एक महीने से कम अवधि में यह तीसरी दर्दनाक रेल दुर्घटना है। इन घटनाओं के बाद से ट्रेनों को कवच तकनीक से लैस की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कवच एक खास तरह का आटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच प्रणाली किसी आपातकालीन स्थिति में ट्रेनों को स्वचालित रूप से रोक देती है। साफ है इससे रेल हादसों को कम किया जा सकता है। इस तकनीक पर भारतीय रेलवे ने साल 2012 में ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अफसोस कि अभी भी इस तकनीक को बहुत कम ही ट्रेनों में इंस्टाल किया जा सका है।

केंद्र सरकार 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से 508 स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने का दावा करती है, किंतु सवाल यह है कि स्टेशनों को चमकते हुए दिखना सुरक्षित रेल यात्रा मुहैया करवाने से अधिक आवश्यक कैसे हो सकता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की ग्रुप सी और डी नौकरियों की भर्ती में कुछ वर्षों से भारी कटौती की जा रही है। ये कर्मचारी रेलवे ट्रैक में खामियां और सिग्नल की समस्या आदि देखा करते हैं। भारत अमेरिका, चीन, रूस के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अमेरिका, चीन और रूस में पैसेंजर ट्रेनों की औसत गति क्रमशः 80-130, 200-300 और 160-200 किमी प्रति घंटा है। जबकि भारत में एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा और साधारण ट्रेनों की औसत गति 37.7 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। इन तीन देशों में भारत की तुलना में यात्री ट्रेनों की स्पीड इतनी अधिक होने के बावजूद रेल दुर्घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं।

रेल दुर्घटनाओं को मरने वालों की संख्या से नहीं आंका जाना चाहिए। प्रतिदिन लगभग ढाई करोड़ लोग भारतीय रेल में यात्रा करते हैं। जाहिर है इस तरह के हादसे इन रेल यात्रियों के विश्वास को डगमगाते हैं। इससे पहले कि रेल का टिकट मौत का टिकट बने, सरकार को रेलवे की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले आधुनिक तकनीक के माध्यम से सभी रेलवे ट्रैक को कवच तकनीक से सज्जित किया जाना चाहिए। हालांकि इसकी लागत बहुत अधिक है, परंतु यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से यह आवश्यक है। साथ ही रेलवे को चाहिए कि वह तकनीकी खामियों को घटाने की कोशिश करे एवं ग्रुप सी तथा डी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए। रेलवे की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करवाना होना चाहिए, न कि केवल स्टेशन को चमकाना, क्योंकि 'जान है तो जहान है'।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

धर्म की आड़ में हिंसा नहीं

'देशघाती साबित होता एक अधिकार' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राजीव सचान ने सांप्रदायिकता की समस्या को उजागर करते हुए शिक्षा में सुधार, मीडिया की जिम्मेदारी और कठोर सरकारी कदम उठाने पर जोर दिया है। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां तकनीक और विज्ञान ने हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, तब भी हम सांप्रदायिकता के दलदल में फंसे हुए हैं। हमें समझना होगा कि यह हमारे समाज को कमजोर बनाती है और हमारे विकास में बाधा डालती है। नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना होगा। हमें अपनी राजनीतिक और धार्मिक मान्यताओं को एक तरफ रखकर समाज के विकास और प्रगति के लिए एकजुट होना होगा। इसके लिए समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसे कि डाक्टर, वकील, शिक्षक, और अन्य पेशेवरों को आगे आना होगा और समाज में जागरूकता फैलानी होगी। समाधान के लिए हमें सबसे पहले अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने होंगे। बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही पंथनिरपेक्षता, सहिष्णुता, और भाईचारे का महत्व सिखाना होगा। इसके साथ ही, हमें अपने शिक्षण संस्थानों में नैतिक शिक्षा और मानवाधिकारों की शिक्षा को प्रमुखता से शामिल करना होगा। सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। सरकार को कठोर कानून बनाने होंगे जो सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में सक्षम हों। इसके साथ ही, प्रशासन को भी सतर्क रहना होगा और ऐसी घटनाओं को समय रहते काबू में करना होगा। इसके लिए पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे ऐसी स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभाल सकें। अंत में यह समझना आवश्यक है कि समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें हर प्रकार के विभाजनकारी तत्वों का विरोध करना होगा और समाज में भाईचारा और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करना होगा। केवल इसी मार्ग पर चलकर हम एक मजबूत और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

देश के प्रति जिम्मेदार बनें नेता प्रतिपक्ष

'विभाजनकारी राजनीति' शीर्षक से युक्त संपादकीय में केंद्रीय बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष की बेतुकी बातों को फिजूल बताते हुए जो नसीहत दी गई है, वह गौरतलब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी यह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता जनार्दन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत देकर भाजपा को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपते हुए कांग्रेस को फिर से विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है। संख्याबल की दृष्टि से उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का सम्मानजनक दायित्व भी मिल चुका है। निःसंदेह अब उनको चुनावी प्रतिद्वंद्विता की मानसिकता से बाहर निकल कर देशहित में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वाह गंभीरता के साथ करना चाहिए, क्योंकि देश उनको लोकसभा के अंदर धीर-गंभीर नेता प्रतिपक्ष के रूप में राष्ट्रहितैषी आचरण करते हुए देखना चाहता है, लेकिन यह विडंबना ही है कि राहुल गांधी चुनावी मोड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वह बजट बनाने वाले अधिकारियों की जाति ढूंढ़ रहे हैं। उनके मन-मस्तिष्क में चुनाव के समय की विद्वेषपूर्ण राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इस कदर घर गई है कि भाजपा के चुनावी चिह्न कमल को भी बजट की चर्चा में घसीट लाए। लोकसभा के मानसून सत्र में जब केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर विपक्ष की ओर से गंभीर और सकारात्मक विमर्श की उम्मीद थी तब नेता प्रतिपक्ष ने अपनी अटकलबाजियों से देश को निराश किया। नेता प्रतिपक्ष ने बजट की सार्थक चर्चा से परे जाकर प्रधानमंत्री मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारत के दो बड़े उद्योगपतियों को लक्षित कर जैसी बेतुकी बात की है, उससे साबित हो गया कि देशहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने में उनकी कोई रुचि नहीं है।

pandeyvp1960@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

82 प्रतिशत ऊर्जा खपत का हिस्सा जीवाश्म ईंधन के माध्यम से ही हो रहा है समूची दुनिया में, जिसे कम करने के लिए तमाम देश निरंतर अनूठे प्रयोग करते हुए स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के प्रयास में लगे हुए हैं।

संजय श्रीवास्तव
विज्ञान एवं तकनीक के जानकार

आजकल

तैरते न्यूक्लियर प्लांट से बदलेगी तस्वीर

ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों के बीच जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे में तैरने वाला भारत स्माल माड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी प्लांट बनाने के लिए शोध एवं विकास की ओर देश के बढ़ते कदम क्रांतिकारी हैं। इसके जरिये सरकार ऊर्जा, पर्यावरण, आर्थिक, कूटनीति तथा तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में अपनी बढ़त कायम कर सकेगी। सतत विकास के मामले में वह अपेक्षाओं पर खरी उतर सकेगी। वैसे यह इतना आसान भी नहीं हैं, परंतु सरकार ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं, जो सराहनीय पहल है

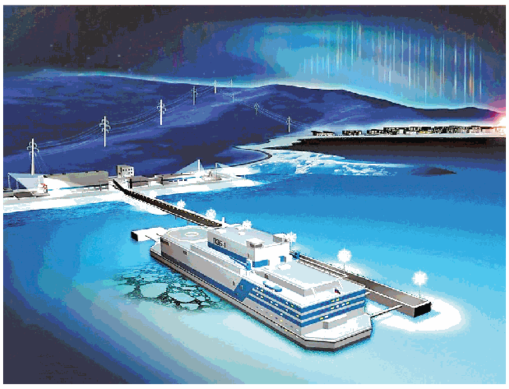

प्रतीकात्मक

हमारा देश छोटे माड्यूलर रिएक्टर से युक्त नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। कई माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलकर बनने वाला यह 'भारत स्माल माड्यूलर रिएक्टर प्लांट' समुद्र पर तैरेगा। इस परियोजना के लिए आम बजट में एक लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। ऊर्जा, पर्यावरण, आर्थिकी और तकनीक के क्षेत्रों में यह योजना क्रांतिकारी प्रभाव डालेगी, परंतु बजट सत्र के दौरान मिलने वाली संभवतः सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन सूचना के बावजूद इसकी चर्चा न्यून ही रही। ऊर्जा, अर्थशास्त्र एवं वित्तीय विश्लेषण संस्थान आइईईएफए के अनुसार, आज दुनियाभर में स्माल माड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर या एसएमआर की लगभग 80 अवधारणाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। कई बड़ी नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं में देरी के चलते नीति निर्माता 10 से 300 मेगावाट तक की क्षमता वाली इस परमाणु तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं।

एसएमआर की तकनीक पर कई देश काम कर रहे हैं जैसे अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। फ्रांस जैसे कुछ देशों के पास यह तकनीक विद्यमान है, लेकिन रूस और चीन ही अभी तक तैरने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर बना सके हैं। अमेरिका का फ्लोटिंग रिएक्टर शायद 2035 तक कार्यक्षम हो पाएगा। भारत ने फिलहाल वर्ष घोषित नहीं किया है, परंतु 2021 से ही प्रयासरत सरकार जल्द इसे स्थापित करना चाहेगी।

हमें सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के वैश्विक लक्ष्य को भी पूरा करना है, ताकि विश्व मंच पर सुर्खरू हो सकें। ऐसे में यह भारत के सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। देश के पारंपरिक वृहदाकार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से दूर होने और किफायती नाभिकीय समाधानों के नजदीक जाने की शुरुआत को इंगित करता है। इस योजना पर आगे बढ़ने के बाद भारत तमाम विकसित देशों और पर्यावरण के पहरुओं के सामने कह सकेगा कि वह शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका प्रमाण उसका यह प्रयास है, जिससे ग्रीन एनर्जी का उपयोग बढ़ेगा। पर्यावरण जिम्मेदारियों के साथ ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

जीवाश्म ईंधन में कमी : कोयले के इस्तेमाल में भारत का स्थान चीन के बाद विश्व में दूसरा है। विकासशील देश होने के नाते हमें अभी बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, देश में बिजली चलित वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में दो दशक के बाद हमारी बिजली की खपत दोगुना तक बढ़ सकती है। परमाणु ऊर्जा के बड़े संयंत्र खर्चीले हैं, इनकी स्थापना के लिए बड़ी जगह चाहिए। ऐसे में फ्लोटिंग रिएक्टर बनाने का फैसला भूमि अधिग्रहण और उससे जुड़ी दिक्कतों को खत्म करेगा। जमीन का उपयोग न होने और अत्याधुनिक तकनीक के चलते इसे कम खर्चीला माना जा रहा है। इनका प्रयोग सुदूर, तटवर्ती अथवा समुद्र के पास के पहाड़ी क्षेत्र, रणनीतिक महत्व वाले द्वीपों तक बिजली पहुंचाने में आसानी हो सकती है। इसे किसी ग्रिड से जोड़ना, ग्रिड की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करना भी आसान है।

दुनिया अभी भी अपनी ऊर्जा खपत का 82 प्रतिशत जरूरतें जीवाश्म ईंधन से पूरी करती है। अगर बिजली क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना है तो सरकारों को ऐसे निर्णय लेने ही होंगे। इसी वजह से सरकार छोटे-छोटे परमाणु रिएक्टरों के जरिए बिजली पैदा करना चाहती है। इसके लिए भारी बजट आवंटन चाहिए, एक लाख करोड़ रुपये बस आरंभ के लिए ही ठीक है। सरकार को प्राइवेट कंपनियों से उम्मीद है जिनके साथ मिलकर वह भारत स्माल माड्यूलर रिएक्टर बनाने और परमाणु ऊर्जा के जरिए ज्यादा से ज्यादा बिजली तैयार करने के बारे में सोच रही है। पर इसका दूसरा पहलू भी है। कंपनियां लंबे समय तक अनिश्चित निवेश से बचना चाहेंगी और अपना आर्थिक लाभ देखकर आएंगी, पर क्या नाभिकीय बिजली बेचना लागत और मुनाफे के आधार पर फायदे का सौदा रहेगा?

फिलहाल विदेशी अध्ययन यह कहते हैं कि यह तकनीक अभी भी नई है और व्यावहारिकता के धरातल पर कसा जाना बाकी है। रूस ने इसकी समय सीमा तीन साल रखी थी, लगे 13 साल। चीन ने स्माल रिएक्टर बनाने के लिए समय चार साल रखा था, परंतु 12 साल लग गए। अर्जेंटीना ने इसके शोध और निर्माण के लिए चार साल रखे थे, लेकिन यह 13वां साल चल रहा है और अभी भी विकास का काम पूरा नहीं हुआ है। अमेरिकी फ्लोटिंग रिएक्टर चार साल निर्माणाधीन रहा, बाद में लागत में अत्यधिक वृद्धि होते जाने से कंपनी ने 2022 में सौदा रद कर दिया। वह अब 2035 की समय सीमा के साथ दोबारा प्रयासरत है।

आइईईएफए का कहना है कि बिजली उत्पादन के मात्रात्मक दावे भी सही हों, जरूरी नहीं। ऐसे में अप्रत्याशित लागत और निर्माण में असाधारण देरी एवं उत्पादित बिजली के अव्यावहारिक दाम की समस्या की बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों के अनुसार एसएमआर तकनीक काफी नई और अप्रमाणित है, इसलिए कार्यक्षमता और सुरक्षा के मामले में भी जोखिम मौजूद हो सकते हैं। इसके संचालन, कार्यकाल पूरा होने के बाद इसके निपटारे, संयंत्र की सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन में कितना खर्चा आएगा, क्या कैसे करना होगा इस बाबत अभी बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। सरकार की सदिच्छा में कोई खामी नहीं है, परंतु उसे इस योजना पर पूरी तरह आगे बढ़ने से पहले इसे गहन अध्ययन और शोध के निष्कर्ष पर परखना होगा। उम्मीद है कि जब तक वह सक्रिय होगी, तकनीकी विकास ये सारी दिक्कतें दूर कर चुका होगा। (ईआरसी)

दवा विकास की प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन

राजकुमार जैन
तकनीकी मामलों के जानकार

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विकसित हो रहा है। जिससे विज्ञान कथा और वास्तविकता के मध्य दिखाई पड़ने वाला अंतर धुंधला रहा है। तकनीक का उद्भव वैश्विक औद्योगिक परिदृश्य और जीवनशैली को तेजी से बदल रहा है। ऐसे में क्वांटम कंप्यूटिंग और एआइ का संयोजन क्वांटम एनलार्ज्ड एआइ (क्यूएआइ) नवाचार के एक ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में उभर रहा है जिसे पहले लगभग असंभव समझा जा रहा था। वस्तुतः क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके जानकारी को अविश्वसनीय गति से संसाधित करती है। यह तकनीक पारंपरिक कंप्यूटरों से मौलिक रूप से अलग है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के क्यूबिट में इलेक्ट्रान या फोटान जैसे उप-परमाणु कणों का उपयोग किया जाता है। इन क्यूबिट्स में अवस्थाओं के रैखिक संयोजन यानी सुपरपोजिशन के माध्यम से एक साथ कई अवस्थाओं में रहने की अनूठी क्षमता होती है। यह विशेषता क्वांटम कंप्यूटरों को समानांतर रूप से बहुत अधिक मात्रा में जानकारी संभालने की दक्षता देती है। इस विशेषता से वह अपार कंप्यूटिंग शक्ति हासिल होती है जो इन्हें बेजोड़ प्रसंस्करण क्षमता और दक्षता प्रदान करती है।

मशीन लर्निंग के ऐसे अनुप्रयोगों जैसे आणविक माडलिंग, क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा तथा एआइ में अनुकूलन आदि में बड़े-बड़े डेटासेट का उपयोग होता है, उनके विश्लेषण में क्वांटम एआइ विशेष रूप से उपयोगी है। क्वांटम एआइ बड़े डेटासेट का उपयोग करके तस्वीर और आवाज पहचान के लिए न्यूरल नेटवर्क को प्रचलित एआइ के लिए लगने वाले समय के एक अंश मात्र में प्रशिक्षित कर सकता है, जिससे पहले से अधिक सटीक परिणाम हासिल करना संभव होता है। जैसे-जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और एआइ तकनीकें विकसित होंगी, मानव जीवन को प्रभावित करने वाली उन समस्याओं का समाधान करने में भी हम सक्षम होंगे, जो पहले अबूझ मानी जाती थीं। क्यूएआइ के संभावित अनुप्रयोगों में शामिल हैं, व्यक्तिगत चिकित्सा में क्रांति लाना, साइबर सुरक्षा में सुधार करना आदि।

वर्तमान में दवा को विकसित करना महंगा प्रयास है, जिसमें एक दवा को प्रयोगशाला से फार्मेसी तक लाने में औसतन 12 साल और अरबों रुपये का खर्चा लगता है। क्यूएआइ औषधि तलाश में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। दवा के विकास में विज्ञानी सिमुलेशन का उपयोग इस तथ्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए करते हैं कि प्रोटीन जैसे कुछ जैव अणु संभावित दवा के किसी नए यौगिक के साथ किस तरह परस्पर क्रिया करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग किसी पूर्व उपलब्ध जानकारी के बिना भी बड़े अणुओं और यौगिकों की परस्पर क्रियाओं को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में अधिक तेजी और सटीकता से सिम्युलेट कर सकता है जिससे दवा विकास के समय और लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। व्यक्तिगत चिकित्सा में क्यूएआइ विशाल जेनेटिक और क्लिनिकल डेटा को विश्लेषित कर सकता है, ताकि रोगियों के लिए व्यक्तिगत उपचार तैयार किए जा सकें, उनकी प्रभावशीलता में सुधार हो और दुष्प्रभाव कम हो।

क्वांटम हार्डवेयर, त्रुटि सुधार और एल्गोरिदम विकास में चल रही प्रगति से एआइ व कंप्यूटेशनल क्षमताओं में नई सीमाओं के खुलने की उम्मीद है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र विकसित होता है, क्वांटम एआइ कंप्यूटेशन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। वैसे क्यूएआइ के विकास में कई चुनौतियां भी हैं, जिनमें क्वांटम कंप्यूटरों की स्थिरता और स्केलेबिलिटी शामिल हैं। इसके अलावा, क्यूएआइ के नैतिक और सामाजिक पहलुओं को समझना और उनके समाधान प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण होगा।

खरी-खरी

मोरे अंगना आओ रे बदरा...

प्रभुनाथ शुक्ल

पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार) में आजकल बादल नाराज हैं। सूरज और बादलों के बेमेल गठजोड़ ने सावन और किसानों की सत्ता हिलाकर रख दिया है। किसानों के चेहरे पर जहां हवाइयां उड़ रही है, वहीं खेतों में झुर्रियां पड़ गई हैं। जमीन में मोटी-मोटी दरारें पड़ गई हैं। सावन प्यासा है और हांफ रहा है। खेत-खलिहान में हरियाली गायब है। धुल उड़ रही है। धान की फसल सूख गई है। धरती पर हरियाली का नाम नहीं है। हर तरफ सूखा नजर आ रहा है। मदमस्त सावन जैसे कुंवारे में ही बूढ़ा हो चला है। उसके हाथों में जैसे किसी ने लाठी पकड़ा दी हो और वह बीमार सा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।

पूर्वांचल में बादलों और सूरज के गठजोड़ से धरती और सावन का सारा फागुन गायब हो चला है। नदियां, पोखर, ताल-तलैया सब सूखे पड़े हैं। कहीं भी बूंद भर पानी नहीं दिख रहा है। सबका दिल जल रहा है, लेकिन कोई प्यास बुझाने वाला नहीं है। हर तरफ बिरह का गान है। सुक्खू, कालू, रामू और बलिराम काका का बुरा हाल है। खेतों में लगी धान की फसल रात-दिन रट लगाए है- मेघा रे मेघा रे.. पानी दे पानी दे...। सावन, धान, किसान सब पानी-पानी पुकार रहे हैं। लेकिन बादल, सावन और उन बेगुनाह किसानों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं।

सावन उदास है, जैसे उसका प्रियतम बादल, रेगिस्तान में जा बसा है और एकदम नीरस हो गया है और वह सावन की बेकरारी नहीं समझ रहा है। गांवों में झूले नहीं दिख रहे हैं। सूरज इतना आग उगल रहा है कि जेठ के नौतपा को उसने मात दे दी है। बेचारा सावन, बारिश में भीगने को बेताब है, लेकिन उसकी बेताबी प्रेमी बादल नहीं समझ रहे हैं। सावन, बरसात में भीगने के बजाय पसीने से भीग रहा है। पूरे शरीर और माथे से पसीना टपक रहा है। वह तो बस! पिया-पिया रट रहा है, लेकिन हरजाई बादल उसकी बेकरारी को सुनने से रहे। उदास सावन पुरवाई पवन के जरिए अपनी पीड़ा बादलों तक भेजना चाहता है, लेकिन निर्मोही बादल जब उसकी पीड़ा को समझें तब न।

पोस्ट

ईरान ने यह स्वीकार किया है कि हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या हो गई है। इसे कहते हैं 'घर में घुसकर मारना।'
सुशांत सरीन@sushantsareen

कांग्रेस ने 1991 में मुलायम सिंह यादव के सामने समर्पण किया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में उसकी हैसियत घटती गई। दिल्ली में उसने 'आप' के साथ यही करने की कोशिश की और अब बंगाल में उसी रास्ते पर है।
प्रमोद जोशी@pjoshi23

वायनाड में भूस्खलन से सैकड़ों लोग मर गए। चरम मौसमी घटनाओं के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संख्या एवं तीव्रता बढ़ रही है। जीवन अधिक संकटग्रस्त हो रहा है। केरल समेत पूरी पश्चिमी तटरेखा पर लोगों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। इन मुद्दों पर चर्चा की बड़ी जरूरत है।
हृदयेश जोशी@hridayeshjoshi

सरकारी नौकरी की तैयारी कराने वाले सभी निजी कोचिंग सेंटरों में स्किल डेवलपमेंट की कोचिंग अनिवार्य कराई जाए। साथ ही निजी क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से भी एक कोर्स डिजाइन कराना चाहिए, ताकि वहां पढ़ने वालों के लिए निजी क्षेत्र में भी नौकरी पाने में आसानी रहे।
सत्या चौधरी@satyagodara

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या संसद में बजट पर हो रही चर्चा सार्थक है?

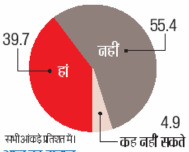

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को बंगाल के अध्यक्ष पद से हटाकर सही किया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पूछा करते चीखकर वे औरों की जात,
अपनी पर आ जाय तो लगता है आघात।
लगता है आघात समझ बैठें वह गाली,
करें जरा वह याद बात अपनी ही वाली।
क्यों औरों की बात आप यूं दिल पर धरते,
जब औरों की जात आप खुद पूछा करते!
- ओमप्रकाश तिवारी

संजय मिश्र
स्थानीय संपादक, नवदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश डायरी

औद्योगिक उड़ान के लिए तैयार हो रहा प्रदेश

प्राकृतिक सौंदर्य के साथ उन्नत कृषि के कारण मध्य प्रदेश की पहचान पूरे देश में है। यह असाधारण है कि किसानों के नवाचार और सरकार के सहयोग से कई उपजों में प्रदेश ने देश में पहला या दूसरा स्थान अर्जित किया है। वर्ष 2020-21 में तो गेहूं उत्पादन एवं खरीद में पंजाब को पीछे छोड़ चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार का मजबूत आधार अभी तक कृषि ही है। हालांकि जिस तरह शहरीकरण बढ़ रहा है, उससे अन्य क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने की जरूरत भी महसूस होने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक संरचना मजबूत करना समय की मांग है। इस दिशा में सरकार की ओर से पहले भी प्रयास हुए, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने तो इंदौर में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कान्क्लेव आयोजित कर औद्योगीकरण की दिशा में प्रदेश के आगे बढ़ने की आधारशिला रखी थी। डा. मोहन यादव की सरकार ने इस कड़ी को आगे बढ़ाया है। यही कारण है कि प्रदेश औद्योगिक विकास के माध्यम से नई उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। उद्योग जगत की अपेक्षा के अनुरूप नीतियों को संशोधित करने के साथ मोहन सरकार अंचलवार औद्योगिक विकास पर फोकस कर रही है। उज्जैन और जबलपुर में कान्क्लेव आयोजित कर सरकार ने उद्योगपतियों को योजनाओं से आकर्षित किया है।

दरअसल, अभी तक सारे बड़े आयोजन प्रदेश के सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्र इंदौर तक सीमित होते थे। यही कारण है कि औद्योगिक घरानों का फोकस भी इंदौर और आसपास के क्षेत्रों तक ही अधिक रहता था। इससे विकास भी एक ही क्षेत्र में अधिक हुआ। इस असमानता को दूर करने का बीड़ा मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने उठाया है। उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव की शुरूआत उज्जैन से की। इस आयोजन को उम्मीद से अधिक समर्थन मिला। अनेक बड़े उद्यमी अपनी योजनाओं के साथ पहुंचे और निवेश की घोषणा की। जबलपुर में भी यह आयोजन हो चुका है। ग्वालियर में 28 अगस्त को उद्योगपतियों को बुलाकर निवेश की संभावनाओं पर काम किया जाएगा। इसके बाद रीवा में भी इसी तरह की कवायद होगी। निश्चित तौर पर सरकार का यह कदम क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में मददगार बनने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का बड़ा माध्यम बनेगा।

जबलपुर में इंडस्ट्री कान्क्लेव के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते डा. मोहन यादव। फाइल

राज्य में आर्थिक गतिविधियों के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास बहुत ही जरूरी है। प्रदेश में भूमि, जल, बिजली और प्रचुर मानव संसाधन की उपलब्धता के साथ शांति का वातावरण कई प्रदेशों से बेहतर है। इसके बावजूद जिस तरह से उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई। पूर्व में बड़े-बड़े आयोजनों में देश के शीर्ष उद्योगपति भी आए और लाखों करोड़ रुपये के निवेश के दावे भी किए, पर धरातल पर कोई बड़ी उपलब्धि नहीं उतर पाई। इसके लिए कुछ कमियां शासन की ओर से भी रह गईं। अब मोहन सरकार ने दृष्टिकोण बदलने का संकेत दिया है। लिहाजा पहले ही आयोजन में लगभग एक लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिल गए। ये प्रस्ताव मूर्त रूप लेते हैं तो इनसे एक लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

उद्योगपतियों की ओर से मिल रहे सकारात्मक संकेत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मोर्चा मुख्यमंत्री ने स्वयं संभाला है। अलग-अलग प्रांतों में जाकर उद्योगपतियों से न केवल संवाद किया जा रहा है, बल्कि रोड शो के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने की मुहिम छेड़ दी गई है। पिछले दिनों मुंबई में इंडस्ट्री कान्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 75 हजार करोड़ रुपये के निवेश आने की संभावना बनी, जिससे एक लाख से ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने 50 हजार करोड़ रुपये, ग्रासिम इंडस्ट्री ने चार हजार करोड़ रुपये, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने 450 करोड़ रुपये, महिंद्रा हालिडे ने 750 करोड़ रुपये और ओबेराय होटल समूह ने 400 करोड़ रुपये निवेश का वादा किया है।

जबलपुर में हुई आंचलिक कान्क्लेव में 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र जारी किए गए। इन इकाइयों द्वारा 1,800 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिससे 12 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश के बाहर मुंबई के बाद कोयंबटूर में दूसरा रोड शो भी किया गया। इसमें 3500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयंबटूर में प्रदेश का उद्योग कार्यालय खोलने की घोषणा की गई। हालांकि चुनौती यह भी होगी कि जो निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं, सरकार उन्हें सामयिक ढंग से जमीन पर कैसे उतारती है। ये निवेश प्रस्ताव यदि जमीन पर उतर जाते हैं, तो न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गति आएगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे।

मंथन

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
चेयर प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा, पंजाब

शिक्षा में सुधार की चिंता

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति सरकार निरंतर प्रयासरत है। धरातल पर भी इसे महसूस किया जा सके, इसके लिए शीर्ष स्तर पर भी चिंता की जा रही है, लिहाजा इसके परिणाम सुखद रहेंगे

प्रतीकात्मक

हमारा देश तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर है। हर क्षेत्र में देश नए प्रतिमान गढ़ रहा है। आम बजट में वित्त मंत्री ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रविधान किया है। सरकार के समग्र प्रयासों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 अब भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था में प्रसार पा रही है। भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान के विस्तार के लिए पुरजोर प्रयास हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के स्तर में पिछले एक दशक में व्यापक सुधार हुए हैं। एक दशक पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के केवल नौ शिक्षा संस्थान थे, आज इनकी संख्या 50 के आसपास पहुंच गई है। निश्चित रूप से भारत की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पालिसी ने भारत के युवाओं के सपनों का विस्तार दिया है। भारत के विश्वविद्यालयों ने विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी शुरू कर दी है।

गांधी की वैचारिकी का उद्धरण : ऐसे समय में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने यह आह्वान किया है कि ज्ञान समाज और देश के विकास के लिए होने चाहिए। वह अपने भारतीय भविष्य को सहेजना चाहती हैं। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हमारे विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों से उपाधि धारित जिज्ञासा और मानवता को बनाए रखें। वस्तुतः राष्ट्रपति को दयाहीन विज्ञान से भय है, इसलिए उन्होंने गांधी को स्मरण किया। राष्ट्रपति ने गांधी की वैचारिकी का भी उद्धरण दिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने सात सामाजिक पाप परिभाषित किए हैं जिनमें से एक है दयाहीन विज्ञान। यानी मानवता के प्रति संवेदनशीलता से रहित विज्ञान को बढ़ावा देना पाप कर्म करने जैसा है। उनका यह स्पष्ट संदेश हमें सदैव याद रखना चाहिए।

वस्तुतः राष्ट्रपति इस प्रकार की अपील इसलिए कर रही थीं, क्योंकि जिस प्रकार से शैक्षणिक व्यवस्था से मशीनीकृत दिमाग की पीढ़ी तैयार हो रही है, वह भारत के भविष्य को कभी सुंदर नहीं बना सकती है। वह सुंदर तभी बनेगी, जब उनमें मानवता के बीज अंकुरित होते रहेंगे और वे मुरझाएंगे नहीं। सार्थक विद्या एवं ज्ञान वही है, जिसका प्रयोग मानवता की बेहतरी एवं उत्थान के लिए हो। इसे इतना गंभीर होने की इसलिए आवश्यकता है, क्योंकि उनके संपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ यह विश्वास जताना कि मुझे आशा है कि विज्ञान शिक्षा से जुड़े आप जैसे सभी लोग एवं नीति-निर्मातागण मिलकर इन सभी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि मानवता, अनुसंधान एवं विकास का अधिक से अधिक लाभ उठा सके और उसे कोई हानि न पहुंचे, यह स्वयं में उनके व्यापक चिंतन से निकली अभिव्यक्ति है जिस पर वह सभी वैज्ञानिक नवोदितों को संदेश देती हैं कि हमारे जीवन के आधार मानवता की डोर को बांधकर रखें।

मानवता के समक्ष नई चुनौतियां : नैतिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े संकट की चिंता भी राष्ट्रपति की विशेष चिंताओं में शामिल है। राष्ट्रपति का स्पष्ट शब्दों में यह कथन है कि नए-नए तकनीकी विकास मानव समाज को क्षमताएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मानवता के सामने नई चुनौतियां भी पैदा कर रहे हैं। वह यह स्वीकार करती हैं कि तकनीक कई असाध्य बीमारियों के समाधान करने की दिशा में सहयोगी साबित हुई है। परंतु इस तकनीक के प्रयोग के कारण नैतिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े संकट भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसी प्रकार जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रहे विकास से डीप फेक की समस्या तथा अनेक रेगुलेटरी चैलेंसेज यानी नियामकीय चुनौतियां सामने आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि उनके वक्तव्यों में नई पीढ़ी को संभलकर चलने की सलाह है और मनुष्यता से जुड़े रहने की अपील है। वह नहीं चाहतीं कि हमारे छात्र या छात्राएं भ्रम में जीवन जिएं। उन्होंने इसीलिए बहुत साफगोई से यह कहा कि जो नैतिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े संकट हैं या जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समन्वय और संयोजन की समस्याएं हैं, उसे हम हलके में न लें और पूरी सजगता से इस दिशा में हमारी सोच और एक्शन दोनों उभरकर मानवता के लिए प्रेरित होने चाहिए। जो चीजें हमारे लिए खतरा बन सकती हैं, उसे दबाया जाना चाहिए या उससे मुक्ति के उपाय तलाशे जाने चाहिए। इसके साथ ही, शिक्षा में लड़कियों के शैक्षणिक उत्थान के और उनकी संख्या में जो अभिवृद्धि की पहल है, वह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में महिला साक्षरता दर जितनी बढ़ेगी, उतना ही तेजी से भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा।

****

इन्फोसिस को 32,403 करोड़ की जीएसटी मांग का नोटिस

नई दिल्ली: देश की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कंपनी इन्फोसिस को लगभग 32,403 करोड़ रुपये कथित जीएसटी चोरी को लेकर नोटिस मिला है। कंपनी ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी प्राधिकरण ने लगभग 32,403 करोड़ रुपये जीएसटी (माल एवं सेवा कर) भुगतान को लेकर नोटिस दिया है। यह मामला जुलाई, 2017 से मार्च, 2022 के बीच का है। यह इन्फोसिस लिमिटेड के विदेश में स्थित शाखा कार्यालयों के खर्चों से संबंधित है। (प्रेट्र)

भारत 2047 तक 35 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। एयरटेल के पास वृद्धि और व्यापार के नए रास्ते के लिए जबरदस्त अवसर होंगे।
— सुनील मित्तल, चेयरमैन, भारती एयरटेल

सेंसेक्स	81,741.34	285.94
निफ्टी	24,951.15	93.85
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 71,950	₹350
चांदी प्रति किलोग्राम	₹85,600	₹1,100
डालर	₹83.72	₹0.01
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 80.51	

एक नजर में

इंडिया रेटिंग्स ने विकास दर का अनुमान बढ़ा 7.5% किया

नई दिल्ली: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने उपभोग मांग में सुधार की उम्मीद के बीच चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.1 प्रतिशत से बढ़ाकर बुधवार को 7.5 प्रतिशत कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सरकारी पूंजीगत व्यय, कारपोरेट/बैंकों के ऋणमुक्त बहीखाते और निजी कारपोरेट पूंजीगत व्यय चक्र की शुरुआत से जारी वृद्धि गति को केंद्र सरकार के बजट से समर्थन मिला है। (प्रेट्र)

फर्स्टक्राई का आइपीओ छह अगस्त को खुलेगा

नई दिल्ली: आनलाइन ई-कामर्स प्लेटफार्म फर्स्टक्राई की पैरेंट कंपनी ब्रेनबीज साल्यूशंस लिमिटेड छह अगस्त को अपना आइपीओ लांच करेगी। तीन दिन का निर्गम आठ अगस्त को बंद होगा। पुणे स्थित ब्रेनबीज साल्यूशंस के प्रस्तावित निर्गम में 1,666 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर और 5.44 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। (प्रेट्र)

स्मार्टफोन की बिक्री जून तिमाही में दो प्रतिशत घटी

नई दिल्ली: जून तिमाही में तेज गर्मी और सुस्त मांग की वजह से देश में स्मार्टफोन की बिक्री सालाना आधार पर दो प्रतिशत घट गई। शाओमी 23 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ शीर्ष स्थान पर रही। कुल बिक्री में उसकी हिस्सेदारी 18.9 प्रतिशत रही जबकि वीवो 18.8 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रही। मूल्य के मामले में सैमसंग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बाजार में सबसे आगे रही। (प्रेट्र)

मारुति सुजुकी का शुद्ध लाभ 47 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआइ) का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 47 प्रतिशत बढ़कर 3,650 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी ने कहा कि लागत में कटौती के प्रयासों, अनुकूल जिंस कीमतों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ की वजह से उसके मुनाफे में वृद्धि हुई। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,485 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया था। (प्रेट्र)

कोर सेक्टर में वृद्धि 20 माह के निचले स्तर पर

क्रूड व रिफाइनरी प्रोडक्ट का उत्पादन घटने से जून में चार प्रतिशत रही बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वृद्धि दर

- मई, 2024 में कोर सेक्टर की वृद्धि दर 6.4% थी, पिछले साल जून में यह 8.4 प्रतिशत थी
- इससे पहले अक्टूबर, 2022 में वृद्धि दर सबसे कम यानी 0.7 प्रतिशत दर्ज की गई थी

नई दिल्ली, प्रेट्र: कच्चा तेल और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में गिरावट के चलते इस साल जून में आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि 20 महीने के निचले स्तर यानी चार प्रतिशत पर आ गई। मई, 2024 में बुनियादी उद्योगों (कोर सेक्टर) का उत्पादन 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। जून 2023 में कोर सेक्टर यानी कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली की वृद्धि 8.4 प्रतिशत रही थी। इससे पहले अक्टूबर, 2022 में वृद्धि दर सबसे कम यानी 0.7 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में इन प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन 5.7 प्रतिशत बढ़ा जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह छह प्रतिशत बढ़ा था। इन आठ प्रमुख क्षेत्रों का देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में 40.27 प्रतिशत का योगदान है। आइआइपी देश की समग्र औद्योगिक वृद्धि को मापने का एक सूचकांक है। जून में कच्चे तेल और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में क्रमशः (-) 2.6 प्रतिशत और (-) 1.5 प्रतिशत की गिरावट आई। वहीं प्राकृतिक गैस, उर्वरक, इस्पात और सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि दर क्रमशः 3.3 प्रतिशत, 2.4 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत रही। हालांकि, कोयला और बिजली के उत्पादन में क्रमशः 14.8 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

> मई 2024 की तुलना में कोयला, उर्वरक और सीमेंट को छोड़कर आठ घटकों में से पांच में वृद्धि में नरमी या संकुचन गहराने से कोर सेक्टर का विस्तार 20 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। कोर सेक्टर की वृद्धि में गिरावट से जून 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 3.5-5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगा।
>
> **-अदिति नायर,** मुख्य अर्थशास्त्री, इक्रा लिमिटेड

पहली तिमाही में राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष के लक्ष्य का 8.1%

नई दिल्ली, प्रेट्र: 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही के अंत तक केंद्र का राजकोषीय घाटा पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य का 8.1 प्रतिशत रहा है। महालेखा नियंत्रक द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, मूल्य के लिहाज से राजकोषीय घाटा (व्यय और राजस्व के बीच का अंतर) जून के अंत तक 1,35,712 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि में घाटा बजट अनुमान का 25.3 प्रतिशत रहा था। बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.9 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था। कुल मिलाकर सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को 16,85,494 करोड़ रुपये तक सीमित रखना है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले तीन (अप्रैल-जून) महीनों के लिए केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय के आंकड़े साझा करते हुए महालेखा नियंत्रक ने कहा कि शुद्ध कर राजस्व 5,49,633 करोड़ रुपये या चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 21.1 प्रतिशत था। पिछले वित्त वर्ष में जून के अंत तक शुद्ध कर राजस्व संग्रह पूरे साल के लक्ष्य का 18.6 प्रतिशत था। केंद्र सरकार का कुल व्यय पहली तिमाही में 9,69,909 करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 20.4 प्रतिशत रहा। एक साल पहले इसी अवधि में व्यय बजट अनुमान का 23 प्रतिशत से अधिक था।

जीवन व चिकित्सा बीमा प्रीमियम से हटाया जाए जीएसटी : गडकरी

नितिन गडकरी

वित्त मंत्री सीतारमण को लिखा पत्र, बोले-बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीवन एवं चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी हटाने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्री को लिखे पत्र में गडकरी ने नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया, जिसने बीमा उद्योग के मुद्दों के संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था।

ज्ञापन का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा, 'जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। कर्मचारी संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को सुरक्षा देने के लिए, जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को 'कवर' करता है, उससे 'कवर' खरीदने के लिए प्रीमियम पर कर नहीं लेना चाहिए।' उन्होंने कहा कि इसके अलावा कर्मचारी संघ द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा जीवन तथा चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को हटाने से संबंधित है। जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम दोनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी दर लागू है।

उन्होंने कहा, 'इसी प्रकार चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी इस व्यवसाय खंड के विकास में बाधक साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से आवश्यक है।' उन्होंने कहा, 'इसलिए आपसे अनुरोध है कि जीवन तथा चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि नियमों के अनुसार उचित सत्यापन के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बोझिल हो जाएगा।'

लगातार चौथे दिन तेजी से सेंसेक्स व निफ्टी अपने नए उच्चतम स्तर पर

धातु, बिजली और चुनिंदा वाहन कंपनियों के शेयरों में रही तेजी
बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का एमकैप 462 लाख करोड़ हुआ

मुंबई, प्रेट्र: धातु, बिजली और चुनिंदा वाहन कंपनियों के शेयरों में तेजी के दम पर बुधवार को घरेलू शेयर बाजार के दोनों मानक सूचकांक रिकार्ड स्तर पर पहुंच गए।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 285.94 अंक बढ़कर अपने अब तक के उच्चतम 81,741.34 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में सेंसेक्स एक समय 372.64 अंक उछलकर 81,828.04 अंक के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंचा गया था।

एनएसई का सूचकांक निफ्टी 93.85 अंक बढ़कर 24,951.15 अंक के सर्वकालिक उच्चस्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें एक समय 127.3 अंक की बढ़त दर्ज की गई थी। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का पूंजीकरण बढ़कर 462.38 लाख करोड़ हो गया। यह लगातार चौथा सत्र है जब बाजार बढ़त के साथ बंद हुए हैं।

सोना 350 रुपये मजबूत तो चांदी 1,100 रुपये चढ़ी

घरेलू मांग और वैश्विक रुझानों से संकेत लेते हुए बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 350 रुपये बढ़कर 71,950 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले सत्र में यह कीमती धातु 71,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, बुधवार को चांदी 1,100 रुपये बढ़कर 85,600 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले कारोबार में यह 84,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

रोजगार सृजन के लिए सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल करे निजी क्षेत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने बुधवार को कहा कि भारत के निजी क्षेत्र को अगले दशक में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार की हाल में घोषित योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। इनमें सबसे पहले रोजगार के लिए नई नौकरियां सृजित करना और नई नियुक्तियां शामिल है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (एमएंडएम) की एजीएम में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने दोहराया कि वृद्धि और समृद्धि रोजगार सृजन से प्रेरित होनी चाहिए। यह निजी क्षेत्र और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है तथा रोजगार सृजन के लिए व्यापक प्रयास आवश्यक है। रोजगार तथा कौशल बढ़ाना प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2024-25 बजट भाषण में जोर दिया है।

आज से बदल जाएंगे कई नियम, जेब पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली, जेएनएन : गुरुवार यानी एक अगस्त से फास्टैग और आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित कई नियम बदलने जा रहे हैं। इसका सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ेगा। जिन नियमों में बदलाव हो रहा है, उसमें गूगल मैप, फास्टैग और आइटीआर शामिल हैं। ऐसे में आपके लिए इन बदलाव को जानना जरूरी है, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

फास्टैग केवाईसी अनिवार्य होगा

एक अगस्त से देशभर में फास्टैग के नए नियम लागू हो रहे हैं। ऐसे में वाहन चालक के लिए एक अगस्त से फास्टैग केवाईसी अनिवार्य होगा। नए नियम के तहत तीन से पांच साल पुराने फास्टैग हैं, तो आपको केवाईसी अपडेट कराना होगा। वहीं पांच साल से ज्यादा पुराने फास्टैग को 31 अक्टूबर से पहले तक बदलना होगा।

अब आइटीआर दाखिल करने पर देनी होगी पेनाल्टी

बुधवार को आयकर रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन था। अगर आप आइटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो एक अगस्त, 2024 से अर्थदंड देना होगा। नियम के मुताबिक पांच लाख से कम आमदनी वाले को एक अगस्त के बाद 1000 रुपये पेनाल्टी देनी होगी। साथ ही 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव

एचडीएफसी ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में एक अगस्त से बदलाव करने का एलान किया है। अब एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिये पेमेंट करने से लेकर क्रेड, चेक, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज जैसे थर्ड पार्टी एप के इस्तेमाल करने पर आपको ट्रांजेक्शन राशि पर एक प्रतिशत देना होगा। इसकी सीमा 3000 रुपये तक तय की गई है। वहीं, 15000 रुपये से अधिक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर एक प्रतिशत सर्विस चार्ज देना होगा। टाटा न्यू इनफिनिटी और टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड के नियम में भी बदलाव किया है।

गूगल मैप की सेवाएं हुई सस्ती

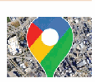

गगूल मैप की तरफ से बिलिंग पॉलिसी में बदलाव किया गया है, नए बदलाव के बाद गूगल मैप की तरफ से भारतीयों के लिए लगने वाले चार्ज में 70 फीसद की कटौती की गई है। इतना ही नहीं, गूगल मैप ने अपनी फीस को डॉलर की जगह में भारतीय रुपये में लेने का वादा किया है। गूगल मैप की फीस में कटौती का असर आम यूजर्स पर देखने को नहीं मिलेगा। यह उन यूजर्स पर लगेगा, जो बिजनेस के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं।

अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

अगस्त में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे। इसमें जन्माष्टमी से लेकर स्वतंत्रता दिवस तक की छुट्टी शामिल है। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो एक बार छुट्टियों की लिस्ट को देखकर ही काम पर निकलें।

राष्ट्रीय फलक

किसानों को हिरासत में लेकर शुरू कराया पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा

जागरण संवाददाता लुधियाना

- हाई कोर्ट के आदेश पर डेढ़ महीने बाद खुलवाया गया लाडोवाल टोल प्लाजा
- विरोध कर रहे 11 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर बाद में छोड़ा

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर पंजाब सरकार ने बुधवार को लाडोवाल टोल प्लाजा खुलवा दिया। विरोध कर रहे 11 किसानों को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया गया। अब यहां से गुजरने वाले वाहनों को टोल देकर गुजरना पड़ रहा है।

पंजाब के इस सबसे महंगे टोल प्लाजा के डेढ़ माह तक बंद रहने के कारण नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) को लगभग 133 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। किसानों के विरोध को देखते हुए ऐहतियातन टोल प्लाजा पर पुलिस बल को तैनात रखा गया है। किसान नेताओं ने भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर गुरुवार को बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए याचिका दायर की जाएगी। टोल प्लाजा शुरू होने के बाद जाम की स्थिति बन गई, क्योंकि ज्यादातर वाहन चालकों ने अपने फास्टैग को रिचार्ज नहीं किया था, जिसकी वजह से टोल कर्मियों के साथ उनकी बहस होती रही। वाहन चालकों को कहना था कि उन्हें पहले बताया जाना चाहिए था ताकि वे अपने फास्टटैग या फिर पास को रिन्यू करा लेते।

लुधियाना में किसान नेता दिलबाग सिंह को हिरासत में लेते पुलिस कर्मी। फोटो जागरण

रैंसमवेयर हमले के कारण कई छोटे बैंकों के ग्राहक प्रभावित

अहमदाबाद, प्रेट्र: प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता (टीसीएस) सी-एज टेक्नोलाजी पर रैंसमवेयर हमले के कारण देशभर में 300 छोटे आकार के बैंकों के ग्राहकों को एटीएम से नकदी निकालने या यूपीआइ का उपयोग करने जैसी भुगतान सेवाओं के लिए परेशानी हुई। अधिकारियों ने कहा कि इसका असर सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों पर पड़ा, जो एसबीआइ और टीसीएस के संयुक्त उद्यम सी-एज पर निर्भर हैं।

अधिकारियों ने कहा कि अन्य बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। सी-एज में पिछले दो दिनों से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी भुगतान प्रणाली की सुरक्षा के लिए सी-एज सिस्टम को अलग करने से लेकर आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी। उन्होंने कहा कि रैंसमवेयर हमले के कारण वित्तीय नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है।

महिलाओं को फंसाने वाला 'लुटेरा दूल्हा' गिरफ्तार

मिड डे, मुंबई

- महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी व राजस्थान की महिलाओं से ठग चुका है गहने
- मेट्रोमोनियल साइटों पर फर्जी अकाउंट से करता था शिकार की तलाश

अमीर तलाकशुदा हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाला एक 'लुटेरा दूल्हा' मुंबई से पकड़ा गया है। 43 वर्षीय फिरोज अहमद नियाज शेख ने पहचान बदल-बदलकर देशभर में अमीर महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया और ठगा है। उसने मेट्रोमोनियल वेबसाइटों पर विनय राजपूत और फिरोज शेख नाम से दो एकाउंट खोले हैं और उन्हीं की मदद से वह तलाकशुदा महिलाओं की तलाश में रहता है।

एक पुलिस अफसर ने बताया कि अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों में फंसाकर उसने महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिलाओं से धोखाधड़ी कर उन्हें लूटा है। और अब वह विदेशी महिलाओं को फंसाने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे धर-दबोचा। मेट्रोमोनियल वेबसाइटों पर उसने एक पायलट और आरबीआइ के एक उच्चाधिकारी के रूप में अपनी फर्जी प्रोफाइलें बनाईं। वह जिन महिलाओं को फंसाना चाहता था, उन्हें वह खुद को बहुत अमीर बताता था। उसके साथ ही वह उन्हें किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए होटल में आमंत्रित करता था। जेवरों से लदी महिलाएं जब कार्यक्रम में आने के लिए उसके पास होटल के कमरे में पहुंचती थीं तो वह कुछ बहाना बनाकर उनके कीमती जेवर उतरवा लेता था और उन्हें वाशरूम भेज देता और उसके बाद सारे गहने लेकर चंपत हो जाता।

पुलिस अफसर ने बताया कि वह जेवरों से सजी-धजी महिला जब उससे मिलने आती थीं तो वह उन्हें किराए की कैब में ब्यूटी पार्लर ले जाता और उनके सभी जेवर उतरवाकर गाड़ी में रख लेता। महिला जैसे ही पार्लर जाती वह गहनों के साथ चंपत हो जाता। जांच अधिकारी पीएसआइ हर्शल राउत ने बताया कि धोखेबाज शेख ने एक महंगी कार खरीदी और विदेशी महिलाओं को लुभाने के लिए मैकबुक भी खरीद ली थी। पूछताछ के दौरान फिरोज ने पुलिस को बताया कि तलाकशुदा महिलाओं को फंसाना उसे आसान पड़ता था, क्योंकि वह भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला शेख फिलहाल नवी मुंबई के बेलापुर में एक महिला के साथ रह रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। ऐसा तब हुआ जब 23 जुलाई को नालासोपारा की एक 38 वर्षीय महिला शेख के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने उसके तौर-तरीकों और पसंद को समझने के बाद एक महिला के फर्जी एकाउंट के जरिये उससे चैट करना शुरू किया। फिर उसे एक दिन कल्याण बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। विरार की पुलिस ने उसके खिलाफ नए मामले तो दर्ज किए ही हैं, जबलपुर की पुलिस ने भी उसके खिलाफ दर्ज छह एफआइआर के सिलसिले में उसकी कस्टडी मांगी है।

आखिरी दिन शाम सात बजे तक 50 लाख से ज्यादा आइटीआर दाखिल

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने के आखिरी दिन बुधवार शाम सात बजे तक सात करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं। अकेले 50 लाख से ज्यादा आइटीआर बुधवार शाम सात बजे तक दाखिल किए गए।

आयकर विभाग ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर यह जानकारी साझा की है। जिन करदाताओं को अपने खातों का आडिट नहीं कराना है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।

उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई, 2023 तक आकलन वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए दाखिल किए गए आइटीआर की कुल संख्या 6.77 करोड़ से अधिक थी। पिछले साल 31 जुलाई, 2023 को 64.33 लाख से अधिक आइटीआर दाखिल किए गए थे।

झारखंड के सरकारी विद्यालय में मुस्लिम शिक्षक ने बच्चों को सरस्वती वंदना से रोका

संवाद सूत्र, जागरण भवनाथपुर (गढ़वा)

- विद्यालय के साउंड सिस्टम भी तोड़ डाले, मना करने पर दूसरे शिक्षक से की धक्का-मुक्की
- वीएचपी ने की शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग, पुलिस ने लिया हिरासत में

झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड की मकरी पंचायत अंतर्गत धंगरडीहा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पदस्थापित सहायक शिक्षक शेख तौहीद ने बुधवार की सुबह विद्यालय में प्रार्थना के दौरान बच्चों को सरस्वती वंदना करने से रोक दी। साउंड सिस्टम भी तोड़ डाले। फिर धार्मिक नारे लगाए। इस दौरान शेख तौहीद और विद्यालय के अन्य शिक्षकों में तीखी नोकझोंक भी हुई।

उत्क्रमित मध्य विद्यालय धंगरडीहा में बुधवार की सुबह प्रार्थना के बाद बच्चे सरस्वती वंदना कर रहे थे। तभी विद्यालय के सहायक शिक्षक शेख तौहीद ने बच्चों से कहा कि मेरे रहते इस विद्यालय में कोई भी हिंदू देवी-देवताओं की वंदना नहीं होगी। जब बच्चे नहीं माने तो उक्त शिक्षक ने सरकारी साउंड सिस्टम को पटक दिया। यह देख विद्यालय के ही सहयोगी शिक्षक निशीथ यादव ने उन्हें यह सब करने से रोकना चाहा तो शिक्षक शेख तौहीद उनसे धक्का मुक्की करते हुए धार्मिक नारे लगाने लगे। मामले को बढ़ता देख विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने इसकी सूचना बीईईओ तथा स्थानीय थाने को दी। विद्यालय में सरस्वती वंदना रोकने की सूचना पर बजरंग दल तथा विहिप सदस्यों ने विद्यालय पहुंचकर आक्रोश जताया। वे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा शिक्षक को अविलंब बर्खास्त करने की मांग करने लगे। अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए थाना प्रभारी कृष्ण कुमार विद्यालय पहुंचे तथा उक्त शिक्षक को हिरासत में लेकर थाना ले आए।

पूर्व में जवानों के बलिदान पर मनाया था जश्न

वर्ष 2017 में पुलवामा में आतंकियों के हमले में जवानों के बलिदान होने पर जश्न मनाने का आरोप शिक्षक शेख तौहीद पर लगा था। उस समय उक्त शिक्षक ने बलिदान जवानों को लेकर आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी थीं। हो-हंगामा के बाद भी उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई थी। साथ ही विद्यालय में प्रायः छात्र-छात्राओं को प्रार्थना एवं सरस्वती वंदना करने से रोकने का प्रयास और सरस्वती पूजा का विरोध करते रहे हैं।

बिहार की जेल में दो माह पूर्व रची गई थी शोरूम लूट की साजिश

जासं, पूर्णिया: पुलिस ने बीते 26 जुलाई को बिहार के तनिष्क शोरूम में हुई तीन करोड़ 70 लाख रुपये के जेवरात की लूट का पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस व एसटीएफ ने उन चार बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने लुटेरों को स्थानीय स्तर पर ठहरने से लेकर अन्य सुविधाएं व रेकी में सहयोग किया था। पुलिस ने बंगाल के मालदा जिले से घटना में इस्तेमाल की गई तीन बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। इस लूट की साजिश दो माह पूर्व ही पटना के बेउर जेल में रची गई थी। यह साजिश पहले बैंक व अब ज्वेलरी की लूट के अंतरराज्यीय सरगना सुबोध सिंह, पूर्णिया के कुख्यात बिट्टू सिंह व सुबोध सिंह के सहयोगी प्रिंस राज ने बेउर जेल में रची थी। स्थानीय स्तर पर घटना को अंजाम देने में बिट्टू सिंह ने अपने गिरोह के जरिये बाहर से आए बदमाशों को सहयोग दिया था।

नौकरी का झांसा देकर सपा नेता ने नाबालिग से किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, अयोध्या

- अयोध्या का यह प्रकरण दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण हिंदू संगठनों ने की नारेबाजी
- सपा सांसद ने मामले से अनभिज्ञता जताई तो भाजपा ने इसे बताया संवेदनहीनता की पराकाष्ठा

अयोध्या में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि सपा नेता मोईद खान ने 12 वर्षीय किशोरी को बेकरी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। बाद में नौकर के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। इस दौरान वीडियो बनाए और इसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देते हुए पीड़िता को चुप करा दिया गया। 27 जुलाई को जब पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है, तब उसने पूरी बात घर वालों को बता दी। इसके बाद स्वजन ने मुकदमा पंजीकृत कराया।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी मोईद खान की गिरफ्तारी नहीं होने से क्षुब्ध लोग विरोध-प्रदर्शन पर उतर आए। प्रकरण दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण हिंदू संगठनों ने नारेबाजी शुरू की। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद लोग शांत हुए।

उधर, इस प्रकरण से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अनभिज्ञता जताई है, जबकि उनके संसदीय क्षेत्र में यह मामला हिंदू जनाक्रोश का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली में एक चैनल को दिए बयान में उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की सच्चाई का पता लगाने के बाद ही वह कुछ कह सकते हैं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडेय बादल ने कहा कि यह सांसद की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आरोपित सपा का पदाधिकारी है, इसलिए वह पूरे मामले से अनभिज्ञ होने का दिखावा कर रहे हैं। यह उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता को भी दर्शाता है।

****

7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों द्वारा हमले के बाद इजरायल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसमें अब तक करीब 40 हजार लोग मारे जा चुके हैं। इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है।

अमेरिका बोला, हानिया की मौत से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा

प्रथम पृष्ठ से आगे

अमेरिका ने हानिया की मारे जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन कहा है कि इजरायल पर हमला होने की स्थिति में वह उसके साथ खड़ा होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री लायड आस्टिन ने कहा है कि हानिया की मौत से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया है लेकिन नया युद्ध अवश्यंभावी नहीं है।

पिछले कई वर्षों से हानिया ने कतर में अपना ठिकाना बना रखा था और वहीं से कूटनीतिक गतिविधियां संचालित करते थे। इसलिए वहीं पर उनके शव के अंतिम संस्कार का निर्णय लिया गया है। सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के हमले की उन्हें पहले से जानकारी थी। हमले के बाद उनका खुशी मनाते और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए का वीडियो सामने आया था। करीब दस महीने से जारी गाजा युद्ध के दौरान बीते अप्रैल में इजरायल के हवाई हमले में हानिया के तीन पुत्र, तीन पौत्र और एक पौत्री मारे गए थे। इस पर विचलित न होते हुए हानिया ने स्वतंत्र फलस्तीन की लड़ाई जारी रखने का एलान किया था। फलस्तीनी प्राधिकार के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिया की हत्या की निंदा की है। शोक में वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों ने बुधवार को सभी तरह की गतिविधियां बंद रखीं।

हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या के विरोध में इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के हेब्रोन में बुधवार को फलस्तीनियों ने मार्च निकाला। रायटर

यरुशलम के हेब्रोन में बुधवार को हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया की हत्या किए जाने के बाद फलस्तीनियों ने प्रदर्शन के साथ आगजनी की। इस दौरान जलते टायरों से निकलता धुआं। एएफपी

इस्माइल हानिया की हत्या का विरोध करते हुए वेस्ट बैंक के नब्लस शहर में बुधवार को फलस्तीनियों ने हमास के स्कार्फ और हेडबैंड पहनकर मार्च निकाला। एपी

इजरायल ने हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर को मारा

बेरूत, रायटर : इजरायल ने लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्ला के वरिष्ठ कमांडर फुआद शुकर को हवाई हमले में मार डाला है। कई घंटे की तलाश में मलबे से फुआद का शव मिला है। यह हमला बेरूत के उपनगरीय इलाके में हुआ। हमले में तीन नागरिकों के भी मारे जाने की सूचना है, दर्जनों लोग घायल हैं। यह हमला गोलन पहाड़ी पर 12 नाबालिग इजरायली नागरिकों की हत्या के जवाब में किया गया है। हिजबुल्ला ने इस हमले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है लेकिन कहा है। इस बीच गाजा में जारी इजरायली हमलों में बुधवार को न्यूज चैनल अल-जरीरा के दो पत्रकारों समेत दर्जनों लोग मारे गए हैं। इन्हें मिलाकर सात अक्टूबर, 2023 से जारी इजरायली हमलों में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 39,445 हो गई है।

इजरायल ने ऐसे दी अपने दुश्मनों को खौफनाक मौत

ईरान और बेरूत में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला कमांडर फुआद शुकर की हत्या कर इजरायल ने एक बार फिर साबित किया है कि वह दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने दुश्मनों को निशाना बना सकता है। इजरायल ने फुआद शुकर की हत्या की जिम्मेदारी ली है जबकि हानिया की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का इजरायल का लंबा इतिहास रहा है। उनमें से कुछ मुख्य घटनाओं पर एक नजर...

दुबई के होटल के कमरे में हत्या

2010 में हमास के एक शीर्ष नेता महमूद अल मबौह की हत्या दुबई के एक होटल के कमरे में कर दी गई थी। इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद पर इस आपरेशन को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था। इजरायल ने कभी इस आरोप को स्वीकार नहीं किया।

व्हीलचेयर पर बनाया निशाना

2004 में इजरायली हेलीकाप्टर ने हमास के आध्यात्मिक नेता अहमद यासीन को व्हीलचेयर से गाजा सिटी मस्जिद से बाहर निकलते वक्त निशाना बनाया था। इस हमले में यासीन की मौत हो गई थी। बचपन में एक दुर्घटना में लकवाग्रस्त यासीन 1987 में हमास के संस्थापकों में से एक था। इसके एक महीने से भी कम समय में उसका उत्तराधिकारी अब्देल अजीज भी इजरायली हवाई हमले में मारा गया।

कान के पास उपकरण रख दिया जहर

1997 में मोसाद एजेंटों ने जार्डन के अम्मान में तत्कालीन हमास प्रमुख खालिद मशाल को जहर देकर मारने की कोशिश की। दो एजेंट नकली कनाडाई पासपोर्ट का उपयोग करके जार्डन में दाखिल हुए और मशाल के कान के पास एक उपकरण रखकर उसे जहर दे दिया। घटना के तुरंत बाद एजेंटों को पकड़ लिया गया। इसके बाद अपने एजेंटों को छुड़ाने के लिए इजरायल ने एंटीडोट देकर मशाल की जान बचाई।

कार में रखा बम

2008 में सीरिया के दमिश्क में हिजबुल्ला के सैन्य प्रमुख इमाद मुगनीह की कार में बम रख उसे मार दिया गया था। हिजबुल्ला ने इस हत्या का आरोप इजरायल पर लगाया था।

फोन का जवाब देते ही मौत

1996 में हमास के याह्या अय्याश की मौत एक फोन का जवाब देते ही हो गई थी। अय्याश को हमास के लिए बम बनाने में महारत हासिल थी। इसलिए उसे इंजीनियर उपनाम दिया गया था।

म्यूनिख ओलिंपिक हत्याकांड का लिया बदला

1973 में इजरायली कमांडो ने एहुद बराक के नेतृत्व में एक रात की छापेमारी में बेरूत में एक अपार्टमेंट में फलस्तीन लिबरेशन आर्गनाइजेशन (पीएलओ) के कई नेताओं को गोली मार दी थी। यह आपरेशन 1972 के म्यूनिख ओलिंपिक में 11 इजरायली कोचों और एथलीटों की हत्याओं के प्रतिशोध में किया गया था। बाद में एहुद बराक इजरायल के प्रधानमंत्री बने। (स्रोत : एपी)

बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी फिर सड़कों पर उतरे, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे

छात्रों के घायल होने और पुलिस की ओर से हिरासत में लिए जाने की सूचना

हाल की हिंसक झड़पों में हुई मौतों और गिरफ्तारियों के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन

ढाका, रायटर : बांग्लादेश में बुधवार को प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतर आए। वे हाल ही में आरक्षण के विरोध के दौरान हुई हिंसक झड़पों में मारे गए लोगों और गिरफ्तारियों के खिलाफ रोष जता रहे थे। उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और स्टन ग्रेनेड का प्रयोग किया। पुलिस ने कहा, पूर्वोत्तर सिलहट में प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर अदालतों की ओर जाने लगे, तो बल प्रयोग करना पड़ा। मार्च का आह्वान स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन समूह द्वारा किया गया था। यह संगठन आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन में सबसे आगे था।

क्षेत्रीय उपायुक्त अजबहार अली शेख ने कहा कि हमने प्रदर्शनकारियों से सड़क से हटने का अनुरोध किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने हटने के बजाय पुलिस पर हमला बोल दिया। स्थानीय मीडिया ने कहा कि ढाका और चटगांव समेत कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। हताहतों की संख्या स्पष्ट नहीं है, हालांकि कुछ छात्रों के घायल होने और हिरासत में लिए जाने की खबर है।

- स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन समूह ने किया था मार्च का आह्वान
- हाल में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन में 150 की हुई थी मौत

बांग्लादेश में हाल ही में हिंसा में मारे गए और गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए न्याय की मांग करते हुए बुधवार को ढाका स्थित उच्च न्यायालय के बाहर मार्च में शामिल लोगों की भारी भीड़। एएफपी

हाल ही में बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान 150 लोगों की मौत हो गई थी। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकांश कोटा रद करने के बाद छात्र विरोध बंद करने पर सहमत हुए थे। हालांकि, हिंसक झड़पों के दौरान मौतों और गिरफ्तारियों के खिलाफ बुधवार को वह एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। आंदोलन के समन्वयक मोहम्मद माहिन सरकार कहा, ''हम हिंसा की संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग करेंगे।''

अंतरराष्ट्रीय अधिकार समूहों ने झड़पों में शामिल होने और सरकारी संपत्ति को नष्ट करने के आरोप में करीब 10,000 गिरफ्तारियों की निंदा की है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय निकायों से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा, ''हम उचित जांच करने और जिम्मेदार लोगों के लिए सजा सुनिश्चित करने में उनकी सहायता चाहते हैं।'' साथ ही भारतीय उच्चायुक्त से कहा कि हाल के कोटा सुधार आंदोलन के दौरान ''अराजकतावादियों'' ने बांग्लादेश में श्रीलंका जैसी तबाही मचाने और सरकार गिराने की कोशिश की थी। इस बीच, यूरोपीय संघ ने बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए व्यापार, आर्थिक और विकास संबंधों को बेहतर बनाने के लिए नए सहयोग समझौते पर ढाका के साथ बातचीत स्थगित कर दी है।

भारत में हमले की नई साजिश रच रहा आइएस : यूएन रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में आतंकी संगठन आइएसआइएल-के की भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की नई जानकारी सामने आई है। कहा गया है कि भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला करने में विफल रहा इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट-खुरासान (आइएसआइएल-के) भारतीय आकाओं की मदद से संगठन में ऐसे लोगों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले हमले को अंजाम दे सकें।

संयुक्त राष्ट्र की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मानिटरिंग टीम ने आइएसआइएल (दाएश), अलकायदा और उससे जुड़े लोगों और संस्थाओं को लेकर 34वीं रिपोर्ट मंगलवार को जारी की है। इसमें सदस्य देशों द्वारा इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि अफगानिस्तान से आए आतंकी क्षेत्र में असुरक्षा का कारण बन सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइएसआइएल-के ने उर्दू में एक बुकलेट जारी की है जिसमें भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच दुश्मनी को बढ़ाचढ़ा कर पेश किया गया है। इससे भारत को लेकर उसकी रणनीति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), तालिबान और अलकायदा इन दि इंडियन सबकांटिनेंट (एक्यूआइएस) के बीच लगातार सहयोग बढ़ रहा है। वे अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शिविरों के जरिये साझेदारी कर तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान (टीजेपी) के बैनर तले घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह ये पाकिस्तान के साथ-साथ भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के लिए खतरा बढ़ा सकते हैं।

- कहा, आइएसआइएल-के ऐसे लोगों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले हमले कर सकें
- आतंकी संगठन ने बुकलेट में भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच बढ़ाचढ़ा कर पेश की दुश्मनी

अनुमान के अनुसार, आइएसआइएल-के लड़ाकों की संख्या चार हजार से बढ़कर छह हजार हो चुकी है। वहीं, टीटीपी में छह हजार से साढ़े छह हजार लड़ाके हैं।

इमरान खान ने की सेना से सशर्त वार्ता की पेशकश

इस्लामाबाद, रायटर : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना के साथ सशर्त बातचीत की पेशकश की है। ज्ञात हो इमरान पिछले अगस्त से जेल में बंद हैं। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि वह सेना के साथ क्या बातचीत करना चाहते हैं।

इमरान के आधिकारिक एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में अपनी शर्तों में कहा गया है कि देश में स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव और उनके समर्थकों के खिलाफ लगाए गए झूठे आरोप वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा है कि वह कठपुतली सरकार से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने किसी भी वार्ता में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए करीबी राजनीतिक सहयोगी और सेना के आलोचक महमूद खान अचकजई को नियुक्त किया है। इमरान खान के आफर के जवाब में सेना की ओर से सात मई का एक वीडियो साझा किया गया है। वीडियो में मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी ऐसी राजनीतिक विचारधारा, नेता या राजनीतिक समूह के साथ बातचीत नहीं की जा सकती जो अपनी ही सेना पर हमलों में शामिल है।

रूस ने शुरू किया तीसरे चरण का सामरिक परमाणु हथियारों का अभ्यास

मास्को, एपी: यूक्रेन के पक्ष में पश्चिमी गोलबंदी के बीच रूस ने बुधवार को तीसरे चरण का सामरिक परमाणु हथियारों का अभ्यास शुरू कर दिया। इस युद्धाभ्यास के जरिये क्रेमलिन पश्चिमी बलों के यूक्रेन के समर्थन को सीमित करने का संदेश देना चाहता है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य नाटो देशों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी देना है। हालांकि, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य युद्ध अभियानों के लिए सैनिकों की तैयारी बनाए रखना है।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सैन्य अभ्यास का उद्देश्य इस्कंदर मिसाइलों के साथ मध्य और दक्षिणी जिलों की सेना की एकता को दर्शाना है। वे भंडारण से परमाणु हथियार प्राप्त करने और उन्हें लक्षित प्रक्षेपण क्षेत्रों में तैनात करने का अभ्यास करेंगे। युद्धाभ्यास में वायुसेना की इकाइयां भी शामिल होंगी जो अपने युद्धक विमानों को परमाणु हथियारों से लैस करेंगी और गश्ती उड़ानें संचालित करेंगी।

- युद्धाभ्यास के जरिये यूक्रेन का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों को संदेश
- रूस ने बताया, युद्ध अभियानों के लिए सैनिकों की तैयारी बनाए रखना उद्देश्य

सामरिक परमाणु हथियारों में बम, कम दूरी की मिसाइलों के लिए हथियार और तोपखाने के हथियार शामिल हैं। इससे पहले दो चरणों में मई और जून में युद्ध अभ्यास आयोजित किए गए थे। इसमें जून में उसकी सेनाओं ने सहयोगी देश बेलारूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। इस बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले वालंटियरों का अग्रिम भुगतान दोगुना करने की घोषणा की।

यूक्रेन ने विफल किया रूस का बड़ा हमला, मार गिराए 89 ड्रोन

यूक्रेन की वायुसेना ने बुधवार को कहा कि उसने रूस के सबसे बड़े हमलों में से एक को विफल कर दिया है। कहा, कीव और उसके आसपास के क्षेत्रों को लक्ष्य कर रात में लंबी दूरी के 89 ड्रोन लांच किए गए, लेकिन उसने सभी को नष्ट कर दिया। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है।

सैन्य जासूसी एजेंसी के प्रवक्ता एंडी युसोव ने टेलीविजन पर दी गई अपनी टिप्पणी में कहा कि रूस द्वारा लांच ड्रोनों में अधिक संख्या पहले प्रयोग किए गए ड्रोनों की थी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया के तमाम देश यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में हैं। उन्होंने यूक्रेनी जनता के साथ अपना समथर्न जताने के साथ ही उसकी सेना को युद्ध के लिए अत्याधुनिक हथियार और अन्य सैन्य साजोसामान दिया है। साथ ही आर्थिक रूप से भी करोड़ों डालर की मदद प्रदान की है।

इसके साथ ही रूस को आर्थिक रूप से भी चोट पहुंचाने के लिए तमाम कदम उठाए हैं। इसके तहत रूस के अन्य और तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाया है। रूस की विदेशी बैंकों में जमा धनराशि को भी जब्त कर लिया है।

ब्रिटेन में बच्चियों की हत्या के बाद भीड़ हुई हिंसक, मस्जिद पर बोला हमला

लंदन, प्रेट्र: इंटरनेट मीडिया पर तीन बच्चियों की हत्या के आरोप में हिरासत में लिए गए किशोर के मुस्लिम समुदाय से होने की बात प्रसारित होने के बाद ब्रिटेन में मंगलवार को भीड़ हिंसक हो उठी। सोमवार को चाकू मारकर बच्चियों की हत्या कर दी गई थी। उग्र भीड़ ने उत्तर पश्चिम ब्रिटेन में एक मस्जिद पर हमला बोल दिया। उस पर ईंटे फेंकी गईं। हिंसक झड़प में 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस का मानना है कि इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे दक्षिणपंथी समूह इंग्लिश डिफेंस लीग का हाथ है। किंग चार्ल्स ने कहा है कि बच्चियों के खोने के गम को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।

हार्ट स्ट्रीट स्थित डांस स्टूडियो में 17 वर्षीय किशोर ने सोमवार को 11 लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला बोला था, जिसमें छह से लेकर नौ वर्ष की आयु की तीन बच्चियों की मौत हो गई थी। घायलों में पांच की हालत गंभीर है। पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से इन्कार किया है। एक अधिकारी ने कहा, हिरासत में मौजूद किशोर के बारे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित संदिग्ध का नाम गलत है और उसका जन्म ब्रिटेन में हुआ है। शरण चाहने का दावा भी गलत है। प्रदर्शनकारी बुधवार को पुलिसकर्मी से उलझ गए। पहचान छुपाने के लिए कुछ ने मास्क लगा रखे थे। उन्होंने पास स्थित एक बगीचे की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया और उन ईंटों से अधिकारियों पर हमला बोल दिया। हमले में कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस के तीन कुत्ते भी घायल हो गए। पुलिस वाहनों व मस्जिद की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मस्जिद पर ईंटें फेंकी गईं। स्थानीय सुविधा स्टोर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस बीच, लिवरपूल क्षेत्र में स्थित मस्जिद ने चाकूबाजी की घटना की निंदा की। साथ ही कहा, कुछ लोग यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह अमानवीय कृत्य मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। वह नफरत फैलाकर अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

- हिंसक झड़पों में 40 पुलिसकर्मी घायल, वाहनों में आग लगाई
- इंटरनेट मीडिया पर हमलावर के मुस्लिम होने की बात हो रही प्रसारित

इंग्लैंड के साउथपोर्ट में साउथपोर्ट इस्लामिक सोसाइटी मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों द्वारा आगजनी किए जाने के बाद सुरक्षा में तैनात पुलिसबल। एएफपी

कमला हैरिस ने ट्रंप को दी बहस की चुनौती

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित प्रत्याशी भारतवंशी कमला हैरिस की लोकप्रियता बढ़ रही है। ताजा सर्वे में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के 42 प्रतिशत समर्थन के मुकाबले कमला को 43 प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं का समर्थन बताया गया है। इससे उत्साहित कमला ने ट्रंप को बहस की चुनौती दी है। कहा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुंह पर कहिए। वहीं, ट्रंप की चुनावी टीम ने हैरिस के विरुद्ध 'खतरनाक रूप से उदारवादी'' विज्ञापन लांच किया गया है।

जार्जिया के अटलांटा शहर में मंगलवार को चुनावी रैली में कमला हैरिस ने कहा, राष्ट्रपति पद की दौड़ में मेरे शामिल होने के बाद चुनाव का माहौल बदल गया है। ट्रंप भी इसे महसूस कर रहे हैं। वह सितंबर की बहस में भाग नहीं लेना चाहते, जबकि पहले वह इसमें शामिल होने की घोषणा कर चुके थे। उन्होंने भीड़ के जोरदार समर्थन के बीच कहा, ट्रंप को प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल होने को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। वह और उनके रनिंग मेट मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अच्छा होगा यदि वह इसे मेरे मुंह पर कहें। रैली में 10 हजार लोगों के शामिल होने का दावा किया गया।

उधर, ताजा सर्वे में कमला की ट्रंप पर बढ़त है। सात स्विंग राज्यों में से छह में उनके समर्थकों में वृद्धि हुई है। मिशिगन, एरिजोना, विसकंसिन और नेवादा में कमला जबकि पेंसिलवेनिया व नार्थ कैरोलिना में ट्रंप आगे हैं। जार्जिया में दोनों बराबर हैं।

- कहा, जो कुछ कहना चाहतें हैं मुंह पर कहें तो बेहतर होगा

ताजा सर्वे में भी कमला अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी से आगे

छह अगस्त को अपने रनिंग मेट का एलान करेंगी कमला

डेमोक्रेट प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा से पहले ही कमला ने 99 प्रतिशत पार्टी डेलीगेट का समर्थन हासिल कर लिया है। कमला की चुनावी टीम ने बताया कि वह अपने रनिंग मेट यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक प्रत्याशी की घोषणा छह अगस्त को पेंसिलवेनिया की रैली में करेंगी। इस दौड़ में सीनेटर मार्क केली, पेंसिलवेनिया के गवर्नर जोश शापिओ व केंटुकी के गवर्नर एंडी बेशियर शामिल हैं।

चीन शुरू करना चाहता है राष्ट्रीय इंटरनेट आइडी प्रणाली

न्यूयार्क टाइम्स से

बीजिंग : चीन में अब आनलाइन पहचान छुपाना मुश्किल होगा। सरकार इसके लिए राष्ट्रीय इंटरनेट आइडी प्रणाली लाने जा रही है। वेबसाइटों और एप यूजर को उनके फोन नंबरों से सत्यापित करना होगा। यह उनके व्यक्तिगत पहचान नंबर से जुड़ा होगा। चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय और चीन के साइबरस्पेस प्रशासन का कहना है कि यह प्रस्ताव गोपनीयता की रक्षा और आनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए है। अब चीन के इंटरनेट नियामकों के एक प्रस्ताव के तहत लोगों को इंटरनेट का उपयोग करने के लिए एक आइडी देना चाहता है।

- वेबसाइटों और एप यूजर को उनके फोन नंबरों से सत्यापित करना होगा

नियामकों ने कहा कि राष्ट्रीय इंटरनेट आइडी इंटरनेट प्लेटफार्मों द्वारा नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने से रोकेगी। प्रस्ताव के अनुसार, वेबसाइटों और एप द्वारा आइडी प्रणाली का उपयोग स्वैच्छिक होगा। चीनी सरकार ने वर्षों से सूचना पर कड़ा नियंत्रण रखा है और वह इंटरनेट पर लोगों के व्यवहार पर बारीकी से नजर रखती है। पिछले कुछ वर्षों में चीन के सबसे बड़े इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म जैसे वीबो, लाइफस्टाइल एप जियाहोंगशु और लघु वीडियो एप डायिन ने अपने पोस्ट में यूजर के स्थान प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है।

****

आज के कार्यक्रम

निशानेबाजी : 50 मीटर थ्री पोजीशन पुरुष क्वालीफिकेशन, दोपहर 12:30 बजे (**ऐश्वर्य प्रताप तोमर, स्वप्निल कुसाले**)

एथलेटिक्स : पुरुष 20 किमी रेस वाक, सुबह 11:00 बजे, **अक्षदीप सिंह, विकास सिंह और परमजीत बिष्ट**

महिला 20 किलोमीटर रेसवाक, सुबह 11 बजे, **प्रियंका गोस्वामी**

गोल्फ : पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 1, दोपहर 12:30 बजे, **गगनजीत भुल्लर, शुभांकर शर्मा**

हाकी : भारत बनाम बेल्जियम, दोपहर 1:30 बजे

मुक्केबाजी : महिला 50 किग्रा प्री क्वार्टर फाइनल, दोपहर 2:30 बजे, **निकहत जरीन बनाम वू यू**

तीरंदाजी : पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा राउंड आफ 32, दोपहर 2:30 बजे, **प्रवीण जाधव बनाम काओ वेंचाओ**

सेलिंग : पुरुष डिंघी रेस 1, दोपहर 3:45 बजे, **विष्णु सरवनन**

● महिला डिंघी रेस 1, शाम 7:05 बजे, **नेत्रा कुमानन**

तालिका

देश	सोना	चांदी	कांस्य	कुल
1 चीन	8	6	2	16
2 जापान	7	2	4	13
3 फ्रांस	6	9	6	21
4 ग्रेट ब्रिटेन	6	6	5	17
5 आस्ट्रेलिया	6	4	3	13
6 द. कोरिया	5	3	3	11
7 अमेरिका	4	12	11	26
8 इटली	3	6	4	13
9 कनाडा	2	2	2	6
10 जर्मनी	2	0	1	3
37 भारत	0	0	2	2

पदक तालिका *रात 9:00 बजे तक

ओलिंपिक में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के **फाइनल में** पहुंचने वाले पहले भारतीय बने स्वप्निल कुसाले, आज पदक पर लगाएंगे निशाना

धौनी से प्रेरित स्वप्निल ने रचा इतिहास

पेरिस, प्रेट्र : भारत के स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलिंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि ऐश्वर्या प्रता सिंह तोमर चूक गए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही कुसाले ने इतिहास रच दिया और वह इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले निशानेबाज बन गए। कुसाले क्वालीफाइंग दौर में 590 का स्कोर करके सातवें स्थान पर रहे, जबकि तोमर 589 का स्कोर करके 11वें स्थान पर रहे। चीन के लियू युकुन 594 स्कोर करके शीर्ष पर रहे जो ओलिंपिक क्वालीफिकेशन का रिकार्ड है। कुसाले जब गुरुवार को फाइनल में उतरेंगे तो उनकी नजरें भारत की झोली में तीसरा पदक डालने पर होंगी।

स्वप्निल कुसाले महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धौनी से प्रेरणा लेते हैं जो करियर की शुरुआत में उन्हीं की तरह रेलवे में टिकट कलेक्टर थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कंबलवाड़ी गांव के रहने वाले 29 वर्ष के कुसाले 2012 से अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में खेल रहे हैं लेकिन ओलिंपिक पदार्पण के लिए उन्हें 12 साल इंतजार करना पड़ा। धौनी की ही तरह 'कूल' रहने वाले कुसाले ने विश्व कप विजेता क्रिकेट कप्तान पर बनी फिल्म कई बार देखी। फाइनल में पहुंचने के बाद कुसाले ने कहा, मैं निशानेबाजी में किसी खास खिलाड़ी से मार्गदर्शन नहीं लेता, लेकिन अन्य खेलों में धौनी मेरे पसंदीदा हैं। मेरे खेल में भी शांतचित रहने की जरूरत है और वह भी मैदान पर हमेशा शांत रहते थे। वह भी कभी टीसी थे और मैं भी हूं। कुसाले 2015 से मध्य रेलवे में काम करते हैं। उनके पिता और भाई जिला स्कूल में शिक्षक हैं और मां गांव की सरपंच हैं। अपने प्रदर्शन पर स्वप्निल ने कहा, मेरा अभी तक अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मुझे निशानेबाजी पसंद है और मुझे खुशी है कि इतने लंबे समय से कर पा रहा हूं। मनु भाकर को देखकर आत्मविश्वास आया है। वह जीत सकती है तो हम भी जीत सकते हैं। कुसाले ने पूर्व निशानेबाज तेजस्विनी सावंत से प्रशिक्षण लिया है।

श्रेयसी और राजेश्वरी ने किया निराश: महिलाओं के ट्रैप क्वालीफिकेशन के दूसरे राउंड में भी भारत की श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी ने निराश किया। बुधवार को हुए राउंड में श्रेयसी और राजेश्वरी ने 125 में 113 का स्कोर बनाया। राजेश्वरी 22वें तो श्रेयसी 23वें स्थान पर हीं। छह शीर्ष निशानेबाजों ने फाइनल में जगह बनाई।

स्वप्निल कुसाले ● एपी

क्या है 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा

इस स्पर्धा में राइफल को पकड़ने के लिए भी अलग-अलग पोजीशन (मुद्रा) इस्तेमाल की जाती हैं। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में राइफल पकड़ने के लिए कुल मिलाकर तीन तरह की पोजीशन इस्तेमाल की जाती है। इसलिए इस इवेंट को 50 मीटर राइफल 'थ्री पोजीशन' कहा जाता है। इसमें निशानेबाज तीन अलग-अलग मुद्रा से निशाना साधते हैं। पहला घुटने के बल, दूसरा पेट के बल और तीसरा खड़े होकर। निशानेबाज को इन तीनों मुद्राओं में स्कोर करना होता है।

लक्ष्य ने विश्व नंबर चार क्रिस्टी को हराया, सिंधू की आसान जीत

पेरिस, प्रेट्र : भारतीय बैडमिंटन के उभरते सितारे लक्ष्य सेन और पीवी सिंधू ने पेरिस ओलंपिक में अपने-अपने मुकाबले जीतकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता सिंधू ने इस्टोनिया की क्रिस्टीन कूबा को सीधे गेमों में 21-5, 21-10 से हराया। रियो ओलिंपिक में रजत और टोक्यो में कांस्य पदक जीतने वाली सिंधू ने यह एकरफा मुकाबला महज 33 मिनट में अपने नाम किया। सिंधू ने जीत के बाद कहा, मैं बहुत खुश हूं। ग्रुप में शीर्ष पर रहना जरूरी था। इस जीत से मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगले मुकाबले आसान नहीं होंगे। लक्ष्य ने दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को सीधे गेमों में मात दी। विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता अलमोड़ा के 23 वर्ष के लक्ष्य ने मौजूदा आल इंग्लैंड और एशियाई खेल चैंपियन के विरुद्ध मुकाबला 50 मिनट में 21-18, 21-12 से जीता। लक्ष्य ने जीत के बाद कहा कि यह काफी कठिन मैच था और मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं। स्वर्ण पदक पर नजरें हैं।

पीवी सिंधू ● एपी

सेन के नो-लुक बैकहैंड शाट ने सभी को चौंकाया

जीत के बाद लक्ष्य सेन ● एएनआइ

विश्व नंबर चार इंडोनेशियाई खिलाड़ी के विरुद्ध लक्ष्य सेन की जीत विशेष है। हालांकि, उनकी जीत से भी अधिक अगर किसी चीज की चर्चा है तो वह है लक्ष्य के नो-लुक बैकहैंड शाट की। पहले सेट में लक्ष्य के इस शाट ने न केवल प्रशंसकों को चौंका दिया, बल्कि विश्व नंबर चार खिलाड़ी भी इससे हैरान हो गए। मैच में पहले सेट में लक्ष्य सेन ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 19-18 से बढ़त बना ली थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच इस अंक के लिए लंबी रैली चली और इसी बीच लक्ष्य को क्रिस्टी ने उनके बाएं हाथ से काफी दूर फंसा लिया। लक्ष्य फोरहैंड से इसे किसी भी हालत में वापस नहीं भेज पाते और इसी समय उनका यह नो लुक शाट आया, जिसने सबका दिल जीत लिया। लक्ष्य के उस शाट पर क्रिस्टी भी दंग रह गए। इस शाट में लक्ष्य सेन का आत्मविश्वास झलक रहा था। इस शाट से क्रिस्टी उबर नहीं सके और एक अंक के साथ पहला सेट भी गंवा बैठे।

भजन कौर के बाद दीपिका भी प्री क्वार्टर फाइनल में

पेरिस : भजन कौर के बाद तीरंदाज दीपिका कुमारी ने लगातार दो मुकाबले जीतकर महिला व्यक्तिगत वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल प्रवेश कर लिया। कुछ दिन पहले भारतीय महिला तीरंदाजों की टीम क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स से हार गई थी जिसमें दीपिका के प्रदर्शन की काफी आलोचना हुई थी। दीपिका ने व्यक्तिगत वर्ग में पहले इस्टोनिया की रीना परनाट को शूटआफ में 6-5 से हराया। इसके बाद नीदरलैंड्स की क्विंटी रोफेन को 6-2 से मात दी। अब उनका सामना प्री क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की मिशेले क्रोपेन से होगा।

6-5 से रीना परनाट को शूटआफ में हराया

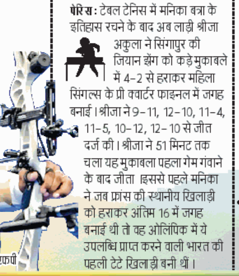
दीपिका कुमारी ● एएफपी

श्रीजा भी अंतिम 16 में पहुंचीं

पेरिस : टेबल टेनिस में मनिका बत्रा के इतिहास रचने के बाद अब लाड़ी श्रीजा अकुला ने सिंगापुर की जियान झेंग को कड़े मुकाबले में 4-2 से हराकर महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। श्रीजा ने 9-11, 12-10, 11-4, 11-5, 10-12, 12-10 से जीत दर्ज की। श्रीजा ने 51 मिनट तक चला यह मुकाबला पहला गेम गंवाने के बाद जीता। इससे पहले मनिका ने जब फ्रांस की स्थानीय खिलाड़ी को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई थी तो वह ओलिंपिक में ये उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारत की पहली टेटे खिलाड़ी बनी थीं।

घुड़सवार अनुष अग्रवाला ने बाहर होकर भी रचा इतिहास

वर्सेल्स (फ्रांस) : पेरिस ओलिंपिक में भारत के एकमात्र घुड़सवार अनुष अग्रवाला अपने घोड़े सर कारमेलो ओल्ड के साथ ड्रेसेज व्यक्तिगत क्वालीफायर राउंड में नौवें स्थान पर रहे। अनुष ओलिंपिक में ड्रेसेज में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय हैं। अनुष से पहले फवाद मिर्जा ने 2020 टोक्यो, इम्तियाज अनीस ने 2000 सिड्नी, इंद्रजीत लांबा ने 1996 अटलांटा ओलिंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। ये सभी इवेंटिंग में उतरे थे, जबकि अग्रवाला ड्रेसेज में क्वालीफाई हुए थे, जो बड़ी उपलब्धि है।

भारतीय रोवर बलराज पंवार छठे स्थान पर रहे

पेरिस : पेरिस ओलिंपिक में भारत के एकमात्र रोवर बलराज पंवार पुरुष सिंगल स्कल्स सेमीफाइनल सी/डी में 7:04.97 सेकेंड का समय लेकर छठे स्थान पर रहे। छठे स्थान पर रहने के कारण पंवार अंतिम डी में पहुंच गए, जो 19वें से 24वें स्थान तक सुनिश्चित करने के लिए है। यह शुक्रवार को होगा। पहली हीट में चौथे और रेपेचेज के बाद प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन क्वार्टर फाइनल में 7:05.10 सेकेंड के साथ पांचवें स्थान पर रहने के बाद वह पदक की दौड़ से बाहर हो गए।

जोकोविक पहले स्वर्ण से तीन कदम दूर

ओलिंपिक में विश्व

पेरिस, एपी : सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने बुधवार को जर्मनी के डोमिनिक कोइपफर को 7-5, 6-3 से हराकर चौथी बार ओलिंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विश्व के सबसे सफलतम पुरुष टेनिस खिलाड़ी सर्बियाई स्टार सिंगल्स में 24 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता हैं, लेकिन केवल एक उपलब्धि है जो उन्होंने अपने 16 वर्षों के करियर में प्राप्त नहीं की है वह है ओलिंपिक में स्वर्ण पदक।

37 वर्षीय खिलाड़ी न केवल पुरुषों में सर्वाधिक बार के ग्रैंडस्लैम विजेता हैं, बल्कि टेनिस इतिहास में सबसे लंबे समय तक विश्व नंबर एक रहने वाले खिलाड़ी भी हैं। यही कारण है कि इस वर्ष ओलिंपिक उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। शीर्ष वरीय खिलाड़ी ने ओलिंपिक में अब तक केवल 2008 में बीजिंग में कांस्य जीता था, इस बार उनका प्रयास यही होगा कि वह अपने पदक का रंग बदलें। रोलां गैरो के कोर्ट फिलिप चैटरियर पर तीन बार के ग्रैंडस्लैम विजेता ने यहां 2021 में स्टेफानोस सितसिपास को हराकर खिताब जीता था, क्वार्टर फाइनल में अब उन्हें उनसे ही भिड़ना है। सितसिपास ने अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बैज को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विश्व नंबर एक खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने भी चीन की वांग जी यू को 6-2, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्वियातेक का सामना अमेरिका की डेनियल कोलिंस से होगा।

नोवाक जोकोविक ● एपी

जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने स्वर्ण जीतकर रचा इतिहास

पेरिस, एपी : मानसिक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर टोक्यो ओलिंपिक में कई स्पर्धाओं के फाइनल से पीछे हटने वाली सिमोन बाइल्स की अगुआई में अमेरिकी महिला जिम्नास्टिक टीम ने पेरिस में स्वर्ण पदक जीतकर आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। बाइल्स, जोर्डन चिलेस और सुनिसा ली पहले भी ओलिंपिक में पदक जीत चुकी हैं, लेकिन इसी मंच ने उन्हें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घाव भी दिए जो शायद कभी भरेंगे तो नहीं लेकिन उनकी टीस जरूर इस स्वर्ण से कम हो जाएगी। करियर में इन तीनों ने कई चुनौतियों का सामना किया।

पेरिस में आज से अभियान शुरू करेगा एथलेटिक्स दल

पेरिस, प्रेट्र : भारत का 29 सदस्यीय दल पेरिस ओलिंपिक खेलों में गुरुवार से शुरू होने वाली एथलेटिक प्रतियोगिता में जब अपना अभियान शुरू करेगा तो सभी की निगाह नीरज चोपड़ा पर टिकी रहेंगी जो भाला फेंक में खिताब का बचाव करके भारतीय खेलों के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने का प्रयास करेंगे।

एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत पुरुष और महिला 20 किमी पैदल चाल से होगी, जिसमें अक्षदीप सिंह, विकास सिंह और परमजीत सिंह बिष्ट पुरुषों की जबकि प्रियंका गोस्वामी महिलाओं की 20 किमी रेसवाक स्पर्धा में भाग लेंगी।

दौड़ स्पर्धाओं के लिए पहली बार रेपचेज राउंड

इन ओलिंपिक खेलों में बाधा दौड़ स्पर्धाओं सहित 200 मीटर से 1500 मीटर तक की सभी व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धाओं में रेपेचेज राउंड शुरू किया जाएगा। अब प्रत्येक हीट में शीर्ष पर रहने वाले खिलाड़ियों को सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश मिलेगा जबकि अन्य खिलाड़ियों को रेपेचेज के जरिये यहां पहुंचने का मौका मिलेगा।

बेल्जियम के सामने होगी भारत की असली परीक्षा

पेरिस : क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर चुकी भारतीय हाकी टीम पेरिस गुरुवार को को मौजूदा चैंपियन बेल्जियम के रूप पहली कठिन चुनौती का सामना करेगी तो उसे प्रदर्शन में निरंतरता रखनी होगी। बेल्जियम पूल बी में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर है जबकि भारत दो जीत और एक ड्रा के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात उसके कप्तान हरमनप्रीत का लगातार गोल करना है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पहले दोनों मैचों में निर्णायक गोल दागे और फिर आयरलैंड के विरुद्ध पेनाल्टी स्ट्रोक पर पहला और पेनाल्टी कार्नर पर दूसरा गोल किया। राइट बैक जरमनप्रीत सिंह इस टूर्नामेंट की खोज साबित हुए हैं जिन्होंने अब तक काफी प्रभावी प्रदर्शन किया है।

निशानेबाजी में सफलता समर्थन का परिणाम

गगन नारंग की कलम से

सफलता से ज्यादा शोर किसी चीज का नहीं होता। पेरिस ओलिंपिक में भारतीय निशानेबाजी दल के शानदार प्रदर्शन ने यह एक बार फिर से साबित कर दिया है। खेल में यह भी एक बार फिर से साबित हो गया कि कि समय बदलने में देर नहीं लगती। जो भारतीय दल 2021 में टोक्यो ओलिंपिक से खाली हाथ लौटा था, उसने न सिर्फ पेरिस में पदक का खाता खोला, बल्कि मनु भाकर और सरबजोत ने इतिहास भी रच दिया। मैं निजी तौर पर बहुत खुश हूं क्योंकि 12 साल पहले जिस तारीख को लंदन ओलिंपिक में मैंने पदक जीता था, ठीक उसी तारीख को मनु और सरबजोत ने पदक जीता। हालांकि यहां पर अर्जुन बबूता का जिक्र न करना गलत होगा। वह बहुत ही कम अंतर से पदक जीतने से चूक गए। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया।

तो इस ओलिंपिक में आखिर क्या बदला गया है। दो चीजें ऐसी हैं, जो तुरंत मेरे दिमाग में आती हैं, पहला युवा निशानेबाजों का आत्मविश्वास। खेल गांव में मैंने मैच से पहले भारतीय निशानेबाजी दल से शेफ डि मिशन नहीं बल्कि एक एथलीट के रूप में मुलाकात की। युवा निशानेबाजों के गजब आत्मविश्वास ने मेरा दिल जीत लिया। सीनियर होने के नाते मैंने उन्हें एक ही सलाह दी है कि वर्तमान में जो रहा है, उसी पर फोकस करो। यह सच है कि आजकल एथलीट के सामने ट्रेनिंग के लिए फंड की बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती। सच तो यह है कि 21 सदस्यीय दल में से 10 वर्ष 2018-19 से ही खेलो इंडिया एथलीट हिस्सा है, इन्हें ग्रास रूट स्तर से ही टाप्स के जरिए एलीट सपोर्ट मिल रहा है। यही नहीं अन्य 11 खिलाड़ियों को भी टाप्स ने सपोर्ट किया है। यह एथलीट के लिए बड़ी राहत की बात होती है और इससे उन्होंने अपने खेल पर 100 प्रतिशत फोकस करने का आत्मविश्वास मिलता है। इसके साथ ही देश की ओर से भी जबरदस्त प्रेरणा मिल रही है, माननीय प्रधानमंत्री खिलाड़ियों तक यह संदेश दे रहे हैं कि वे जो भी कर रहे हैं, वह देश के लिए काफी मायने रखता है।

दूसरा बड़ा बदलाव जो मुझे दिख रहा है, वह है कि सभी हितधारक आपसी संयोजन से सुनिश्चित कर रहे हैं कि एथलीट जो भी मांगे, उसे मिलना चाहिए। चाहे ओलिंपिक से पहले या ओलिंपिक के दौरान निजी कोच, विदेश में ट्रेनिंग करना हो या आधुनिक उपकरण हों, पेरिस के लिए यह सब उपलब्ध कराया गया। और यह सिर्फ निशानेबाजी में ही नहीं, बल्कि सभी खेलों में यह प्रक्रिया लागू हुई है। दो पदक जीतना अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा देने वाला साबित होगा। ये ओलिंपिक अब तक का सर्वश्रेष्ठ साबित होगा।

(लेखक ओलिंपिक कांस्य पदक विजेता और पेरिस में भारतीय दल के प्रमुख हैं)

आइपीएल नीलामी और रिटेंशन को लेकर फ्रेंचाइजियों मे मतभेद

खेल डायरी

नई दिल्ली, जेएनएन : अगले वर्ष होने वाली आइपीएल मेगा नीलामी और उससे पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने को लेकर फ्रेंचाइजियों में मतभेद हैं। मुंबई में बीसीसीआइ मुख्यालय पर बुधवार को हुई बैठक में कुछ फ्रेंचाइजी ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करने के पक्ष में हैं तो कुछ फ्रेंचाइजी चाहती हैं कि खिलाड़ियों का रिटेंशन सीमित होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, आइपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों के बीच हुई चर्चा के दौरान कोलकाता नाइटराइडर्स के स्वामी शाह रुख खान समेत कुछ मालिकों ने मेगा नीलामी का विरोध किया है। एक समय ऐसा भी आया कि जब केकेआर के मालिक की पंजाब किंग्स के सहमालिक नेस वाडिया के साथ रिटेंशन की संख्या को लेकर तीखी बहस हुई।

दरअसल, शाहरुख चाहते थे कि टीमों को ज्यादा खिलाड़ी रिटेन करने का अधिकार मिले, जबकि नेस का मत तीन से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन नहीं करने का था। बैठक में दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद, राजस्थान और आरसीबी के मालिक मौजूद रहे।

सोनी स्पोर्ट्स ने ड्रग्स के विरुद्ध चलाया अभियान

नई दिल्ली, जेएनएन : सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने ड्रग्स के सेवन के विरुद्ध 'इस बार ड्रग्स की हार' अभियान चलाया। खेल प्रसारक ने भारत के युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में ड्रग्स के दुरुपयोग के लगभग 13 प्रतिशत पीड़ित 20 वर्ष से कम आयु के हैं। पिछले आठ वर्षों में देश में ड्रग्स की खपत में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अभियान का उद्देश्य संभावित पहली बार ड्रग्स का सेवन करने वालों को खेल का विकल्प चुनने और युवाओं को ड्रग्स का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करना है।

गंभीर ने दी टर्निंग पिचों पर सुधार की सलाह

पल्लेकेले, प्रेट्र : भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने श्रीलंका के विरुद्ध कम स्कोर वाले तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सुपर ओवर में जीत हासिल करके सीरीज में क्लीनस्वीप करने के लिए टीम की प्रशंसा की लेकिन साथ ही कहा कि टर्न लेती पिचों पर लगातार सुधार करने की जरूरत है।

गंभीर ने कहा, 'सीरीज में शानदार जीत के लिए सभी को बधाई। सूर्यकुमार को शानदार बल्लेबाजी और बेजोड़ कप्तानी के लिए बधाई। मैंने मैच शुरू होने से पहले कुछ कहा था और आप लोगों ने उस पर पूरी तरह से अमल किया। जब आप अंत तक हार नहीं मानते तो उसका परिणाम ऐसा मिलता है।' उन्होंने कहा, 'इस तरह के मैच में अनुकूल परिणाम तभी प्राप्त होता है जब आप प्रत्येक गेंद और प्रत्येक रन के लिए संघर्ष करना जारी रखते हैं। यह मैच उसका शानदार उदाहरण है।' गंभीर ने इसके साथ ही टर्न लेती पिचों पर अपने खेल में लगातार सुधार करने की अपील की जिनमें विशेष कर बल्लेबाजों को अलग तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है।

पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ का निधन

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद बुधवार को निधन हो गया। गायकवाड़ 71 वर्ष के थे और उन्होंने भारत की ओर से 40 टेस्ट व 15 वनडे मैच खेले थे और वह भारतीय टीम के कोच भी रहे थे। गायकवाड़ का लंदन के किंग्स कालेज अस्पताल में रक्त कैंसर का उपचार चल रहा था। वह लंदन में लंबा समय बिताने के बाद पिछले महीने स्वदेश लौट थे। पिछले महीने ही बीसीसीआइ ने उनके उपचार के लिए एक करोड़ रुपये की सहायता की थी, जबकि 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य भी उनकी आर्थिक रूप से मदद कर रहे थे।

गायकवाड़ ने अपने 22 वर्ष के करियर में 205 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। उनके कोच रहते भारतीय टीम ने 1998 में शारजाह में त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में आस्ट्रेलिया को हराया था। जब अनिल कुंबले ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में पाकिस्तान के विरुद्ध जब टेस्ट पारी में 10 विकेट चटकाए थे तब भी वह टीम के कोच थे। वह सौरव गांगुली की कप्तानी में 2000 आइसीसी चैंपियंस ट्राफी में उपविजेता रही भारतीय टीम के कोच भी थे।

भारतीय क्रिकेट की द ग्रेट वाल: गायकवाड़ तेज गेंदबाजों के विरुद्ध अपनी रक्षात्मक मानसिकता के लिए जाने जाते थे। जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों की विश्व में तूती बोलती थी, उस समय गायकवाड़ ने अपनी रक्षात्मक अप्रोच से अपनी पहचान बनाई। अपने मजबूत डिफेंसिव शैली के कारण उन्हें द ग्रेट बाल का उपनाम दिया गया। उन्होंने 27 दिसंबर 1974 को कोलकाता में वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और 31 दिसंबर 1984 को अंतिम टेस्ट खेला था। गायकवाड़ ने 40 टेस्ट मैचों में 30.07 की औसत से 1985 रन बनाए, जिसमें दो शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं।

उन्होंने 1982-83 में जालंधर में पाकिस्तान के विरुद्ध अपना सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 201 रन बनाया था। इस पारी के दौरान उन्होंने क्रीज पर 671 मिनट बिताए, उनकी धैर्यपूर्ण शैली और एकाग्रता का एक उदाहरण है।

71 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस, रक्त कैंसर से थे पीड़ित

1952-2024

अंशुमन गायकवाड़ जी को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वह एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर और बेहतरीन कोच थे। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।

– **नरेन्द्र मोदी**, प्रधानमंत्री

अंशुमन गायकवाड़ जी के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। पूरे क्रिकेट जगत के लिए बेहद दुखद खबर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

– **जय शाह**, बीसीसीआइ सचिव

एक प्रशंसक ऐसी भी...

ओलिंपिक डायरी

पेरिस, एपी : ओलिंपिक के प्रति दीवानी लास एंजिलिस की 66 वर्ष की विवियन राबिंसन अपनी बचत खर्च कर यहां पेरिस में पहुंची हैं। ओलिंपिक की 'सुपरफैन' विवियन 40 वर्ष में सात ओलिंपिक देख चुकी हैं, लेकिन पेरिस की यह यात्रा बहुत महंगी पड़ी। उन्होंने 38 प्रतिस्पर्धाओं के टिकट खरीदने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और इस यात्रा के लिए दो नौकरी कीं।

वह दिन में 'वेनिस बीच' पर काम करती थीं जिसमें वह चावल के दानों पर नाम लिखती थीं और रात में किराने का सामान पैक करती थीं। उन्होंने कहा कि पेरिस में ओलिंपिक देखने के अपने जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने जो पैसे खर्च किए हैं उन्हें भरने के लिए उन्हें दो और साल काम करना होगा। वह कहती हैं, 'पैसे बचाना मुश्किल था और यह एक बड़ा बजट था, लेकिन यहां आना हजार गुना शानदार है।'

सीन नदी में हुई ट्रायथलान प्रतियोगिताएं : सीन नदी के पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता के बाद अंततः पेरिस ओलिंपिक खेलों की महिला और पुरुष ट्रायथलान स्पर्धाएं संपन्न हुईं। महिलाओं में जहां मेजबान फ्रांस की कैसेंड्रे ब्यूग्रांड ने स्वर्ण पदक जीता, पुरुषों में ग्रेट ब्रिटेन के एलेक्स यी ने बाजी मारी। सीन नदी में ट्रायथलान की तैराकी स्पर्धा का आयोजन सोमवार को ही किया जाना था, लेकिन उसके पानी की गुणवत्ता को लेकर पिछले कुछ समय से चिंता व्यक्त की जा रही थी। इस वजह से यहां पुरुष और महिला ट्रायथलान के अभ्यास सत्र और मुख्य मुकाबले भी स्थगित करने पड़े थे।

ओलिंपिक देखने पेरिस पहुंचीं अमेरिकी प्रशंसक विवियन राबिंसन ● एपी

****

टेक सिक्योरिटी

वायस असिस्टेंट और टारगेटेड एडवरटाइजिंग के इस दौर में यह चिंता और उत्सुकता स्वाभाविक ही है कि कहीं स्मार्टफोन हमारी आपसी बातचीत को सुन तो नहीं रहा है। निजता और साइबर सुरक्षा की चिंताओं की बीच इस प्रश्न का जवाब तलाश रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र...

फोटो : प्रतीकात्मक

फोन सुन रहा है आपकी बातचीत!

इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने अंडमान और लक्षद्वीप में पर्यटन विकास का एजेंडा पेश किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार लक्षद्वीप भी घूमने का प्लान बनाया जाए, पति की बात सुनते ही पत्नी का जवाब आया, मेरी भी महीनों से ऐसी ही इच्छा है। फिर तो, यात्रा कैसे शुरू करनी है, कैसे और कहां ठहरना है, जैसी बातों का लंबा सिलसिला चल पड़ा। अगले दिन सुबह जब पति ने अपने फोन को स्क्राल करना शुरू किया तो उन्हें होटलों और ट्रैवल एंड टूर एजेंसियों के ढेर सारे विज्ञापन दिखने लगे। अचानक उनके दिमाग में एक सवाल कौंधा- क्या फोन हमारी बातचीत को सुन रहा था?

इसका सवाल का संक्षिप्त उत्तर है-नहीं, जबकि बड़ा उत्तर है- यह संभव तो है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं, जैसा हम सोच रहे हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं-आफिस के एक दोस्त ने अंश को कुछ दिनों पहले स्मार्टवाच के हेल्थ ट्रैकिंग फीचर के बारे में बताया था। अब उसे फेसबुक पर स्मार्टवाच के कई सारे विज्ञापन दिखने लगे हैं।

डिजिटल फुटप्रिंट है सबसे अहम कड़ी : कुछ वर्ष पहले प्रोजेक्ट 'शेयरलैब' द्वारा बताने का प्रयास किया गया कि फेसबुक डाटा को कैसे एकत्र और विश्लेषित करता है। अंश ने फेसबुक पर अकाउंट बनाते समय उम्र, जन्मतिथि, जेंडर, परिवार के सदस्यों, अपनी शिक्षा, वर्तमान नौकरी जैसी जानकारियां दर्ज की थीं। अंश जैसे अन्य लोगों की जानकारियां भी एल्गोरिदम के जरिए एसोसिएट कर ली जाती हैं। अंश ने एक स्मार्टवाच कंपनी की पोस्ट पर लाइक और कमेंट भी किया था। इससे अंश उस सूची में शामिल हो गए, जो भविष्य में स्मार्टवाच के संभावित खरीदारों में से हो सकते हैं। वे फोन में कब और कहां लाग-इन करते हैं, वेबसाइट पर कुकीज से इसे भी ट्रैक किया जाता है। अंश इंस्टाग्राम या अन्य साइट पर होते हैं, तो भी फेसबुक को डिजिटल फुटप्रिंट डाटा दे रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में एनालिटिक्स, मार्केटिंग और एडवरटाइजिंग के उद्देश्य से थर्ड पार्टी भी शामिल होती हैं। कंपनियां अंश जैसे यूजर्स को उनकी पसंद, जरूरत के आधार पर विज्ञापन दिखाती हैं। इसी तरह अन्य डिजिटल प्लेटफार्म भी आपकी निजी जानकारियों पर नजर बनाकर रखते हैं।

पर्दे के पीछे सक्रिय कंप्यूटर

एआइ में अनेक मशीन लर्निंग तकनीकें काम करती हैं, जो डाटा को फिल्टर व विश्लेषित करती हैं, जैसे- डाटा क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन और रिइन्फोर्समेंट लर्निंग (आरएल)। यूजर इंटरैक्शन के फीडबैक के आधार पर आरएल एजेंट स्वत: प्रशिक्षित होते हैं, जैसे बच्चा बार-बार दोहराने से सीख जाता है। जब आप इंटरनेट मीडिया पर किसी पोस्ट पर लाइक करते हैं तो आरएल एजेंट को आपकी रुचि और प्राथमिकता का संदेश प्राप्त हो जाता है।

विज्ञापन दिखने के ये भी हैं कारण

- विज्ञापन पर आपने क्लिक किया हो।
- अपनी उम्र, ईमेल, जेंडर, लोकेशन जैसी निजी जानकारियों को साझा किया हो।
- अन्य एडवरटाइजर द्वारा जानकारियां साझा की गई हों, जिसके आप पहले ग्राहक रहे हों।
- किसी पेज या ग्रुप को ज्वाइन या लाइक किया हो।

दोस्त या स्वजन के डाटा के आधार पर भी आपको एड का रिकमेंडेशन मिलता है। अगर आपके दोस्त ने कोई खरीदारी की है, तो उससे संबंधित विज्ञापन आपको भी दिख सकता है। यह जरूरी नहीं आप दोनों की उस संदर्भ में कोई बातचीत हुई ही हो।

निजता का ध्यान क्यों जरूरी

किसी एप को लाग इन करते समय डाटा को कलेक्ट, स्टोर और प्रयोग करने के तरीकों को लेकर नियम और शर्तें होती हैं, जिसे आपकी अनुमति की आवश्यकता होती है। कोई भी अनुमति देते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर किसी तरह का संदेह है तो केवल जरूरत होने पर ही डाटा एक्सेस की अनुमति दें। जैसे वाट्सएप को कैमरा और माइक्रोफोन की अनुमति स्वाभाविक तौर पर देनी होती है। लेकिन सभी एप के लिए यह अनिवार्य नहीं है।

आजमाएं कुछ जरूरी उपायों को

- डाटा का आनलाइन किसी तरह दुरुपयोग न हो, इसके लिए एप की परमिशन सेटिंग को समय-समय पर चेक करते रहें।
- किसी एप या वेबसाइट को परमिशन या कुकीज स्वीकार करने से पहले विचार जरूर करें।
- किसी वेबसाइट या सर्विस में अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से कनेक्ट या लाग-इन करते समय सावधान रहें। ज्यादातर मामलों में वाया ईमेल साइनअप का भी विकल्प होता है।
- अगर निजता को लेकर अधिक सतर्क हैं तो अपने डिवाइस पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) को इंस्टाल कर सकते हैं, यह आपके आइपी एड्रेस को मास्क और आनलाइन एक्टिविटी एन्क्रिप्ट करता है।

लगता है कि फोन सुन रहा है तो...

फोन की सेटिंग में जाएं और सभी एप्स के लिए माइक्रोफोन के एक्सेस को डिसेबल कर दें। साफ्टवेयर को अपडेट रखें और विश्वसनीय एंटीवायरस एप का प्रयोग करें। किसी एप को डाउनलोड करने से पहले उसकी पर्याप्त जानकारी जुटाएं और सतर्क रहें।

न्यू गैजेट

एचपी एलीट बुक अल्ट्रा और ओमनी बुक एक्स

आप फ्रीलांसर या क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं या डायनेमिक लाइफ स्टाइल के लिए एक ऐसे लैपटाप की तलाश में हैं, जिससे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, प्रजेंटेशन, रिमोट मीटिंग जैसे कार्य सहजता से कर सकें, तो एचपी द्वारा हाल में लांच एआइ पीसी 'ओमनी बुक एक्स' को एक विकल्प के तौर पर रख सकते हैं। एचपी द्वारा एंटरप्राइज, स्टार्टअप आदि पेशेवर जरूरतों को देखते हुए 'एलीटबुक अल्ट्रा' को भी पेश किया गया है। दोनों ही एचपी के पहले कोपायलट+पीसी और स्नैपड्रैगन एक्स एलटी प्रोसेसर पर आधारित हैं। इसका 45 ट्रिलियन आपरेशंस पर सेकंड (टाप्स) क्षमता का एनएलयू (न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट) लैपटाप के जेनरेटिव एआइ और लैंग्वेज माडल को प्रभावी बनाता है। बारीक, आकर्षक डिजाइन और हल्के वजन (1.3 किग्रा.) वाले इन लैपटाप में नए दौर के साइबर हमलों से निपटने और डाटा सुरक्षा को देखते हुए एंड प्वाइंट सिक्योरिटी की सुविधा दी गई है। एआइ की बात करें तो एचपी एआइ कैंपेनियन, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए पर्सनल एआइ असिस्टेंट, पर्सनलाइज और पावरफुल कंप्यूटिंग के लिए कोपायलट प्लस, वर्चुअल इंटरैक्शन और एप्स स्ट्रीमिंग के लिए पोली कैमरा प्रो दिया गया है। कीमत की बात करें तो एलीटबुक अल्ट्रा के लिए आपको 1,69,934 रुपये और ओमनीबुक एक्स के लिए 1,39,999 रुपये खर्च करने होंगे।

वर्ग पहेली - 2708

बाएं से दाएं

1. मिर्जा हादी रुसवा का एक उपन्यास है-'........अदा' (4,2)। 3. रक्षक का रक्षा कार्य में लगा समय (3)।
5. लेख आदि की प्रतिलिपि, कापी (3)। 7. भारी वस्तु के चलने से आस-पास होने वाला कंपन (3)।
8. मूल्य, कीमत (2)। 9. नश्वरता (4)। 12. मिलन, मिलाप (4)।
14. बरगद (2)। 15. पंक्ति (3)।
16. किसी का खर्च उठाना, भार ढोना, निर्वाह करना (3)। 18. रक्षा करनेवाला (3)। 19. अमिताभ बच्चन की एक फिल्म (3,3)।

1					2		3		4
5		6			7				
				8					
9			10			11			
						12	13		
				14					
		15					16		17
18				19					

© Bird Features & Writing Agency

ऊपर से नीचे

1. हवा में उड़ने की क्रिया (3)। 2. नीच व्यक्ति (4)। 3. आंख के ऊपर का पतला आवरण (3)। 4. हिंदू राजभक्तों को दी जाने वाली उपाधि (2,4)। 6. जर्जर, बहुत कमजोर (3)। 9. संग्रहालय, म्यूजियम (6)। 10. व्यंग्य-पूर्ण चुटीली बात, ताना (2)। 11. महत्त्वपूर्ण, स्पेशल (2)। 13. मनुष्य, आदमी (3)। 14. फलसिद्धि, शुभफलदायिनी (4)। 15. सोना, धतूरा (3)। 17. मुलायम (3)।

कल का हल

इ		प	क	वा	न		वि	र	ह
त्या			प				ज्ञा		
दि	ल	टू	ट	ना		पा	न		ब
		न		ग			क	म	रा
दि				द	त	क	था		ब
न		स	ना	त	न				री
क	स	म			की		क्ष		
र		झ	ट		ह	क	मा	र	ना
		दा				री			र
मे	दा	री		मु	सी	ब	त		द

जागरण सुडोकू-2708

		7		6		9		5
3	8				9			6
		9	3		7	4	1	
1			8			5		7
7		3			2		6	
	6			4				2
9			6			1		
	1	8		7			5	
5			2			7		9

कल का हल

2	5	1	7	9	8	6	3	4
3	8	9	5	6	4	7	2	1
7	6	4	3	2	1	5	8	9
4	7	5	1	3	9	2	6	8
1	9	2	6	8	5	3	4	7
8	3	6	2	4	7	1	9	5
9	1	3	8	7	2	4	5	6
5	2	8	4	1	6	9	7	3
6	4	7	9	5	3	8	1	2

आज का भविष्यफल- 01अगस्त,2024 गुरुवार

के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : श्रावण मास कृष्ण पक्ष द्वादशी। आज का राहुकाल : दोपहर 01 बजकर 30 मिनट से 03 बजे तक। आज का दिशाशूल : दक्षिण। पर्व एवं त्योहार : प्रदोष व्रत।

कल 02 अगस्त, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : पश्चिम
कल की भद्रा : मध्याह्न 03 बजकर 27 मिनट से प्रात: 04 बजकर 39 मिनट तक।
विक्रम संवत 2081 शके 1946 दक्षिणायण, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तत्पश्चात चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र हर्षण योग तत्पश्चात वज्र योग मिथुन में चंद्रमा।

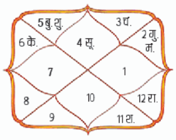

- **मेष :** शिक्षा प्रतियोगिता में आशातीत सफलता मिलेगी।
- **वृष :** क्रोध पर नियंत्रण रखें। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी।
- **मिथुन :** विरोधी सक्रिय रहेंगे। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं।
- **कर्क :** किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- **सिंह :** शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।
- **कन्या :** योजना फलीभूत होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
- **तुला :** अधिकारी का सहयोग मिलेगा। प्रयास फलीभूत होगा।
- **वृश्चिक :** दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
- **धनु :** आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा।
- **मकर :** निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।
- **कुंभ :** पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा।
- **मीन :** स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं।

आज है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस

इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम यानी इंटरनेट के जरिए दुनियाभर में हर क्षण करोड़ों लोग जुड़े रहते हैं। इस ग्लोबल सिस्टम ने कैसे सामान्य से लेकर खास तक हर किसी के जीवन को प्रभावित किया है और करने जा रहा है, आइए जानते हैं...

कैसे बदल रही है इंटरनेट की दुनिया

तकनीकी दुनिया की आज के दौर की बड़ी उपलब्धियों में से एक है-चैटजीपीटी। इसे बनाने वाली कंपनी ओपनएआइ ने बीते दिनों एआइ पावर्ड सर्च इंजन 'सर्चजीपीटी' की घोषणा की, तो 200 अरब डालर के सर्च इंजन मार्केट के दिग्गज गूगल के लिए इसे एक नई चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। दरअसल, ओपेनएआइ नए सर्च फीचर के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें वेब पर उपलब्ध प्रासंगिक और स्पष्ट जानकारियों के आधार पर एआइ माडल तीव्र गति से सर्च का जवाब देने में सक्षम होगा। साथ ही ओपनएआइ इस फीचर को अपने फ्लैगशिप एआइ माडल चैटजीपीटी में भी जोड़ने की तैयारी में है। इससे इंटरनेट पर उपयोगी जानकारियों को खोजना न केवल अधिक सहज हो जाएगा, बल्कि यूजर को क्यूरेटेड जवाब भी मिल सकेगा। हालांकि, इससे पहले सर्च इंजन इकोसिस्टम को 'प्रोपेलेक्सिटी' ने पहले ही प्रभावित करना शुरू कर दिया है। वहीं गूगल और माइक्रोसाफ्ट भी जेनरेटिव एआइ फीचर्स को जोड़ने के जतन में लगे हुए हैं।

इंटरनेट ने कैसा बदल दिया जीवन

आज से 10-15 वर्ष पूर्व अगर किसी से इंटरनेट के बारे में पूछा जाता, तो उसका जवाब होता- एक ऐसा वेब पेज, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें अलग-अलग जानकारियां उपलब्ध कराता है, लेकिन अब इंटरनेट की परिभाषा बदल गई है। आपका आनलाइन अनुभव किसी एक वेब पेज का मोहताज नहीं है। आज यूजर के पास इंटरनेट से जुड़ने के लिए एप्स, डिवाइसेज, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और वर्चुअल वर्ल्ड जैसी सुविधाएं हैं। आगुमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीक तो हमें वास्तविक दुनिया का भी अनुभव प्राप्त कराती है। कभी स्टेटिक वेब पेजेज, ब्लरी जेपीजी इमेजेज और धुंधले बैकग्राउंड वाली इंटरनेट की दुनिया, आज न केवल हर किसी के लिए उपयोगी हो गई है बल्कि यह यूजर फ्रेंडली और इमर्सिव भी हुई है। यहां तक कि इंटरनेट के बिना सामान्य जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है।

अगले 10 वर्षों में इंटरनेट की दुनिया

जिस तीव्रता से तकनीक बदल रही है, अगले एक दशक में इंटरनेट ऐसे आयाम खोल सकता है, जिसकी कल्पना तक नहीं की गई है। निश्चित ही यह अधिक इमर्सिव और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। जहां काम, आराम, खेल, खरीदारी और लोगों से मेल-मिलाप, सब कुछ बदल जाएगा। अगले एक दशक में 'आफलाइन रहने' का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। स्क्रीन न देखते हुए भी आप आनलाइन एक्टिविटी का हिस्सा होंगे, क्योंकि आपका डाटा निरंतर प्रासेस हो रहा होगा। वर्चुअल स्पेस में लाग-इन या साइन-इन का सिद्धांत चलन से बाहर हो जाएगा, मशीन स्वत: ही बायोमीट्रिक का प्रयोग कर आथेंटिकेट करनी लगेगी। वर्चुअल हेल्थकेयर, वर्चुअल इकोनामिक्स और डिजिटल ओनरशिप जीवन का हिस्सा होंगे।

ब्रह्मानंद मिश्र

राष्ट्रीय फलक

हिमाचल के स्कूलों में प्रतिदिन फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज

जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों में प्रतिदिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ ऐ मालिक तेरे बंदे हम... और इतनी शक्ति हमें देना दाता... प्रार्थना को भी अनिवार्य किया गया है। स्कूलों में अनिवार्य रूप से 15 मिनट तक व्यायाम भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार इस प्रकार की गतिविधियों से युवा पीढ़ी में एकता और देशभक्ति की भावना जागृत होगी। इससे विद्यार्थी भविष्य में राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों का शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक शिक्षा और योग को पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय बनाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के सहयोग से विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

सिंदूरी आभा बिखेर रही कांवड़ के रंग में रंगी धर्मनगरी हरिद्वार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

- कांवड़ मेले के दसवें दिन हरिद्वार से गंगाजल लेकर गंतव्यों को रवाना हुए 76 लाख कांवड़ यात्री

धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धा एवं आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। चारों दिशाएं सिंदूरी आभा बिखेर रही हैं। जितनी आकर्षक कांवड़ सजी हैं, उतना ही निराला अंदाज कांवड़ यात्रियों का भी दिख रहा है। भक्ति में लीन कांवड़ यात्री अपने पुनीत लक्ष्य की ओर लंबे-लंबे डग भर रहे हैं। आस्था के इस रंग में रंगने को हर कोई आतुर नजर आता है। शहर ओर से छोर तक पैक है। दो अगस्त को श्रावण शिवरात्रि है, इसलिए गुरुवार व शुक्रवार को कांवड़ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ेगी। बुधवार को कांवड़ मेले के दसवें दिन 76 लाख कांवड़ यात्री गंगाजल लेकर गंतव्यों को रवाना हुए।

शहर में पूरे दिन कांवड़ यात्रियों की टोलियां विचरण करती रहीं। धर्मनगरी के पौराणिक मठ-मंदिरों में भी कांवड़ यात्रियों के सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा था। बुधवार को डाक कांवड़ की वापसी होने के कारण दक्षेश्वर महादेव, मनसा देवी, चंडी देवी, नीलेश्वर महादेव, बिल्वकेश्वर महादेव आदि मंदिरों में कांवड़ यात्रियों की खासी भीड़ रही।

सुबह दक्ष मंदिर समेत अन्य शिवालयों में जलाभिषेक करने के बाद कांवड़ यात्रियों के गंगाजल लेकर वापसी का क्रम भी तेज हो गया। इसके चलते हाईवे पर डाक कांवड़ वाहनों का रेला उमड़ पड़ा। ऐसे में पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दसवें दिन बीते दिनों से कहीं अधिक कांवड़ यात्री धर्मनगरी पहुंचे। इन्हें मिलाकर अब तक धर्मनगरी पहुंचने और गंगाजल लेकर लौटने वाले कांवड़ यात्रियों का आंकड़ा तीन करोड़ 27 लाख 40 हजार पहुंच गया है।

शाम को आसमान में बादल घिर आने से कांवड़ यात्रियों का जोश दोगुना हो गया। डाक कांवड़ के साथ बाइक सवार कांवड़ यात्री और उनके साथ झूमते-नाचते-गाते चल रहे कांवड़ यात्रियों ने मेले में रंग जमा दिया।

देशभक्ति के रंग में रंगीं कांवड़ : कांवड़ मेले में देशभक्ति का रंग भी घुल रहा है। अकेले और टोली में कोई चार मंजिला कांवड़ तो कोई दस मंजिला कांवड़ को लेकर चल रहा है। पैदल कांवड़ यात्रियों के कंधों और कांवड़ वाहनों पर स्थापित भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमाएं अलग ही छटा बिखेर रही हैं। महिला कांवड़ यात्रियों की संख्या भी अच्छी-खासी है। कांवड़ पटरी पर तो दिन-रात का एहसास ही नहीं हो रहा। ऐसा ही नजारा हरकी पैड़ी व मुख्य कांवड़ मेला बाजार का भी है। शहर के अन्य हिस्सों में भी कांवड़ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही हैं। हालांकि, गर्मी व उमस के बावजूद पुलिस और प्रशासन ने बेहतर ढंग से व्यवस्थाएं संभाली हुई हैं।

शिव की ससुराल में शिवभक्तों का डेरा

हरकी पैड़ी से जल भरने के बाद कांवड़ यात्री भगवान आशुतोष की ससुराल कनखल का भी रुख कर रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव, दरिद्र भंजन, तिल भांडेश्वर आदि मंदिरों में जलाभिषेक को बुधवार को पूरे दिन कांवड़ यात्रियों का जमावड़ा लगा रहा।

बुधवार को कांवड़ मेला यात्रा के दसवें दिन हरकी पैड़ी पर उमड़ पड़ा कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा का सैलाब। साभार कमल खड़का

श्रद्धा का महासावन

मृत्यु व शोक के भय से मुक्त रहते हैं शिव के साधक

महादेव शिव के विविध स्वरूप हैं। हर स्वरूप शुभकारी है। जरूरत है उसके भाव को समझने की। शिव भक्तों का समर्पण चाहते हैं। जो शिव के प्रति समर्पित है उस साधक को मृत्यु, रोग और शोक का भय नहीं होता। शिव शब्द का अर्थ कल्याणकारी है। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश ब्रह्मा, विष्णु और महेश (महेश शिव का नाम है) नामक देवताओं का दायित्व है। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान किया है, इसीलिए उन्हें महादेव कहते हैं। शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर की होती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिह्न। शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परमपुरुष का प्रकृति के समंवित चिह्न। भगवान शिव का रूप-स्वरूप जितना विचित्र है, उतना ही आकर्षक भी है। इनकी जटाएं अंतरिक्ष व चंद्रमा मन का प्रतीक है। इनकी तीन आंखें हैं, इसीलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। ये आंखें सत्व, रज, तम (तीन गुणों), भूत, वर्तमान, भविष्य (तीन कालों), स्वर्ग, मृत्यु पाताल (तीनों लोकों) का प्रतीक हैं। शिव के प्रति त्याग, समर्पण व भक्ति का भाव ही उनके निकट जाने का सरल मार्ग है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर शिव का वास है। वही भवसागर से पार ले जाते हैं। इस भाव को समझकर शिव की स्तुति करनी चाहिए।

जगद्गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, वरिष्ठ सदस्य श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट

पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के भीतर सुरंग व छिपे खजाने की होगी खोज

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

- जांच समिति के अध्यक्ष ने कहा, एसओपी में इसके लिए जोड़े गए प्रविधान
- रत्न भंडार की चाबी गायब होने को लेकर दर्ज किया जाएगा आपराधिक मामला

पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के भीतर सुरंग व अन्य छिपा खजाना होने की बात सच है या नहीं, इसकी जांच होगी। जांच समिति ने इसके लिए एसओपी में सुधार किया है। एसओपी पर अभी कानून मंत्रालय की मुहर लगनी बाकी है। रत्न भंडार जांच समिति की ओर से एसओपी में जोड़े गए नए प्रविधानों का पुरी जगन्नाथ मंदिर संचालन कमेटी अध्ययन कर रही है। इसके बाद इसे सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। एसओपी जांच कमेटी के अनुसार, रत्न भंडार की मरम्मत प्रक्रिया शुरू होने से पहले अत्याधुनिक तरीके से दोनों आंतरिक एवं बाहरी भंडारों का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा।

रत्न भंडार निगरानी कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में रत्न भंडार की जांच, गहनों की मरम्मत, गिनती आदि प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई है। कमेटी के सदस्यों ने प्रस्ताव दिया कि रत्न भंडार मरम्मत करने से पहले अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर विस्तृत जांच की जाए, इस पर कमेटी ने अपनी मुहर लगा दी है। हमने रत्न भंडार की मरम्मत करने का निर्णय लिया था। लोग आशंका जता रहे हैं कि आंतरिक रत्न भंडार के अलावा भी कोई रत्न भंडार मंदिर के भीतर है। पुस्तकों में भी इस बात का उल्लेख है। ऐसे में इस तरह के संदेह को खत्म करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर जांच की जाएगी।

उधर, रत्न भंडार जांच कमेटी के सदस्य जगदीश महांती ने कहा है कि रत्न भंडार की चाबी गायब होने के प्रसंग को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। रत्न भंडार खोलने के समय ताला काटना पड़ा था। जांच कमेटी को जो चाबी मिली थी, उससे ताला नहीं खुला। इससे एक बात प्रमाणित हो रही है कि जो चाबी मिली थी वह असली नहीं थी। चाबी मिल जाने की बात जो कही जा रही थी, वह गलत थी। कानून के अनुसार यह दंडनीय अपराध है। किसी व्यक्ति ने चोरी का प्रयास किया था।

बैठक के बाद जानकारी देते रत्न भंडार जांच कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ (दाएं) व अन्य। जागरण

भाजपा शासित मप्र, राजस्थान ने रायल्टी मामले में केंद्र का समर्थन किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा शासित मध्य प्रदेश और राजस्थान ने खदानों एवं खनिजों पर रायल्टी एवं कर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसकी तारीख के बाद से लागू करने के लिए केंद्र की मांग का बुधवार को समर्थन किया। कहा कि वे नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएंगे और राशि वापस करने की मांग नहीं करेंगे। हालांकि, झामुमो के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने केंद्र की मांग का विरोध किया और 25 जुलाई के फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की मांग की।

केंद्र ने 1989 से खदानों और खनिजों पर लगाई गई रायल्टी की राज्यों द्वारा वापसी की मांग का विरोध करते हुए कहा कि इसका असर नागरिकों पर पड़ेगा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 70 हजार करोड़ देने पड़ेंगे। संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रखा कि क्या कर लगाने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखने वाले उसके 25 जुलाई के फैसले को पूर्वव्यापी या निर्णय आने की तारीख के बाद से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

****

लद्दाख में भारत की पहली जियो थर्मल बिजली परियोजना की ड्रिलिंग शुरू

राहुल शर्मा ● जागरण

- एक मेगावाट होगी उत्पादन क्षमता, प्रोजेक्ट सफल रहा तो और तेज होंगे प्रयास
- 14 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर पुगा घाटी में बनाई जा रही परियोजना

जम्मू : बर्फीला रेगिस्तान कहे जाने वाले लद्दाख की पुगा घाटी में देश की पहली जियो थर्मल (भूतापीय) बिजली परियोजना की ड्रिलिंग शुरू हो गई है। पायलट परियोजना के तहत शुरू की गई इस परियोजना की उत्पादन क्षमता फिलहाल एक मेगावाट के करीब होगी। प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद पुगा घाटी के एक बड़े हिस्से की भूतापीय क्षमता के दोहन के प्रयास तेज किए जाएंगे। प्रारंभिक अनुमान से पता चलता है कि पांच वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 200 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है।

लेह से करीब 190 किलोमीटर दूर स्थित पुगा घाटी में लगाया जा रहा यह प्रोजेक्ट तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद-लेह (एलएएचडीसी) और हिमालयन रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन फर्म (एचआरईसीएफ) की संयुक्त पहल है। यह भूतापीय शून्य-कार्बन नवीकरणीय बिजली परियोजना लेह में 14 हजार फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। सर्वेक्षण से पता चला है कि पुगा घाटी में 1000 मीटर की गहराई पर 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। जो एक मेगावाट बिजली यूनिट शुरू करने के लिए पर्याप्त है। सूत्रों के मुताबिक, परियोजना का उद्देश्य सर्दियों से पहले अंतरिक्ष हीटिंग, जलीय कृषि, कृषि और लैगून स्पा जैसी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद-लेह, ओएनजीसी और लेह स्थित निर्माण कंपनी एचआरईसीएफ के बीच 2021 के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ था। एचआरइसीएफ ज्यादातर नवीकरणीय ऊर्जा में काम करती है। वहीं, ओएनजीसी ने ड्रिलिंग का ठेका निजी कंपनी सेरोस ड्रिलिंग को दिया है। कंपनी ने आइसलैंड से सलाहकार और विशेषज्ञ भी नियुक्त किए हैं। प्रयास सफल रहा तो इसका लाभ न सिर्फ लद्दाख बल्कि देश के दूसरे राज्यों को भी होगा।

लद्दाख में हैं नौ पनबिजली परियोजनाएं : लद्दाख में वर्तमान में लेह और कारगिल जिले के 13.95 मेगावाट की करीब नौ परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं का रखरखाव जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन ही कर रहा है। कारगिल में 44 मेगावाट वाली चुतक और लेह में 45 मेगावाट क्षमता वाली निम्मो बाजगो पनबिजली परियोजनाएं हैं।

प्रीस्टली ने मरक्यूरिक आक्साइड को जला की आक्सीजन की खोज

1774 में आज ही ब्रिटिश रसायनज्ञ जोसेफ प्रीस्टली ने मरक्यूरिक आक्साइड को जलाकर डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर की खोज की थी। 1777 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोन लवायजिया ने इसे आक्सीजन नाम दिया। एंटोन ने ही बताया था कि आक्सीजन एक केमिकल एलीमेंट है।

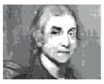

महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया असहयोग आंदोलन

1920 में आज ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेश निर्मित वस्तुओं व कपड़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया। पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।

हिंदी के प्रचार में आजीवन समर्पित रहे पुरुषोत्तम टंडन

स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1882 में आज ही इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। 1906 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद वकालत का करियर छोड़ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने लगे और कई बार जेल गए। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। संविधान सभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का पुरजोर समर्थन किया। 1962 में भारत रत्न से सम्मानित हुए।

इधर-उधर की

तीन छोटे विमानों को खींच बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड

हाथों के बल चलते हुए पावोन ने विमानों को खींचा। इंटरनेट मीडिया

रोम, एजेंसी: इटली के माटेओ पावोन ने हाथों पर चलते हुए तीन छोटे विमानों को खींचकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड नाम कर लिया। पावोन ने कहा कि रग्बी खेलते हुए उन्हें गंभीर चोट लगी जिसके बाद डाक्टरों ने कहा कि वह कभी खेल नहीं सकते। 2018 में उन्होंने असामान्य एथलेटिक गतिविधियों की ओर रुख किया। योग, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से उन्होंने खुद को रिकार्ड के लिए तैयार किया।

रोगों की वजह आनुवांशिक व दूषित पर्यावरण

आनुवांशिक योगदान को पीछे छोड़ते हुए पर्यावरणीय कारक रोग के खतरे में निभा सकते हैं अहम भूमिका

पर्यावरणीय प्रभावों को आनुवंशिक कारकों से अलग करने के महत्व पर दिया जोर

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, आइएएनएस : रोगों के पैदा होने में आनुवांशिक और दूषित पर्यावरण अहम भूमिका निभाते हैं। पर्यावरणीय कारक रोग के खतरे में पहले से कहीं अधिक भूमिका निभा सकते हैं। इस बारे में पेन स्टेट कालेज आफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि आनुवांशिक योगदान को पीछे छोड़ते हुए पर्यावरणीय कारक रोग के खतरे में में पहले से कहीं अधिक भूमिका निभा सकते हैं।

नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि जीवनशैली और दूषित पर्यावरणीय कारक जैसे वायु प्रदूषण रोग के खतरे में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कम के अधिक अवसर मिलते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान के सहायक प्रोफेसर बिबो जियांग ने कहा कि हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आनुवांशिकी और पर्यावरण रोग के विकास को कितना प्रभावित करते हैं। टीम ने रोग के खतरों का विश्लेषण करने के लिए आनुवांशिकी व भौगोलिक स्थान डाटा को मिलाकर एक नए स्थानिक मिश्रित रैखिक प्रभाव (एसएमआइएलई) माडल का उपयोग किया।

शोध के वरिष्ठ लेखक दाजियांग लियू ने पर्यावरणीय प्रभावों को आनुवांशिक कारकों से अलग करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम इन साझा दूषित पर्यावरणों को अलग कर सकें, तो जो कुछ बचा है वह बीमारी की आनुवांशिकता को अधिक सटीक रूप से दर्शा सकते हैं। आईबीएन मार्केट स्कैनर पर्यावरणीय डाटा का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने विभिन्न रोगों में आनुवांशिक योगदान का पुनर्मूल्यांकन किया। उदाहरण के लिए, टाइप 2 मधुमेह के आनुवांशिक खतरे को 37.7 प्रतिशत से 28.4 प्रतिशत तक पुनः मापा गया, जो पर्यावरणीय कारकों की अधिक भूमिका को दर्शाता है। इसी तरह मोटापे के जोखिम में आनुवांशिक योगदान 53.1 प्रतिशत से घटकर 46.3 प्रतिशत हो गया।

पराबैंगनी प्रकाश या कुछ रसायनों जैसे पर्यावरणीय खतरे से क्षतिग्रस्त अणु डीएनए में शामिल हो जाते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इससे कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय व फेफड़ों की बीमारी और अल्जाइमर रोग हो सकता है। अध्ययन ने स्वास्थ्य स्थितियों पर एएम2.5 और एनओटू से विशिष्ट प्रदूषकों के प्रभावों को भी अलग किया। एनओटू को उच्च कोलेस्ट्राल और डायबिटीज जैसी स्थितियों को सीधे प्रभावित करने वाला पाया गया, जबकि पीएम.5 ने फेफड़ों के कार्य और नींद संबंधी विकारों को प्रभावित किया।

यह शोध बताता है कि सटीक चिकित्सा से आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों के बीच संतुलन को समझने से रोग की रोकथाम की रणनीतियों को बेहतर बनाया जा सकता है।

लुप्तप्राय प्रजाति का सफेद गेंडा

फ्रांस के मोंटपेलियर स्थित लूनारेट चिड़ियाघर में बुधवार को मां नोला के बगल में खड़ा एक सफेद गेंडा का बछड़ा। सफेद गेंडा एक लुप्तप्राय प्रजाति बन गई है और यह बछड़ा 20 जुलाई 2024 को पैदा हुआ था। यह लूनारेट चिड़ियाघर में पैदा हुआ पहला सफेद गेंडा है। गैंडों की सींग की बढ़ती मांग के बाद दुनिया से इनकी प्रजाति धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। एएफपी

गठिया की दवाएं इलाज में कोरोना में सूजन से दिला सकती हैं राहत

नई दिल्ली, प्रेट्र: गठिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं लंबे समय तक कोरोना में फेफड़ों से संबंधित लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकती हैं, जो संक्रमण के दो साल बाद भी बने रह सकते हैं। पिछले अध्ययनों में लंबे समय तक कोरोना को बेहतर ढंग से समझने के लिए रक्त के नमूनों को देखा गया था।

इस अध्ययन को साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित किया गया। शोधकर्ताओं ने इन दवाओं का अध्ययन चूहों और मनुष्यों के फेफड़ों के ऊतकों को देखा। अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं सहित टीम ने पाया कि कोविड-19 से संक्रमित होने से फेफड़ों में इम्यून कोशिकाओं में बदलाव हो सकता है, जिससे शुरुआती संक्रमण के बीतने के बाद भी निशान पड़ सकते हैं और सूजन बढ़ सकती है। लंबे समय तक कोरोना से जुड़े होने से लगातार होने वाली सूजन लंबे समय तक चलने वाले श्वसन लक्षणों जैसे खांसी और सांस लेने में कठिनाई में योगदान करती पाई गई। टीम ने कहा कि बैरिसिटिनिब सहित गठिया की दवाएं सूजन रोधी प्रभाव इन श्वसन लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं। गठिया जोड़ों को प्रभावित करने वाली पुरानी सूजन वाली स्थिति है। प्रमुख लेखक जी सन ने कहा कि अध्ययन ने क्लिनिकल नमूनों और एक प्रासंगिक पशु माडल का तुलनात्मक विश्लेषण करके कोरोना के रहने के कारण के कारण सांस संबंधी जटिलता के मूल कारण की पहचान की।

▸ अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं सहित टीम ने किया अध्ययन

प्रतीकात्मक

जन्म से अंधे लोगों के मस्तिष्क में पाए गए 'फिंगरप्रिंट' जैसे अनोखे पैटर्न

नई दिल्ली, प्रेट्र: शोधकर्ताओं ने कहा कि जन्म से अंधे लोगों में प्राथमिक दृश्य कोर्टक्स जो दृश्य जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है, यह दृष्टि वाले लोगों से अलग अनोखे पैटर्न विकसित करता है। इस पैटर्न की तुलना "व्यक्तिगत फिंगरप्रिंट" से की। उन्होंने कहा कि जो लोग देख सकते हैं, उनके दृश्य कोर्टक्स में कनेक्टिविटी में इतने अलग-अलग बदलाव नहीं दिखे और आमतौर पर काफी सुसंगत थे। अमेरिका में जार्जटाउन यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस की सहायक प्रोफेसर और प्रमुख लेखक एला स्ट्रीम-अमित ने कहा कि जन्म से अंधे लोगों में कनेक्टिविटी पैटर्न लोगों में अलग-अलग होता है, जैसे कि एक व्यक्तिगत फिंगरप्रिंट और समय के साथ स्थिर होता है। साथ ही कनेक्टिविटी पैटर्न से व्यक्ति की पहचान की जा सकती है।

नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज (पीएनएएस) की कार्यवाही में प्रकाशित अध्ययन में जन्म से अंधे लोगों का एक छोटा सा नमूना शामिल था, जिन्होंने दो वर्ष में बार-बार कार्यात्मक एमआरआई स्कैन करवाया था। स्कैन का विश्लेषण करने पर शोधकर्ताओं ने पाया कि अद्वितीय कनेक्टिविटी पैटर्न में समय के साथ उल्लेखनीय स्थिरता दिखाई। जार्जटाउन विश्वविद्यालय में शोधकर्ता लेनिया अमरल ने कहा कि हमारे अध्ययन में पाया गया कि ये पैटर्न हाथ में मौजूद कार्य के आधार पर महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदले, चाहे प्रतिभागी ध्वनियों का पता लगा रहे हों, आकृतियों की पहचान कर रहे हों या बस आराम कर रहे हों। इसके बजाय कनेक्टिविटी पैटर्न प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय थे और दो साल की अध्ययन अवधि में स्थिर रहे।

लेखकों ने कहा कि सुझाव दिया कि जीवन के अनुभव अलग-अलग तरीकों से मस्तिष्क के विकास को आकार देते हैं, खासकर अगर वे बिना देखे बड़े हुए हों। स्ट्रीम- अमित ने कहा कि मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी मस्तिष्क को विकसित होने के लिए स्वतंत्र करती है। संभवतः अंधे पैदा हुए लोगों के बीच दृश्य कोर्टेक्स के लिए अलग-अलग संभावित उपयोगों के लिए भी। मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी, या न्यूरोप्लास्टिसिटी पर्यावरण में बदलावों के जवाब में खुद को पुनर्गठित करने की क्षमता को संदर्भित करती है।

▸ नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज (पीएनएएस) की कार्यवाही में प्रकाशित किया गया अध्ययन

प्रतीकात्मक

शरीर में प्रोटीन की अधिक मात्रा से स्वस्थ किडनी को खतरा नहीं

अनुसंधान

शोधकर्ताओं ने पाया कि शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से स्वस्थ किडनी को खतरा नहीं है और न ही गैस्ट्रो का जोखिम है। इसके साथ ही कहा कि कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा से जरूर नुकसान हो सकता है। शोधकर्ताओं का निष्कर्ष मेटा-एनालिसिस फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन में हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

भारत में आमतौर पर लोगों में प्रोटीन की मात्रा कम है। शोध का नेतृत्व करने वाले नानचांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पौधों और पशुओं (विशेष रूप से मछली और समुद्री जीवों) से प्राप्त प्रोटीन की उच्च मात्रा का कम क्रोनिक किडनी डिजीज (सीकेडी) से संबंध पाया। वहीं, कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा एसिड रिफ्लक्स का कारण बन सकती है, जिसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ा व कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटाकर कम किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा से ब्लड शुगर अनियंत्रित होने का खतरा होता है जिससे डायबिटीज और आंशिक रूप से पुरानी बीमारी बढ़ सकती है।

मेटाबोलिक हेल्थ कोच शशिकांत आयंगर कहते हैं कि प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा लेने से किडनी को नुकसान नहीं होता। हैदराबाद के इंद्रप्रस्थ अपोलो हास्पिटल के डा. सुधीर कुमार ने वजन के हिसाब से कम, मध्यम और अधिक शारीरिक गतिविधि के अनुसार क्रमशः एक ग्राम, 1.3 ग्राम और 1.6 ग्राम प्रति किग्रा प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा बताया। प्रोटीन की अधिक मात्रा से किडनी रोग से ग्रसित लोगों पर कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, खासकर पशुओं से प्राप्त प्रोटीन से। लेकिन स्वस्थ किडनी वालों को खतरा नहीं है। (आइएएनएस)

स्क्रीन शाट

ड्राइवर ने नोरा से कहा हीरोइन बनने को सीखनी होगी हिंदी

बेहतर मौकों की तलाश में हैं नोरा। (@norafatehi)

ज्ञान जहां से मिले, ले लेना चाहिए। ऐसा ही कुछ किया अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही ने भी। मजे की बात यह है कि हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री बनने का सपना देखने वाली नोरा को हिंदी सीखने का ज्ञान मिला कार ड्राइवर से। इस बारे में बात करते हुए एक साक्षात्कार में नोरा कहती हैं कि जब काम की तलाश में मैं कनाडा से मुंबई आई, तो मेरा असली संघर्ष शुरू हुआ।

मैं आडिशन देने जाया करती थी। एक बार जिस कार में मैं बैठी थी, उसका ड्राइवर मुझसे पूछने लगा कि आपको क्या करना है। मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग करना है, स्टार बनना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर आपको पहले हिंदी सीखनी होगी। फिर मुझे लगा कि अरे इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। यह तो मेरे प्लान का हिस्सा ही नहीं था।

जब मैं कनाडा से अपना सामान पैक करके निकल रही थी, तब मैंने सोचा नहीं था कि हिंदी सीखनी है। मैंने हिंदी का टीचर ढूंढा। वह रोज छह से आठ घंटे हिंदी सिखाते थे। हिंदी के शब्द सीखने के लिए वह मुझे होमवर्क देते थे, मैं घर पर बैठकर वह होमवर्क करती थी। फिल्में और शोज देखने के लिए कहते थे। जो समझ में नहीं आता था, उसको लिखकर रखती थी फिर पूछती थी।

आगे रिलेशनशिप के लिए रश्मि देसाई को है कुछ ऐसे लड़के की तलाश

प्यार में एक बार दिल टूटने के बाद रिश्तों पर भरोसा करना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आगे जीवनसाथी व रिलेशनशिप को लेकर पैमाने ज्यादा प्रायोगिक और सख्त होते जाते हैं। अभिनेत्री रश्मि देसाई ने 2011 में अभिनेता नंदीश संधू से शादी की थी। दोनों के बीच 2016 में तलाक हो गया। उसके बाद बिग बास 13 में उनका रिलेशनशिप अभिनेता अरहान खान से साथ शुरू हुआ, लेकिन वह भी जल्द खत्म हो गया। अब हाल ही में रश्मि ने एक इंटरव्यू में दोस्त और अभिनेता पारस छाबड़ा से रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बातें की। उन्होंने बताया, 'पिछला रिलेशनशिप हम दोनों (रश्मि और अरहान) के लिए सही नहीं रहा, तो हमने आपसी सहमति के साथ खत्म करने का निर्णय लिया। एक दूसरे से शिकायतें तो थी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं थी। उसके बाद भी मैंने रिलेशनशिप में आने की कोशिश की, लेकिन इस विषय में मेरा संघर्ष चलता ही रहा। मुझे लगता है कि यह चीज मेरे लिए नहीं हैं या जो मेरे लिए बिल्कुल सही है, वो अभी तक मिला नहीं है।' रश्मि को कैसा साथी चाहिए? इसको लेकर उन्होंने कहा कि अपने मैंने वो बचपना जिया नहीं है, जो मैं अब जी रही हूं, वो समझने वाला इंसान मुझे चाहिए। मुझे ऐसा समझने वाला इंसान चाहिए, जैसे एक पिता अपनी बेटी को समझता है। मुझे मेरी स्वतंत्रताओं को छीनने वाला इंसान नहीं चाहिए।

टीवी के साथ अब डिजिटल प्लेटफार्म पर भी टिकी हैं रश्मि की निगाहें।

अमित को होता है कुछ प्रोजेक्ट को इन्कार करने का पछतावा

सिनेमा जगत में अपनी जगह बनाने के बाद हर कलाकार के लिए अपनी मनपसंद काम करना और पसंद न आने पर इन्कार करने की स्वतंत्रता मिलना बड़ी उपलब्धि होती है। इनसाइड एज और महारानी वेब सीरीज तथा फिल्म कला के अभिनेता अमित सियाल की मानें, तो उन्होंने पेशेवर सफर के शुरूआती दौर से स्वयं को यह स्वतंत्रता दे रखी है। हालांकि, इस कड़ी में उन्हें कुछ प्रोजेक्ट को इन्कार करने का पछतावा भी होता है। इस बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में अमित कहते हैं, 'मैंने जिंदगी में न ज्यादा और हां कम बोला है, इसमें मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई। हालांकि कई बार इस जिद के कारण पछतावा हुआ है कि सिर्फ अच्छा ही काम करना है। मन में यह आता है कि अरे वो काम क्यों छोड़ दिया, उसे तो करना चाहिए था। पता नहीं कि तेवर में आकर छोड़ दिया। ये सब तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, ये सब तो होता ही रहेगा। किसी के भी सारे निर्णय सही नहीं हो सकते हैं।' आगामी दिनों में अमित फिल्म रेड 2 में नजर आएंगे। इसके अलावा वह धर्मा प्रोडक्शन के अंतर्गत बन रही एक फिल्म का भी हिस्सा हैं।

फिल्म रेड 2 में अजय के साथ नजर आएंगे अमित। (amit.sial)

गलतियों को पहचानना जरूरी है : अर्जुन रामपाल

फिल्म निकिता राय एंड द बुक आफ डार्कनेस में होंगे अर्जुन। इंस्टाग्राम (@rampal72)

गलतियां करने से ज्यादा अहम है कि उन गलतियों को पहचान कर उसे सुधारा जाए। अभिनेता अर्जुन रामपाल इसी तरीके में यकीन रखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कभी कोई गलतियां की है, जिसका पछतावा रहा? इस पर दैनिक जागरण से बातचीत में अर्जुन कहते हैं कि हां, गलतियां करेंगे, तभी तो उससे सीखेंगे। सफलता यह भी है कि आप गलतियों को पहचान गए कि क्या नहीं करना है। एक पिता, पुत्र भाई, पति, अभिनेता होने के नाते मुझसे गलतियां होती हैं। हर गलती का परिणाम आता है, जो अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे सुधारे। गलतियों को पहचानना जरूरी हैं। पिछले दिनों फिल्म क्रैक : जीतेगा... तो जीएगा में नजर आए अर्जुन किस तरह के रोल की तलाश में हैं? वह कहते हैं कि मैं देख रहा है हूं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूं या नहीं। क्या करने और सीखने को मिलेगा। अगर एक्शन या कामेडी फिल्में कर रहा हूं, तो वह एक्शन या कामेडी बिना दिमाग वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसी फिल्में जो मुझे कुछ नया करने का मौका दे, एक नया कौशल सीखने दे, जिसके बाद मैं एक नया व्यक्ति बनकर निकलूं। निर्देशन की भी चाह है। मुझे कैमरा के पीछे रहना और उससे जुड़ी प्रक्रिया पसंद है। एक लेखक के साथ बैठकर कहानी बनाना, एक दुनिया को क्रिएट करना, सब पसंद है। कहानी मिलनी चाहिए, उसे आप ऐसे देखें, जैसे कोई और देख ही नहीं सकता है।

...इसलिए शांतनु को नहीं है अजय से तुलना का डर

फिल्म इंडस्ट्री में बड़े मौके पाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में आलिया भट्ट के साथ काम कर चुके अभिनेता शांतनु माहेश्वरी भी उस प्रतीक्षा में थे। तभी उन्हें मिली अजय देवगन और तब्बू अभिनीत फिल्म औरों में कहां दम था। दो अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने होने जा रही इस फिल्म में शांतनु, अजय देवगन का युवा वर्जन निभा रहे हैं। बड़े कलाकारों और प्रोडक्शन हाउस में काम करने को लेकर शांतनु दैनिक जागरण से बातचीत में कहते हैं, 'अच्छा लगता है कि बड़े प्रोडक्शन हाउस मुझ पर यकीन दिखा रहे हैं।'

अजय से है कुछ कनेक्शन: फिल्म में अजय के युवा वर्जन को निभाने को लेकर शांतनु कहते हैं, 'मुझे उनके साथ किसी प्रकार का कनेक्शन सा लगता है। खतरों के खिलाड़ी में उन्होंने ही मुझे अवार्ड दिया था। वह गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में भी थे। निर्देशक नीरज पांडे सर ने समझाया था कि तुम्हें अपनी ऊर्जा इस रोल में लानी होगी, ताकि अजय की ऊर्जा के साथ उसे मिला सकें। कहानी में 23 साल का अंतराल है। इतने वर्षों में इंसान में बहुत कुछ बदलता है, इसलिए डर नहीं था कि अजय सर से मेरी तुलना की जाएगी।'

आखिर मिल ही गया दम दिखाने का मौका: शांतनु को कब दम दिखाने का मौका मिला है? इस पर वह कहते हैं, 'जब मैं इंडस्ट्री में शुरुआत कर रहा था, तो कई लोगों ने मुझ पर संदेह जताया था कि इसे फिल्में मिलेगी या नहीं लेकिन मैंने कर दिखाया।'

अजय के साथ दूसरी फिल्म की है शांतनु ने ● मिडडे आर्काइव

प्यार के मामले में पुराने ख्यालात

औरों में कहां दम था रोमांटिक फिल्म है। ऐसे में जब शांतनु से पूछा गया कि आज की पीढ़ी प्यार को लेकर कितनी अलग सोच रखती है? प्यार में स्थायित्व कितना जरूरी है? इस पर वह कहते हैं, 'रोमांस को लेकर मैं ओल्ड स्कूल हूं यानी पुराने ख्यालात वाला हूं। मुझे डेटिंग एप्स समझ में नहीं आते हैं।'

अजय से सीखी ये बात

अजय देवगन

अजय से मिली सीख को लेकर शांतनु कहते है, 'अजय सर की सबसे प्रेरणात्मक बात यह है कि वह आज भी प्रासंगिक हैं। एक तरफ वह द लीजेंड आफ भगत सिंह जैसी फिल्म कर सकते हैं, तो वहीं शैतान और सिंघम जैसी फिल्में भी कर लेते हैं। उनको देखकर आप सीख सकते हैं कि अपने क्राफ्ट को कैसे पकड़कर रखा जाता है, ताकि लंबे समय तक आप प्रासंगिक बने रहें।'

टीवी से होने पर गर्व

शांतनु भी उन कलाकारों में से हैं, जो टीवी से फिल्मों में आए हैं। क्या अब फिल्में करने के बाद वह टीवी की ओर नहीं लौटेंगे? इस पर वह कहते हैं, 'मैं गर्व से कहता हूं कि मैं टीवी से आया हूं। टीवी ने मुझे काफी कुछ सिखाया। फिर रियलिटी शो में मौका मिला। वेब सीरीज में ऐसे रोल मिले, जो युवाओं को आकर्षित करते थे। फिर फिल्में मिली। मेरे लिए चीजें होती चली गईं। कुछ सोच समझकर नहीं किया। बस मैं यही चाहता हूं कि अब मैं जो काम कर रहा हूं, वो सबको समझ में आए। कलाकारों के अपने दर्शक हैं, जिनके अनुसार वह कहानियां चुनते हैं।'

केंद्रीय भूमिका को लेकर दबाव नहीं ले रहा : चंदन

हिंदी के साथ अब दक्षिण भारतीय सिनेमा की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं चंदन ● मिडडे

साहित्यकारों की कहानियों से प्रभावित होकर कई फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को सिनेमा के रूप में पर्दे पर उतारा है। लेखक उदय प्रकाश की लिखी किताब तिरिछ पर फिल्म निर्देशक संजीव के झा इसी नाम की फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म में पंचायत वेब सीरीज फेम अभिनेता चंदन राय मुख्य भूमिका में होंगे। इस फिल्म में पहली बार केंद्रीय भूमिका निभाने जा रहे चंदन दैनिक जागरण से बातचीत में बताते हैं, 'फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। हम जल्द ही इसकी शुरुआत करने वाले हैं। हाल ही में फिल्म के निर्देशक संजीव जी से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने फिल्म को किसी तकनीकी समस्याओं में फंसे होने की बात कही थी। इस समस्या के सुलझते ही हम शूटिंग शुरू कर देंगे। हमारी योजना इस फिल्म को रायपुर और उसके आसपास के वास्तविक स्थानों, जंगलों में शूट करने की है। कहानी के लेखक उसी तरफ के हैं। इसलिए फिल्म की शूटिंग भी उधर ही करेंगे। इस फिल्म में पहली बार केंद्रीय भूमिका निभाने की बड़ी जिम्मेदारी तो है, लेकिन मैं उसका कोई दबाव नहीं ले रहा हूं। फिलहाल मैं तेलुगु फिल्म क्रिकेट डेज की तैयारी में जुटा हूं।'

हाई एक्शन ड्रामा फिल्म में दिखेंगे जूनियर एनटीआर

बाहुबली, केजीएफ और ब्रह्मास्त्र पार्ट : 1 जैसी फिल्मों ने देश में फिल्मकारों को बड़ी कहानी को दो अलग-अलग हिस्सों में दो फिल्मों के तौर पर प्रदर्शित करने की नई दिशा दिखाई। फिल्म आरआरआर से देशव्यापी लोकप्रियता बटोरने वाले अभिनेता जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म देवरा पार्ट 1 भी दो हिस्सों में बन रही है। यह फिल्म 27 सितंबर को प्रदर्शित होगी। इससे पहले खबरें हैं कि जूनियर एनटीआर ऐसे ही एक और दो हिस्सों में बनने वाली फिल्म को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, नवोदित तेलुगु निर्देशक शौर्युव और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म को लेकर बातचीत चल रही है। शौर्युव द्वारा सुनाई गई इस फिल्म की आधारभूत कहानी जूनियर एनटीआर को पसंद आई है। उन्होंने शौर्युव से इस फिल्म की पटकथा तैयार करने के लिए कहा है। यह एक हाई एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे दो हिस्सों में बनाने की योजना है। जूनियर एनटीआर के अगले साल भी देवरा पार्ट 2, वार 2 और ड्रैगन फिल्मों की शूटिंग और तैयारियों में बीतेगा। साल 2026 की पहली तिमाही से शौर्युव की इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं।

वार 2 में खलनायक भूमिका में नजर आएंगे जूनियर एनटीआर ● @jrntr

****